हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 2. 00बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

30/03/2015/1400/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 1825

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन ट्यूबवैल्स का डिस्चार्ज कम हो गया है क्या सरकार उनकी जगह नये ट्यूबवैल लगाने का विचार रखती है? दूसरे, जो ट्यूबवैल ड्यूल काम कर रहे हैं यानी सिंचाई का काम भी कर रहे हैं और पीने-के-पानी का भी काम कर रहे हैं क्या उनकी जगह पर अलग से ट्यूबवैल लगाने का सरकार विचार रखती है?

Irrigation & Public Health Minister: Speaker, Sir, during the last three years 25 water supply schemes have been sanctioned in Una District. As I have given in reply 13 schemes are in Una Division No. 1 and 12 schemes are in Una Division No. 2. The details of each scheme are with me and if required the same can be made available to the Hon'ble Member. But in any case I would like to give you some detail: Haroli Constituency - 5, Una COnstituency - 8, Kutlehar Constituency - 7, Chintpurni Constituency - 1 and Gagret Constituency - 4. All the tube-wells are given requisite discharge continuously. I think so. That is not a problem. But I would like to give some more details. Out of 25 schemes, nine have been completed, one scheme is repeated. Balance 15 schemes are in progress. Total sanction cost of these 25 schemes is 25.77 crores and a sum of Rs. 8.17 crores have been spent on these schemes. Balance schemes will be completed as per availability of funds. This I am sure you will not surprised to see that.

Concluded

30/03/2015/1400/MS/AG/2

Speaker: Next Question Shri Govind Singh Thakur authorised to **Shri Jai Ram Thakur.**

प्रश्न संख्याः 1826

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मंत्री जी के माध्यम से हमें उपलब्ध हुई है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

30.03.2015/1405/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1826:------जारी----------

श्री जय राम ठाकुरः------जारी------
उसके अन्तर्गत इस योजना में 8,81,133 लाभार्थी परिवार हैं, जिनमें से 4,79,606 परिवार स्मार्ट कार्ड धारक हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से इस बात की जानकारी चाहता हूं कि लाभार्थी परिवारों की संख्या 8,81,133 और स्मार्ट कार्ड धारक की संख्या लगभग आधी है, यानि 4,79,606 है। इसको स्पष्ट करें कि यह अन्तर इतना ज्यादा क्यों है?

दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी प्रक्रिया क्या है? ये कौन सी एजैंसी है, जिसके माध्यम से इन स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में डिटेल इन्फोरमेशन चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में आई.जी.एम.सी. या मण्डी जोनल हॉस्पिटल या किसी अन्य हॉस्पिटल में पेशैंट इलाज करने के लिए आते हैं और जब उनका नाम स्मार्ट कार्ड में नहीं होता है तब ऐसी परिस्थिति में उनको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परिवार के सदस्य होने के बावजूद भी उनका उसमें नाम नहीं होता है। कई बार इस तरह के एक्सिडैंट के मामले आते हैं। कई बहुत गम्भीर बीमारियों के मामले आते हैं जिनका इलाज जल्दी से होना चाहिए उस तरह के मामले आते हैं। कई गरीब होते हैं और उनकी मदद करने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं हो पाती है ,ऐसे में स्मार्ट कार्ड धारक को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है लेकिन उस लाभ से वे वंचित हो जाते हैं। इनको कवर करने के लिए आप किस प्रकार से कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि इस योजना के अन्तर्गत 8,81,133 लाभार्थी परिवार हैं। उसमें वे परिवार भी शामिल

हैं जिनके कार्ड पहले बन चुके हैं और डुप्लिकेट हुए हैं। क्योंकि पहले यह स्मार्ट कार्ड आई.आर.डी.पी. परिवारों तक ही सीमित होता था। अब इसमें रेहड़ी,

30.03.2015/1405/जेके/एजी/2

फड़ी वाले ,ड्राइवर्ज, टैक्सी ड्राइवर्ज, रिक्षा चालक और थ्री व्हीलर्ज और इनके अलावा दूसरी केटेगरीज़ भी इसमें शामिल की गई है लेकिन इनकी डुप्लिकेशन हुई है। मैंने विभाग को कहा कि इसकी पूरी जानकारी लो कि अब कितने हैं? उसमें से जैसे कि आपने कहा कि 4,79, 606 स्मार्ट कार्ड धारक हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 74 हजार ड्राईवर्ज हैं। They refused to make Smart Card. क्योंकि उनको 50 प्रतिशत देना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट कार्ड नहीं लेना चाहते हैं। इसके साथ-साथ हम पंचायतों के लिए एक किट जारी कर रहे हैं और कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है वह विभिन्न विभागों से कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्राप्त होती है। इस डाटा को भारत सरकार द्वारा You are Generate करने के बाद वेब साइट पर डाला जाता है तथा एक वर्ष के लिए उसको लॉक कर दिया जाता है। अभी हमारे यहां पर और भी स्मार्ट कार्डज़ बने हैं उसकी सूचना हम भारत सरकार को भी देते हैं उसको वे अपनी वैब साईट पर डालते हैं और एक साल तक वह चार्ज रहता है। इस वर्ष जो 31 मार्च तक का डाटा होगा वह हम भारत सरकार को देंगे और वे अपनी वेब साईट में डाल देंगे। उसको फिर लॉक कर दिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी लोगों के स्मार्ट कार्ड बनाएं। इस तरह से हमने इस पीरियड के अन्दर लगभग 73, 199 स्मार्ट कार्ड होल्डर्ज को लाभान्वित किया है। जो ऑर्डिनरी है उनको हम एक साल का 30 हजार रूपया देते हैं। जो क्रिटिकल केयर के लोग हैं, जैसे कार्डिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन आँकोलोजी, ट्रामा,ट्रांसप्लांट सर्जरी, स्पाईनल सर्जरी, गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी और केंसर आदि के तीन हॉस्पिटल्ज में इलाज होते हैं , जिनमें आई.जी.एम.सी., डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और तीसरा पी.जी.आई. को उसमें शामिल किया गया है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

30.03.2015/1410/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1826 क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः
उनको भी 1,75,000/- रुपया हिमाचल सरकार अपनी तरफ से देती है और उनका इलाज करवाया जाता है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, एक बात पूछी थी कि जो कार्ड है उसमें परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है तो उस केस में क्या होगा?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात होगी और हमारे ध्यान में लायेंगे तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाती है। 30हजार तक आई0आर0डी0पी0 परिवार जो कार्ड होल्डर है उनका इलाज मुफ्त किया जाता है कोई इन्कार नहीं कर सकता।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का ठीक प्रकार से उत्तर नहीं आया। मैं एक स्पैसिफिक केस में पूछ रहा हूं। मैं प्रक्रिया का ज़िक्र कर रहा हूं कि किस प्रकार से आम जनता तक इसकी सूचना/जानकारी पहुंचे कि आज आपका स्मार्ट कार्ड बनना है। एक तो इसके बारे में जानकारी चाही थी।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पैसिफिक प्रश्न पूछा था कि कौन-सी एजेंसी है जिसके माध्यम से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है?

तीसरी, जो जानकारी मुझे चाहिए थी, उसमें प्रमुख रूप से यह है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसा होता है कि जब एजेंसी वाले पंचायतों में कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो किसी कारण से परिवार का सदस्य वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसका नाम कार्ड में इंक्लूड नहीं हो पाता। उसमें परिवार का वही सदस्य इंक्लूड हो पायेगा जो वहां पर उपस्थित होगा। उसका फोटो होगा और उसका फिंगर प्रिंट होगा। उसके बाद जब परिवार का सदस्य छूट जाता है तो छूटने के बाद जिस तारीख को वहां पर यह सारी प्रक्रिया करने के लिए एजेंसी के माध्यम से लोग आए होते हैं वे चले जाते हैं तो फिर उसके बाद हट करके नहीं आते हैं। दूसरी बार, आने वाले समय में उनको भी कवर कर सकें इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाये गए। एक तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत सिर्फ इंडोर पेशैंट आते हैं। जो आउटडोर पेशैंट हैं जिनको गम्भीर बीमारी है एक बड़ा खर्चा उनके इलाज पर होता है क्या उनको भी इस योजना में कवर करने के आदेश करेंगे?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने कार्ड बनाने की प्रक्रिया के बारे में प्रश्न पूछा है उसमें ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण के साथ मिल करके जिनमें कि पंचायत सचिव भी शामिल होते हैं कार्य सलाह का आयोजन करती है। पंचायतवार कार्ड बनाने का प्लान बनाया जाता है। उसी प्लान के आधार पर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि पंचायत में जाकर कार्ड बनाते हैं। जो बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि हैं वे पंचायतों में जा करके जो भी इस कैटेगिरी में आते हैं उनके कार्ड बनाते हैं। स्मार्ट कार्ड प्रिंट करने के लिए पंचायत सचिव का अंगूठा लगाया जाता है। उसी के बाद कार्ड प्रिंट करके उनको दिया जाता है। जो डाटा एक बार वैबसाइट पर डाला जाता है उसमें एक वर्ष तक फिर एडिशन नहीं की जाती। इन्होंने कहा कि कुछ लोग बच जाते हैं। लाभार्थी पंचायत में आते नहीं हैं वे फिर एक साल के लिए महरूम रह जाते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारी इंश्योरैंस कम्पनी है उनको निवेदन करेंगे कि साल में दो बार भी पंचायतों में जाकर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। लेकिन जब कार्ड बन जाते हैं तो यह काम हैल्थ मिनिस्ट्री में आ गया। उनको डाटा देते हैं फिर वह डाटा वैबसाइट में शामिल कर देते हैं। जहां तक आपने कहा कि ओ0पी0डी0 में कुछ बड़े क्रिटीकल केयर के लोग आते हैं। जब डॉक्टर यह वैरिफाई करता है, डाइग्नोज़ करता है कि वह क्रिटीकल केयर का पेशैंट हैं तो उनको तुरन्त इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज (कांगड़ा) और पी0जी0आई0, चंडीगढ़ को रैफर करता है तो उसके आने-जाने के किराये का एक हजार रुपया और सारा इलाज 1,75,000/- रुपये तक मुफ्त किया जाता है।

Secondly, Speaker Sir, under RSBY OPD costs are not covered. ओ0पी0डी0 कॉस्ट कवर नहीं करती। लेकिन जब डॉक्टर यह डाइग्नोज़ करता है कि यह क्रिटीकल केयर का पेशैंट है और टैस्ट करने के बाद यह प्रूव हो जाता है then his case is referred to three prestigious institutions of the State. However the Government of India has now announced Universal Health

30.03.2015/1410/SS-AG/3

Insurance Scheme under which free medicines and diagnostic are to be covered in this free medical treatment.

जारी श्रीमती के0एस0

/1415/30.03.2015केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1826 जारी—

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी
यह भी अब गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने हमें हिदायतें दी है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो 4,01,427 परिवार जो इसमें बचें हैं उनके कार्ड कब बनाए जाएंगें और उनकी ड्राईव कब लगाई जाएगी ताकि वे भी इसका लाभ ले सके?

दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी तिथि और कौन से वर्ष में हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भ हुई थी और तीसरा, पी.जी.आई. को हमने इस सुविधा के लिए इन्क्ल्यूड किया है और जो पी.जी.आई. में हमारा कार्यकता, सरकारी कर्मचारी है, वहां जो हम किसी प्रकार का कम्युनिकेशन हिमाचल के मरीजों को देते हैं वह अपर्याप्त है। एक व्यक्ति सोलन जिला का हस्पताल का वहां पर रहता है जिसका कोई ऑफिस नहीं है। हिमाचल के विभिन्न स्थानों से जाने वाले मरीजों को यही जानकारी मिलती है कि पी.जी.आई. में उनका ईलाज नहीं होगा। ऐसे में क्या हम पी.जी.आई. में और सेक्टर-32 गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज, चण्डीगढ़ में अपना कोई ऑफिस खोलकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा का सहयोग अपने मरीजों को दिलाने का प्रयास करेंगें क्योंकि वहां पर मरीज जा रहे हैं और उसके बाद वे माननीय मुख्य मंत्री जी को मुख्य मंत्री राहत कोष के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं या अलग-अलग जगह पर भेजते हैं फिर बी.पी.एल. कार्ड उसके साथ लगाते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ।

/1415/30.03.2015केएस/एजी/2

अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन चीजें जाननी चाही है। चार लाख परिवारों का बीमा कब करेंगें? दूसरा, हिमाचल में यह योजना कौन सी तारीख को शुरू हुई और तीसरा, पी.जी.आई. और सेक्टर-32 में क्या आप अपना कोई कार्यालय खोलकर उसको विधिवत्त चलाएंगें ताकि लोगों को लाभ मिले?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले कहा कि यह जो मैंने 8 लाख 81 हजार की बात की, मैंने कहा कि इसमें बहुत डुप्लीकेशन है और जो डुप्लीकेट हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा इसलिए 30 से 40 प्रतिशत की डुप्लीकेशन है तो 40 प्रतिशत इसमें अपने आप ही कम हो जाएंगें । जो बचेंगें उसके अलावा जनवरी, 2013 तक कुल कार्ड थे 3,83,464 और अभी पिछले दो-तीन दिन पहले तक अब 4,79,606 कार्ड यानि लगभग 90-95 हजार कार्ड हमारे दो साल के अंदर बने हैं और इसके अलावा माननीय सदस्य ने पूछा कि यह स्कीम कब लागू हुई है? तो दो जिलों में यह स्कीम 2008-09 में लागू हुई है जिसमें कांगड़ा और शिमला जिला शामिल किया गया। उसके बाद 1 मार्च, 2010 को पूरे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी है। आपने कहा कि हमारा एक अधिकारी है We have posted one Doctor/official वह डिप्लॉय किया गया है पी.जी.आई. शॉपिंग कम्पलैक्स में उसका दफ्तर है और जब भी हम दोनों मैडिकल कॉलेज से कोई केस पी.जी.आई में रैफर करते हैं तो उसका वहां लायसन करता है उसके ट्रीटमैंट के लिए he is also PG Doctor.

/1415/30.03.2015केएस/एजी/3

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, पी.जी.आई. में उसका दफ्तर नहीं है, यही हम चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री जी पी.जी.आई. में और सैक्टर-32 गवर्नमैंट हॉस्पिटल को भी प्लीज़ इन्क्लूड करें क्योंकि पी.जी.आई. में बहुत रश होता है, तो क्या आप वहां पर एक छोटा सा दफ्तर चाहे 6"x6" फुट का खोले, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश का कोई अंक लगाओ । वहां पर मरीजों को पता नहीं लगता है । क्या आप सदन को ऐसा आश्वासन देंगें इन गरीबों की मदद के लिए?

Health & Family Welfare Minister: Speaker, Sir, definitely we will take steps. We will ask the Director, PGI to allot one small room for the office of that Doctor so that at least his location is known to the patients who are referred from this place. उसके लिए हम डायरैक्टर से व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगें । पी.जी.आई. में अगर वह दफ्तर देंगें निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगें। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इसके बारे में बात करूंगा।

श्रीमती अ0व द्वारा-

30.3.2015/1420/ag/av/1

प्रश्न संख्या : 1826 --------क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी----------
मैं व्यक्तिगत तौर पर इसके बारे में बात करुंगा। जहां तक सैक्टर 32 मैडिकल कॉलेज की बात है वैसे ही हमारे मैडिकल कॉलेज भी हैं। इसलिए हमने सैक्टर 32 मैडिकल कॉलेज को इसमें नहीं किया है। इसके लिए हमने पी.जी.आई. और दो अपने मैडिकल कॉलेज को ही प्रैस्टिजियस इनस्टिच्यूशन्ज आईडैंटिफाई किए हैं।

समाप्त

30.3.2015/1420/ag/av/2

प्रश्न संख्या : 1827

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जंगलों में क्रीपर्ज की बड़ी गम्भीर समस्या है। यहां पर दी गई सूचना मुझे गोल-मोल सी लग रही है। क्रीपर्ज पैरासाइट्स हैं और पाइन ट्रीज को छोड़कर यह दयार इत्यादि के पेड़ों पर पूरी तरह से छाई हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं है, आप जंगल में जाकर देखिए कि इनको काटा-वाटा नहीं जाता। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या विभाग के पास इस संदर्भ में कोई डाटा है कि इससे कितने प्रतिशत पेड़ प्रभावित हुए हैं? दूसरे, आप इन क्रीपर्ज को किस सीजन में काटते हैं तथा इसके लिए आपने प्रदेश में कितनी मैन-पावर्ज रखी है? साथ में, यह भी बताया जाए कि हर सीजन में इस संदर्भ में आप कितना खर्चा करते हैं?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास यह सूचना नहीं है और माननीय सदस्य को यह सूचना बाद में उपलब्ध करवा दी जायेगी। आपने दरख्तों पर फैली बेलों को काटने के बारे में पूछा है कि किस सीजन में काटी जाती है। इनके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि इनको सीजन के मुताबिक काटा जाता है। जब सेब के पेड़ों की कटिंग एण्ड प्रूनिंग होती है उस समय इनको काटा जाता है। इसी तरह से सर्दियों तथा बरसात के मौसम में इनकी बेलों को काटा जाता है।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, खेद का विषय है कि मंत्री जी ने एक साथ दोनों बातें कह दीं। इन्होंने एक तरफ कहा कि इन बेलों का कोई असर नहीं होता और दूसरी तरफ यह कहा कि पेड़ों के विकास में इनका कूप्रभाव पड़ता है। साथ में, आपने यह भी कहा कि इन क्रीपर्ज को काटा जाता है जो कि मेरी सूचना के मुताबिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। हम में से काफी लोग जलोड़ी-जोत होकर जाते हैं या दूसरी जगह भी जाते हैं। वहां हजारों की संख्या में पेड़ सूख रहे हैं। न केवल दूसरे पेड़ बल्कि देवदार के पेड़ ऊपर चोटी से सूखना शुरु होते हैं। यहां माननीय मंत्री कौल सिंह जी बैठे हैं और इनके क्षेत्र में भी यह समस्या है। पैरासाइट्स का क्रीपर तो

30.3.2015/1420/ag/av/3

निश्चित रूप से पेड़ की खुराक भी चूस लेता है। उसकी वजह से पेड़ सूखते हैं। अगर किसी और बीमारी से भी सूखते हैं तो क्या मंत्री जी ने इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण करवाया कि इन पेड़ों के सूखने का क्या कारण है और पिछले पांच वर्षों में कितने पेड़ सूखे? इसके अतिरिक्त देहरादून में जो रिसर्च सैंटर है वहां इसकी जानकारी के लिए कोई टैस्ट करवाएं कि इसको किस प्रकार रोका जा सकता है? पिछले पांच सालों में जो पेड़ सूखे हैं उनकी गणना क्या है और उनको किस काम में लाया गया? फॉरैस्ट सैटलमैंट में आपको यह अधिकार था कि जितने बर्तनदार हैं वे साल में दो बार जंगल में जायेंगे। वे वहां आपकी देख-रेख में शाख-तराशी भी करेंगे तथा इस प्रकार के झाड़ भी हटायेंगे ताकि जंगलों में आग न लगे। सर्दियों के मौसम के बाद वे फिर जाते थे और वहां पर अपरूटिड ट्रीज या गले-सड़े पेड़ों को बाहर निकालते थे जिससे जंगल की सफाई होती थी। टी.डी. राइट तो आज भी है। लेकिन जो लोगों का फायर लाइन बनाने का दायित्व था आज विभाग न तो उनका उसमें सहयोग लेता है और न ही इन झाड़ियों को काटने में सहयोग लेता। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इन झाड़ियों को काटने वाला कौन है?

अध्यक्ष श्री बी.जे.द्वारा जारी

30.03.2015/1425/negi/ag/1

प्रश्न संख्याः 1827....जारी...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी अगर आपके पास सूचना है तो दे दीजिए।

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,जैसे मैंने बताया कि वनवर्धन गतिविधियों के अन्तर्गत 2014-15 के लिए कुल 1.80 करोड़ रूपये की वार्षिक कार्य योजना का प्रावधान रखा गया । इस योजना के तहत वृत-वार स्वीकृत राशि का ब्यौरा इस प्रकार से हैः- बिलासपुर में 15 लाख, चम्बा में 15 लाख, धर्मशाला में 15 लाख, हमीरपुर में 15 लाख, कुल्लू में 20 लाख, मण्डी में 25 लाख, नाहन में 25 लाख, रामपुर में 20 लाख तथा शिमला में 30 लाख, इस तरह से 1.80 लाख रूपये इसको काटने के लिए ही खर्च किया है ।

श्री महेश्वर सिंह : यह काम बर्तनदारों का है। क्या आपने इस परम्परा को छोड़ दिया है? क्योंकि न तो आज फायर लाईन बनती है । जो आपने कहा कि शाक्त राशि में इतना खर्चा हुआ तो किन-किन वनों में कितनी सफाई हुई ? बेशक आप यह सूचना बाद में दीजिए कि शाक्त राशि कितनी हुई और कौन-कौन से जंगल साफ हुए?

अध्यक्ष :माननीय मंत्री जी अगर सूचना है तो दे दीजिए।

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, टी.डी. राइट्स उन्हीं को दिए जाते हैं जिनके वाजिवुल अर्स में राइट्स हैं और वे उस ढ़ंग से कोऑपरेट भी करते हैं। पहले तो लोगों ने जंगल में जब आग लगती थी तो जाना ही बन्द कर दिया था सिर्फ फोरेस्ट वाले ही जाते थे। लेकिन हमने यह कंडिशन लगाई है कि टी.डी. उन्हीं को मिलेगी जो जंगल में आग लगते समय कोऑपरेट करेंगे। तभी जंगल बचेगा नहीं तो बात कहां से बनेगी । इसीलिए लोगों को इसमें इनवॉल्व करने के लिए हमने कंडिशन लगाई है।

समाप्त

प्रश्न संख्याः 1828.

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। हमें बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि जो जनहित के प्रश्न होते हैं उनके बारे में जब भी हम यहां प्रश्न करते हैं तो उत्तर आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह कार्यप्रणाली सरकार की, सामने नज़र आ रही है। हर प्रश्न में हम यही देखते आ रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी एश्योर करेंगे कि इसी सत्र में, इसी सेशन में यह सारी सूचना दे दंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता का स्वागत है। यह डिटेलड इंफोर्मेशन है which concerns a Centrally Sponsored Scheme like Indira Awas Yojna and various other schemes. Hence, it will take some time. But we will try our best, if it comes, we shall give it to the House and to the Hon'ble Member also.

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष जी, यह सैटिस्फैक्टरी जवाब नही है। जब प्रार्थी की एप्लीकेशन आती है तो वह कम्प्यूटर पर ऐड होती है, वो चाहे गृह निर्माण की हो और चाहे पैंशन की हो, यानि जो भी हो। 12 जिलों की कम्पॉइल करके सूचना इस मान्य सदन में देने में कितना समय लेगेगा? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इसी सत्र में यह सूचना उपलब्ध करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, यह सूचना इस सत्र में आ जाएगी कि नही आएगी, आप यह बताइये।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रयास जारी है क्योंकि यह विस्तृत सूचना है और ठीक तरीके से ही यह सूचना देनी चाहिए। जैसे ही आएगी, शीघ्र ही आपको मुहैया करवा दी जाएगी।

समाप्त

30.03.2015/1425/negi/ag/3

अध्यक्षः अगला प्रश्न-182 -9श्री गोविन्द राम शर्मा जी. - एबसेन्ट.

अगला प्रश्न - 1830श्रीमती यू.के. द्वारा जारी...

30/1430/2015/03/यूके/एजी/1

प्रश्न संख्या1830 -

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो उठाऊ सिंचाई योजना है मझैरना है उसको पुनः चालू करने के लिए कब तक धन उपलब्ध होगा।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें थोड़ा विस्तार मे बताना चाहंगा कि लिफ्ट इरिगेश स्कीम कूकेना में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है was accorded amounting to Rs. 5.70 lacs on 17th February, 1987 and work of scheme was taken in hand. The scheme was completed during the year 1992 at a completion cost of Rs. 10 lacs. As per the sanctioned scope of the scheme, the area to be covered is 45 hectares. और उसके अलावा ईयरवाईज हम बजट के ऐक्सपेंडीचर को भी इन्क्रीज करेंगे ताकि आपकी इस स्कीम कम्पलीट किया जा सके। उसके अलावा मझैरना उठाऊ सिंचाई योजना के बारे में भी थोड़ा आपको बताना चाहूंगी कि इसके वर्क के लिए 15,51,000 रुपए की ऐक्सपेंडीचर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 3 0जुलाई 1989 में हुई है इस स्कीम के काम को शुरु कर दिया है तथा यह स्कीम जल्दी से हो जायेगी और जो आपकी यह स्कीम 1990-91 की है जिसके लिए 29,10,000 सैंक्शन करके इसके लिए 234 हैक्टेयर लैण्ड का प्रोपोज़ल प्रोवाईडिड होगा, इरिगेशन के लिए, इस स्कीम की फैसिलिटी के लिए, जिसका आपको पूरा फायदा होगा। इसके अलावा आपको इसमें जो भी कमी दिखाई देती है उसको हम दूर करेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूं कि however, the rising main now consists of 400 mm dia of CI pipes/AC pressure pipes and Mild pipes जो माईल्ड स्टील पाईप्स आपकी बहुत पुरानी होती हैं, किसी जमाने की, वे पाईप्स हैं। ये डिफरैंट रीजन्स में हैं। इस स्कीम को रिमॉडलिंग करने की आवश्यकता है

। डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम चाहेंगे कि आपको रिक्वायर करके रिप्लेस कर दिया जायेगा । जहां आपको दिक्कत आ रही है To make the scheme fully functional, funds amounting to Rs. 1.93 crores are required for replacement of old rising main, distribution system, renovation of delivery tanks and repair of pump house etc. The pumping machinery of this scheme was replaced during the year 2007-

30/1430/2015/03/यूके/एजी/2

2008 and is in the working order. कितने पुराने जमाने का होगा, वह आप समझ सकते हैं कि कितना वर्किंग ऑर्डर हमको देखना पड़ रहा है । माननीय विधायक जी, हम आपको तसल्ली देना चाहते हैं We have requested you verbally long time back as well as in writing to include the remodelling of this scheme under MLA priority. The DPR for the remodelling of the scheme shall be prepared after inclusion of the scheme in MLA priority. So, don't worry. Everything will be coming back to you.

30/1430/2015/03/यूके/एजी/3

प्रश्न संख्या- 1831

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने CHCs हैं ? क्या किसी भी CHC के अन्दर जो पॉपुलेशन है 80,000 से कम नहीं आती है? पहले यह बताएं, उसके बाद आगे पूछूंगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कुल 78 CHCs हैं और एवरेज पॉपुलेशन कवर्ड जो हैं इन 78 CHC में, 80,320 बनती है तो इसलिए प्लेन एरिया में 1लाख 20 हजार की पॉपुलेशन पर एक CHC बनता है और हिली और ट्राईबल एरिया में भारत सरकार ने हमें 80 हजार की पॉपुलेशन दी है।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी--

30.03.2015/1435/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 1831....जारी

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री... जारी
केवल 80,000 की जनसंख्या दी है, इतनी जनसंख्या पर सी.एच.सी. बन सकता है।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राम शहर तीन असैंबली निर्वाचन क्षेत्रों का केंद्र बिंदु है। यहां इन तीनों क्षेत्रों की जो पंचायतें हैं उनकी जनसंख्या के दृष्टिगत अगर इस पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में अपग्रेड किया जाए तो यहां के लोगों को लाभ मिलेगा। जहां तक जनसंख्या का प्रश्न है, अगर मंत्री जी इसकी गणना करवाएं तो यह 80,000 से ऊपर होगी। मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि अगर यह क्षेत्र 80,000 की जनसंख्या की कंडिशन को मीट विद करे तो क्या इस पर विचार करेंगे? पिछले कई सालों से इसकी मांग चली आ रही है इसलिए मैं इसकी अपग्रेडेशन का आश्वासन चाहता हूं।

Health & Family Welfare Minister: Mr. Speaker, Sir, in Nalagarh Constituency, the position of staff and location of PHC, CHC and Civil Hospital, I think, that is more than sufficient to cater with the total population of Nalagarh Constituency. At present, in Nalagarh Constituency, there is already one CHC, eight PHCs, 43 Health Sub Centres. अध्यक्ष महोदय, नालागढ़ में अब हमने इनके अस्पताल को सिविल अस्पताल बना दिया है और वह 100 बिस्तरों का है। वहां डॉक्टर्ज़ भी सरप्लस हैं, स्टॉफ नर्सें भी सरप्लस हैं और दूसरा स्टॉफ भी सरप्लस है। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा है कि रामशहर तीन निर्वाचन क्षेत्रों का सैंटर है; वैसे तो बद्दी चुनाव क्षेत्र में भी चण्डी सबसे पुराना पी.एच.सी. है लेकिन वहां भी पापुलेशन नार्म फुलफिल नहीं होता। इसलिए अभी तक इसका मामला विचाराधीन नहीं है। जब पापुलेशन बढ़ेगी या

30.03.2015/1435/sls-ag-2

भारत सरकार पापुलेशन का क्राईटेरिया कम करेगी, तब इस पर विचार किया जाएगा।

समाप्त

30.03.2015/1435/sls-ag-3

प्रश्न संख्या : 1832

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न का जो जवाब दिया है ,इसके दृष्टिगत मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ की भौगोलिक स्थिति चण्डीगढ़ जैसी है और बाकी हिमाचल से भिन्न है। इसलिए जो सैटबैक्स किसी भी मकान का नक्शा पास करने में चारों तरफ छोड़े जाते हैं ,उनमें बहुत सारी जगह जाया हो जाती है; उपयोग योग्य जगह कम बचती है। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि नियमों में हमारे क्षेत्र में चण्डीगढ़ की तर्ज़ पर केवल आगे और पीछे ही सैटबैक छोड़ने की अमैंडमैंट करने की कृपा करेंगे?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ही इस प्रकार से चारों तरफ सैटबैक छोड़े जाते हैं। वह एक तरह से सनलाईट, वैंटिलेशन और कभी नैचुरल कैलेमिटी हो जाए ,उसके लिए बफ़र जोन का काम करते हैं। इसलिए अभी सरकार का ऐसा कोई विचार नही है।

डॉ० राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके यहां सैटबैक के क्राईटेरिया में फ्लोर एरिया रेशो का प्रावधान है और फ्लोर एरिया रेशो क्या सबसे बेहतर सांईटिफिक मैथड है या नहीं? अगर फ्लोर एरिया रेशो लग रहा है तो उसके अंदर सैटबैक तो फ्लोर एरिया रेशो से ही डिसाईड होगा। इसलिए आगे-पीछे, दाहिने-बाएं का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फ्लोर एरिया रेशो पर हमारे सैटबैक कैलकुलेट हो रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सैटबैक्स हैं वह फ्लोर एरिया रेशो के हिसाब से ही प्रदेश में निर्धारित किए जा रहे है। मैंने पहले ही कहा कि भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं। जो मूल प्रश्न है, जो इन्होंने पूछा है उसमें ऐसी कोई बात अभी तक न सरकार

के विचार में है, न मैं समझता हूं कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा उचित होगा।

30.03.2015/1435/sls-ag-4

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इस बात से अवगत हैं कि टाऊन एंड कंट्री प्लॉनिंग एक्ट पर गत विधान सभा बजट सत्र में बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी ..

जारी...गर्ग जी

30/03/2015/1440/RG/AG/1

प्रश्न सं. ---- 1832क्रमागत

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सारी रिटैन्शन पॉलिसी इनक्लूडिंग सैट बैक इत्यादि पर पिछले बजट सत्र में विधान सभा में बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी और जो ये विधेयक लाए थे उसको इन्होंने प्रवर समिति को रैफर किया था ,लेकिन प्रवर समिति ने उस पर गहन विचार करके उसको लौटा दिया। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में उस समिति की बैठकें हुई थीं। उसके पश्चार ऑर्डिनैंस जारी हुआ, नियमों में कुछ परिवर्तन हुए। जो चतुर या महत्वाकांक्षी लोग थे वे तो लाभान्वित हो गए, लेकिन सीधे-सादे लोग आज भी उस रिटैन्शन पॉलिसी के इन्तजार में हैं। ऐसा हुआ,

तीन बुलाए, तेरह आए, देखो यहां की रीत,
बाहर के आकर मौज करे और घर के गाये गीत।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब तक ये विधेयक लाएंगे ताकि लोगों को राहत मिले।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपने जो फैसला किया है वह बता दीजिए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है ,मूल प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है। जो इन्होंने पूछा है, तो ये स्वयं उस समिति के सदस्य थे और समिति ने जो प्रस्ताव किए हैं वे सरकार के विचाराधीन हैं।

प्रश्न समाप्त

2/-

30/03/2015/1440/RG/AG/2

प्रश्न सं. 1833

अध्यक्ष : श्री बिक्रम सिंह जरयाल, प्रश्न सं. 1833, अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 1834

अध्यक्ष : प्रश्न सं. 1834, श्री संजय रतन अनुपस्थित ।

30/03/2015/1440/RG/AG/3

प्रश्न सं. 1835

श्री ईश्वर दास धीमान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने उत्तर में सात सिविल हॉस्पीटल बताए हैं, तीन में पदों का सृजन भी कर दिया गया है और भरे कितने हैं उनका उत्तर नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत हैरानी की बात है कि सी.एच.सी. से जो सिविल हास्पीटल बने, नॉर्म्ज के मुताबिक सी.एच.सी. में 24 और सिविल हास्पीटल में 40 पोस्ट्ज होती हैं। डॉक्टर्ज के 4 से 6 पद, वार्ड सिस्टर्ज के 1 से 2 और सिविल हॉस्पीटल के लिए नर्सिस, एम.पी.डब्लू. ,ओ.टी.ए. इत्यादि की भी कुछ नई पोस्ट्ज क्रियेट होती हैं। आपने विभागीय उत्तर में कहा है कि 4 नागरिक अस्पतालों में पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ,तीन नागरिक अस्पतालों में पदों का सृजन किया है। अब मुझे यह समझ नहीं आता कि जो आपने तीन सिविल हॉस्पीटल अपग्रेड

किए हैं जैसे हरोली में तो आपने सात पद दे दिए, इसी प्रकार सुन्नी में 15 दे दिए ,लेकिन भोरंज में केवल दो पद दिए एक चिकित्सक और दूसरा वार्ड सिस्टर की पोस्ट दी। इसके क्या कारण हैं? भोरंज हमीरपुर सिविल हॉस्पीटल को छोड़कर दूसरा एक ऐसा सी.एच.सी. था।

अध्यक्ष : धीमान साहब, आप संक्षेप में अपना सप्लीमैंट्री प्रश्न कीजिए।

श्री ईश्वर दास धीमान : तो मैं जानना चाहूंगा कि इतना फर्क क्यों है और इसके क्या कारण हैं? जहां 16 पोस्ट्ज आनी हैं कहीं आप सात देते हैं, कहीं 15 देते हैं और सी.एच.सी., भोरंज में केवल दो पद देते हैं। इसके कारण बताए जाएं। इसके अतिरिक्त जो ये ऑउटडोर एवं इण्डोर की बात करते हैं वह भी सूचना दी जाए कि किसमें कितनी संख्या है, यदि आप संख्या के मुताबिक अपग्रेड कर रहे हैं। यह मैंने सिर्फ 50 बैड का दिया है ,मैंने 100 या 200 बैड का नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय, भवनों के बारे में इन्होंने कहा है कि कुछेक भवन निर्मित हो चुके हैं------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2015/1445/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 1835क्रमागत----श्री ईश्वर दास धीमान जारी-----

मैंने 100और 200 बैड का नहीं दिया है, एक तो यह बताया जाए। भवनों के बारे में आपने बताया है कि कुछेक भवन निर्मित हो चुके हैं और कुछेक भवन निर्माणाधीन हैं।
अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप कृपा करके अनुपूरक प्रश्न पूछिए।
श्री ईश्वर दास धीमानः उनके लिए अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया गया है।

अध्यक्षः भवनों का तो इधर सवाल ही नहीं है। आप सप्लीमैंट्री थोड़े न कर रहे हैं?
श्री ईश्वर दास धीमानः आप मुझे प्रश्न तो करने दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि ये भेदभाव जो मैंने पहले बताया, पदों में क्यों है और वे कौन-कौन से सिविल अस्पताल हैं, जिनमें अभी तक भवनों का कोई प्रबंध नहीं है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, अगर आप अनुबंध 'क' देखें तो उसमें विस्तृत तौर पर बताया गया है कि PHCs में नॉर्म्ज के मुताबिक कितने डॉक्टर्ज होने चाहिए ,CHCs में कितने होने चाहिए और जो CHCs छः बिस्तरों से 50 बिस्तरों का सिविल अस्पताल बनता है, उसमें कितने डॉक्टर्ज होने चाहिए। हमने 100 और 200 बिस्तरों का बताया हुआ है। माननीय सदस्य ने भोरंज की बात कही है। जहां तक 50 बैड CHC का सिविल अस्पताल का प्रश्न है तो सभी में स्टाफ बराबर है। हरोली में स्टाफ कम था क्योंकि इंटरनलाइजेशन से CHC बना था। वहां पद सैंक्शन नहीं थे इसलिए हरोली को 50 बिस्तरों के सिविल अस्पताल के लिए पद स्वीकृत किए। भोरंज में CHC में पहले ही चार डॉक्टर्ज उपलब्ध थे, उसको सिविल अस्पताल मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार बनाया गया है। सभी सिविल अस्पताल जो 50 बिस्तरों के हैं, सबको नॉर्म्ज के मुताबिक बराबर पद दिए गए हैं। कइयों में पहले डॉक्टर्ज लगे थे। कइयों को इंटरनलाइजेशन से कहा था कि इसको अपग्रेड तो कर देते हैं लेकिन डॉक्टर्ज और पैरा मेडिकल स्टाफ के पद नहीं देंगे। विभाग अपने आपस में एडजस्टमैंट करने की कोशिश करे। इसलिए हरोली को ज्यादा दिए गए बाकी हरोली के अलावा दूसरे अस्पतालों में जितना स्टाफ था, उसके मुताबिक ही स्टाफ दिया गया है। जो माननीय सदस्य ने कहा कि कितने सिविल अस्पताल सरकारी भवनों में हैं। भवनों की सूची के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि चरणबद्ध

30/03/2015/1445/MS/AG/2

कार्यक्रम में जो हमने CHC से सिविल अस्पताल बनाए हैं, उनको 50 बिस्तरों के अस्पताल बनाने का प्रबंध करेंगे। कुछ में ऑलरैडी उपलब्ध हैं और कुछ में उपलब्ध नहीं हैं।

श्री ईश्वर दास धीमानः अध्यक्ष जी, यह देखने वाली बात है। मंत्री जी ने यहां दिया हुआ है कि कितने पद CHC में सृजित होते हैं और कितने पद सिविल अस्पताल में होते हैं। भोरंज में सिविल अस्पताल बनने से पहले ही पद क्या भर दिए गए थे? मंत्री महोदय आप मुकाबला तो कीजिए। आपके PHC में दो डॉक्टर्ज होते हैं ,CHC में चार होते हैं और 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में छः डॉक्टर्ज होते हैं। ये पद क्या आपने पहले भर दिए थे? वार्ड सिस्टर का एक पद CHC में होता है और दो पद 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में होते हैं। क्या ये पद पहले भर दिए थे? इसी तरह से अगर आगे चलें तो कुछ पद तो CHC में होते ही नहीं हैं जो सिविल अस्पताल में होते हैं। क्या वे पद नहीं भरने होते हैं ?

आप क्या गोलमोल जैसा जवाब दे रहे हैं? मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि आप जैसा सीनियर मंत्री यहां पर गलत आंकड़े और जाल बिछाकर यहां मिसलीड कर रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया आप अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री ईश्वर दास धीमानः इस बात को क्लीयर किया जाए। यह क्या कारण है, क्या इतना फर्क हो सकता है? वैसे मैं मान सकता हूं कि कुछ पदों में ऐसा हो लेकिन 24 से 40 तो पोस्टें होनी हैं। ये 16 पद तो आने ही हैं और 16 पदों की जगह आप दो पद दे रहे हैं? मुझे बताया जाए कि इसका क्या कारण है?

Health & Family Welfare Minister: Sir, Health Department has fixed norms for PHC, CHC, 50 bedded hospital, 100 bedded hospital and 200 bedded hospitals. इसमें अगर आप अनुबंध 'क' पर देखेंगे तो पूरा डिटेल दिया हुआ है। कुछ PHC जो पहले खुले थे उनमें दो डॉक्टर्ज के पद होते थे। अब जो नये PHC खुल रहे हैं उनमें एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक क्लास फोर लगा रहे हैं। उसी तरह मैंने कहा है कि 50 बिस्तरों का जो अस्पताल होता है उसमें छः डॉक्टर्ज लगाए जाते हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

30.03.2015/1450/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1835:------जारी----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः-----जारी----

उनमें 10 स्टाफ नर्सिज लगाई जाती हैं। 2 वार्ड सिस्टर लगाई जाती हैं। इसी तरह से सीनियर लैब एस्सिटैंट 2 लगाए जाते हैं। रेडियोग्राफर 1 लगाया जाता है। ओ.टी.ए. एक लगाया जाता है। ऑथ्थैलमिक असिस्टैंट एक लगाया जाता है। फार्मासिस्ट दो लगाए जाते हैं। यह सारे की सारी डिटेल हमने अनैक्चर में दी है। जिन सी.एच.सीज़. में पहले ही स्टाफ ज्यादा था उनमें हमने उतना ही स्टाफ दिया जितनी कमी थी और कोई डिफरैंस वाली बात नहीं है। भोरंज में यदि धीमान साहब स्टाफ कम है और वहां पर स्टाफ की ज्यादा जरूरत है तो हम वहां पर स्टाफ ज्यादा लगाएंगे। हमने ही भोरंज को अपग्रेड किया है। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए। भोरंज आपके चुनाव क्षेत्र के नाम

पर है। उसको हमने अपग्रेड करके कम्युनिटी हॉस्पिटल से सीविल हॉस्पिटल 50 बेडिड का बनाया है। अगर उसमें कोई स्टाफ की कमी होगी तो आप हमें बताएं वहां पर 6 ही डॉक्टर्ज लगा दिए जाएंगे।

श्री बिक्रम सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर ज़वाब आया है इसमें लिखा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को नागरिक अस्पताल के रूप में उन्नयन करने के लिए सम्बन्धित संस्थान की IPD/OPD से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है। एक तो इन्होंने पी.एच.सीज. से 10 सी.एच.सीज. बनाए और सी.एच.सीज. 7 अपग्रेड की गई । सबसे ज्यादा संख्या इसमें हरोली विधान सभा क्षेत्र की है। क्या हरोली में ज्यादा लोग बीमार रहते हैं? IPD/OPD की जनसंख्या आपने लिखी है। जो आपने अपग्रेड किए हैं इनमें कितने-कितने IPD/OPD थे जिसके कारण इनको अपग्रेड करना पड़ा? दूसरे, जो बाकी प्रस्ताव आपको पूरे हिमाचल प्रदेश से आए हैं, क्या उनमें IPD/OPD की संख्या जो आपने अपग्रेड किए हैं उनसे कम है? हमें यह बताएं कि पी.एच.सीज., सी.एच.सीज. और सीविल

30.03.2015/1450/जेके/एजी/2

हॉस्पिटल्ज में कितने-कितने बैड होते हैं? हिमाचल प्रदेश में कितनी ऐसी पी.एच.सीज़. हैं जिनमें एक भी डॉक्टर नहीं है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि पी.एच.सी. में बिस्तरों की कितनी संख्या होती है और सी.एच.सी. में कितनी होती है ओर सिविल हॉस्पिटल में कितनी होती है तो पी.एच.सी. में 6 बिस्तरों का प्रावधान होता है जहां सरकारी भवन बने हैं और बिस्तरें उपलब्ध हैं। जो सी.एच.सीज. है उनको 6 बिस्तरों से सीधे 30 बिस्तरों का हम कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर्ज बनाते हैं। उनमें 4 डॉक्टर्ज का प्रावधान किया जाता है। सीविल हॉस्पिटल्ज 4-3किस्म के हैं। एक तो 50 बिस्तरों वाला है, उसमें 6 डॉक्टर्ज लगाए जाते हैं। एक 100 बिस्तरों का होता है और एक 200बिस्तरों का होता है। ज़ोनल हॉस्पिटल्ज 300 बिस्तरों के होते हैं । जहां तक आपने कहा कि कितने पी.एच.सीज़ ऐसे हैं, यह मुख्य प्रश्न में नहीं पूछा गया है अगर आप प्रश्न पूछेंगें, हमारी कोशिश है और मैंने माना है कि डॉक्टर्ज की हिमाचल प्रदेश में कमी है। उसमें हमारी कोशिश यह है कि कम से कम हर पी.एच.सी. में एक डॉक्टर उपलब्ध करवा दिया जाए। हर मंगलवार को डॉक्टरों के इन्टरव्यू लिए जा रहे हैं। जो डॉक्टर्ज़ आ रहे हैं हम

उन खाली पी.एच.सीज. में उन डॉक्टरों को भेज रहे है। जहां तक प्रश्न IPD/OPD का है जब भी कोई प्रोपोज़ल विभाग के पास आती है तब हम उसकी फीज़िबिलिटी देखने के लिए निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को इग्जामिन करने के लिए भेज देते हैं। वह उसकी रिपोर्ट सी.एम.ओ. से मंगवाता है और जो रजिस्टर के मुताबिक IPD/OPD का परसेंटेंज कितनी है, इन्डोर की कितनी परसेंटेज हैं और ऑऊट डोर पेशैंट साल के अन्दर कितने आते हैं उसके आधार पर फैसला लिया जाता है? कुछ फैसलें प्रशासनिक आधार पर किए जाते हैं। कुछ फैसले जरूरत के मुताबिक किए जाते हैं।

प्रश्न समाप्त।

अगला प्रश्न श्री एस.एस. द्वारा जारी------

30.03.2015/1455/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1836

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि डलहौजी की जो सीवरेज स्कीम है इसका 20 साल से काम चालू नहीं हुआ है। इसका बजट एस्टीमेट भी डबल हो गया है। 851 लाख से 1700 लाख हो गया है। एक तो मैं यह जानना चाहूंगी कि इस वित्तीय वर्ष यानी 16-2015में कितना बजट प्रावधान है?

दूसरा, आपने कहा कि एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस के लिए केस बन रहा है। 19 साल से केस नहीं बना। कब तक यह केस बन जायेगा?

तीसरा, पाइप्स अवेलेबल हैं क्या आप पाइप लेइंग का टेंडर/काम शुरू करवायेंगे?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, डलहौजी की जो सीवरेज स्कीम है इसकी 1996 में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हुई। जब एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हुई तो उसके बाद डलहौजी को पांच जोन में डिवाइड किया गया और पांच सीवरेज प्लांट प्रॅपोज़ थे। लेकिन 2010 में दोबारा से इसका रिसर्वे हुआ और उसमें एक सीवरेज प्लांट ही भरेड़ा में प्रॅपोज़ किया गया। उसके उपरांत दोबारा से डी0पी0आर0 आई0पी0एच0 विभाग ने तैयार की। जहां

तक इसकी फॉरैस्ट क्लीयरैंस का सवाल है 10 नवम्बर, 2014 को जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (आई0पी0एच0) डलहौजी के हैं उन्होंने सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट का फॉरैस्ट क्लीयरैंस का केस भेजा है। लेकिन क्योंकि अभी एफ0आर0ए0 की जिला स्तरीय कमेटी नहीं बनी है इसलिए अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। जहां तक फंडस का सवाल है तो अभी वर्तमान में 5 करोड़ 52 लाख रुपया इस स्कीम के अन्तर्गत खर्च होने को पड़ा है। 16 किलोमीटर की पाइप लाइन आई0पी0एच0 विभाग ने परचेज़ की थी। लेकिन जो सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट है उसका काम शुरू नहीं हुआ। बहुत बार सीवरेज स्कीम में यह देखा गया है कि सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट पहले बना देते हैं और जब पाइप लाइन ले करना शुरू कर देते हैं तब तक सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती कि वह उपयोग में नहीं लाया गया। कई जगह ऐसा हुआ है। जहां तक पाइप लाइन को ले करने का सवाल है, इसका टेंडर हो चुका है लेकिन जब तक फॉरैस्ट क्लीयरैंस नहीं आ जाती अगर हम पाइप लाइन ले करना शुरू कर देंगे जोकि 47 किलोमीटर की है

30.03.2015/1455/SS-AG/2

और फॉरैस्ट क्लीयरैंस में देरी हुई तो मैं समझता हूं कि उससे सीवरेज की पूरी-की-पूरी स्कीम को नुकसान हो सकता है। जहां तक आपने 2015-16 की फंडिंग की बात की है अभी 5 करोड़ 52 लाख रुपया वहां पर पड़ा हुआ है लेकिन मैं माननीय सदस्या को एश्योर करना चाहूंगा कि जो भी धनराशि इसके ऊपर खर्च होनी है वह प्रायोरिटी बेस पर जैसे काम शुरू होगा तो सैंक्शन कर दी जायेगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा कि एफ0सी0ए0 की क्लीयरैंस के लिए केस भेजा है और एफ0आर0सी0 नहीं बनी हैं। पहली बात तो मैं इनसे यह जानना चाहूंगी कि एफ0आर0ए0 के तहत अर्बन एरियाज़ में एफ0आर0सीज़0 बनाने की क्या प्रक्रिया है? क्या कोई प्रक्रिया अर्बन एरियाज़ के लिए दी गई है? जो रूरल एरियाज़ हैं वहां तो पंचायतों में कॉरम फिक्स कर दिया गया है। अर्बन एरियाज़ में एफ0आर0ए0 के तहत एफ0आर0सीज़0 जो बननी हैं उनका क्या क्राइटेरिया है? क्या आप इस बारे हाउस को भी बतायेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता भी जानना चाहेगी? मेरा अलग से भी प्रश्न लगा हुआ है। फॉरैस्ट राइट्स ऐक्ट के तहत एफ0आर0सीज़0 जो बननी थीं वह अर्बन एरिया में एप्लीकेबल है या नहीं? अगर एप्लीकेबल है तो वहां कमेटी का आकार क्या होगा?

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न सीवरेज स्कीम डलहौजी के बारे में है। जो यह एफ0आर0सीज़0 का गठन होना है इनके बारे में अलग से प्रश्न पूछें तो उसकी मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा।

प्रश्नकाल समाप्त

30.03.2015/1455/SS-AG/3

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः अब मेरे पास माननीय प्रतिपक्ष के नेता, श्री धूमल जी की एक व्यवस्था आई है कि वे आई0सी0टी0 प्रोजैक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आई0सी0टी0 पर प्रश्न 31 मार्च को श्री गोविन्द राम शर्मा द्वारा लगाया गया है। अगर आप इस पर उसी समय बोलें तो अच्छा रहेगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, यह अलग इश्यु है।

अध्यक्षः यही प्रश्न है जो कल भी लगा हुआ है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी श्रीमती के0एस0

/1500/30.03.2015केएस/एजी/1

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, आई.सी.टी. का एक प्रोजैक्ट 170 करोड़ का इन्फोंमेशन एण्ड कम्युनिकेशन टैक्नोलॉजी के लिए भारत सरकार से स्वीकृत हुआ है। लगभग 1500 स्कूलों में 850हाई स्कूल और 600 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी की एक लैब स्थापित होनी है और कल इस फाईनैंशियल ईयर का अंतिम दिन है। यह 2014-15 के लिए 170 करोड़ का प्रोजैक्ट है और 75:25 की रेशो में है। अगर कल तक इसका एग्रीमैंट साइन नहीं होता तो इसका एग्ज़ीक्यूशन नहीं होगा ,वह लैप्स हो सकता है, समाचार पत्रों में भी ऐसे समाचार आए थे। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि जो ऑर्गुमैंट किया जा रहा है, वह है कि 14वें वित्तायोग ने फंडिंग का पैटरन बदल दिया है । लेकिन 14वां वित्तायोग तो अगले साल से शुरू होगा,

अगले फाईनैंशियल ईयर से और यह तो करंट फाईनैंशियल ईयर के लिए है। यह प्रोजैक्ट जिन टर्म्ज़ एण्ड कंडिशन पर आया है उसी पर लागू होगा तो क्या सरकार तुरन्त यह कदम उठाएगी कि इस प्रोजैक्ट में जो बच्चों को लाभ मिलने वाला है, जो लगभग 615 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में मिल चुका है 850 हाई और 600 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में भी यह लाभ मिले, क्या सरकार इसके लिए तुरन्त कदम उठा कर, इसके लिए जो कार्रवाई करनी है, करके इसी साल से इसको करेगी ताकि उसी दर से वह सुविधा अगले 1500 स्कूलों में भी मिल सके, मैं यह पूछना चाहता हूं।

अध्यक्षः क्या माननीय आई.टी. मिनिस्टर इसको क्लैरिफाई करेंगी?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित है ।

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न है इसका जवाब मुख्य मंत्री जी को देना होगा कि क्या इस प्रोजैक्ट को साईन करके इसको लागू करवाएंगें?

/1500/30.03.2015केएस/एजी/2

Speaker: In the meantime, we will go ahead with the report of the Committees of the House.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय धूमल जी द्वारा आई.सी.टी. के बारे में उठाये गये प्रश्न के उत्तर में यह कहना चाहूंगा कि the Government of India has given first instalment of ICT Project. Further funding is likely to be revised. We will sort out the matter before close of the financial year.

/1500/30.03.2015केएस/एजी/3

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री इस मान्य सदन को इस सप्ताह की कार्य सूची से अवगत करवायेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मान्य सदन को इस सप्ताह की कार्य सूची से अवगत करवाता हूं जो कि निम्न प्रकार से हैः-

सोमवार, 30मार्च, 2015 (1) शासकीय / विधायी कार्य।
(2) बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2015-16 -मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

मंगलवार, 31 मार्च, 2015 (1) शासकीय / विधायी कार्य।
(2) बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2015-16
(i) मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
(i) विनियोग विधेयक- पुरःस्थापना, विचार विमर्श एवं पारण।

बुधवार, 1अप्रैल, 2015 **शासकीय / विधायी कार्य।**

वीरवार, 2अप्रैल, 2015 **शासकीय / विधायी कार्य।**
/1500/30.03.2015केएस/एजी/4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री जय राम ठाकुर, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15) ,समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगें।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2014-15) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का **98वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 74वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **99वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 75वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से** सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **100वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 76वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है; और

30.03.2015/1500/केएस/एजी/5

(iv) समिति का **101वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 268वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेगी।

श्रीमती आशा कुमारी :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्र समिति, (वर्ष 2014-15)का 37वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं ।

/1500/30.03.2015केएस/एजी/6

अध्यक्षः अब श्री खूब राम, सदस्य, अधीनस्थ विधायन समिति (वर्ष 2014-15), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

श्री खूब रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधायन समिति (वर्ष 2014-15), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का **पंचम मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि बारहवीं विधान सभा के पंचम, षष्टम् एवं सप्तम् सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **षष्टम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि बारहवीं विधान सभा के पंचम, षष्टम् एवं सप्तम् सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है ।

/1500/30.03.2015केएस/एजी/7

अध्यक्षः अब श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15) समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगें।

श्री कर्ण सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15), का 13वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन

अध्यक्ष : अब माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री प्रस्ताव करेंगी कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11(1)बी(7) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11(1)बी(7) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11(1)बी(7) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

तो प्रश्न यह है कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री प्रस्ताव करेंगी कि "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम 1986 की धारा 11(1)बी(7) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0

30.3.2015/1505/ag/av/2

एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

(प्रस्ताव स्वीकार)

विधायी कार्य श्री बी.जे.द्वारा जारी

30.03.2015/1510/negi/ag/1

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब विधायी कार्य होंगे। अब सरकारी विधायकों की पुरःस्थापना होगी। अब माननीय मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2015, (2015का विधेयक संख्यांक-5)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें, (संशोधन) विधेयक, 2015, (2015का विधेयक संख्यांक-5)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2015, (2015का विधेयक संख्यांक-5)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2015, (2015का विधेयक संख्यांक-5)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री "हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें संशोधन विधेयक, 2015, (2015का विधेयक संख्यांक-5)" को पुरःस्थापित करेंगे।

30.03.2015/1510/negi/ag/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2015, (2015का विधेयक संख्यांक-5)" को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः "हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2015, (2015का विधेयक संख्यांक-5)" को पुरःस्थापित हुआ। अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 6)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

आबकारी एवं कराधान मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 201 5 (201 5का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दी जाए।
अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 6)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 6)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी

जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री "हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 6)" को पुरःस्थापित करेंगे।

30.03.2015/1510/negi/ag/3

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5का विधेयक संख्यांक 6)" को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः "हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 201 5(201 5 का विधेयक संख्यांक 6)" को पुरःस्थापित हुआ।

<u>अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना</u>

इससे पहले कि हम 2015-16 के बजट के अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान कर सकें, मैं एक सूचना माननीय सदन में देना चाहता हूं जो इस प्रकार है; आज सुबह ही ई- विधान मोबाईल ऐप्स लॉन्च किया है माननीय मुख्य मंत्री जी ने और उसके लिए आप सबको बधाई हो। बहुत सारे सदस्य नही भी थे इसके लिए मैं आपको कुछ इस सदन में इसके बारे में सूचना देना चाहता हूं।

ई-विधान प्रणाली में माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु कुछ उपयोगी फिचरज जोड़े गये हैं, जिसकी जानकारी मैं माननीय सदन को देना चाहता हूं।

पिछले दिनों बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा ई-विधान प्रणाली की सुविधा का पूर्ण लाभ उठाने हेतु Wi-Fi Internet ,विधान सभा परिसर व उनके निवास स्थान पर उपलब्ध करवाने की मांग की गई थी । माननीय सदस्यों की मांग व

आवश्यकता को मध्यनज़र रखते हुए सभी माननीय सदस्यों को Wi-Fi Internet डोंगल उपलब्ध करवा दिए जा रहे हैं। जिससे सभी माननीय सदस्य ई-विधान प्रणाली का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। इससे माननीय सदस्य न केवल विधान सभा परिसर में बल्कि इसका प्रयोग अपने निर्वाचन क्षेत्र व राज्य से बाहर प्रयास पर रहते हुए भी कर सकेंगे।

30.03.2015/1510/negi/ag/4

मुझे आप सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज विधान सभा में ई-विधान मोबाइल ऐप्स भाग-I का शुभारंभ किया गया है। यह एक नवीनतम तकनीक से लैस एंडरॉयड आधारित मोबाईल व टेबलैट पर ....

श्रीमती यू.के. द्वारा जारी...

30/1515/2015/03/यूके/एजी/1

अध्यक्ष---जारी ---

एवं टेबलेट पर यह सुविधा माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, माननीय मुख्य संसदीय सचिवों, व माननीय विधायकों के लिए उपलब्ध रहेगी । विधान सभा सत्र के दौरान सदस्यों को सदन में होने जा रही कार्यवाही की जानकारी सत्र आरम्भ होने से पहले उपलब्ध रहेगी । तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों व उनके उत्तर सभी सदस्यगण अपने मोबाईल पर सत्र शुरु होने से 45 मिनट पहले देख सकेंगे । मोबाईल पर सभी सदस्य कार्यसूची व सम्बन्धित कागजात भी देख सकेंगे । सदन की कार्यवाही Uncorrected & Unedited भी मोबाईल पर निर्धारित समय में उपलब्ध करवाई जायेगी । माननीय सदस्यगण बिलों को जो सदन में पुरःस्थापित/पारित/स्वीकृत किए जाते हैं, विभाग द्वारा विधान को प्रेषित करने उपरान्त अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के बाद अपने मोबाईल पर देख सकेंगे । समितियों के प्रतिवेदनों को भी मोबाईल पर देखा जा सकेगा ।

माननीय मन्त्री अपने मोबाईल व टैबलेट पर अनुपुरक उत्तर भी अपने सम्बन्धित विभागों से ले सकेंगे और अपने प्रशासनिक सचिव को भी सम्मिलित कर सकेंगे। विधान सभा सत्र के दौरान मीडिया, सदन में होने जा रही कार्यवाही की जानकारी आरम्भ होते ही देख सकेंगे।

इसके अतिरिक्त विधान सभा द्वारा जारी की गयी अधिसूचना, समाचार, बुलेटिन, बजट भाषण/दस्तावेज माननीय सदस्यों को दी जा रही सुविधाएं जो कि प्रतिमाह वेतन स्लिप तथा प्रतिपूर्ति बिलों की स्थिति व अन्य सुविधाएं भी मोबाईल पर उपलब्ध रहेगा। अधिकारियों से सर्म्पक हेतु अनेक मोबाईल नम्बर, पद व नाम सहित मोबाईल पर उपलब्ध रहेंगे। माननीय विधायकगण अपने निर्वाचन क्षेत्र के विशिष्ट अधिकारियों व पदाधिकारियों से इस सुविधा के तहत मोबाईल द्वारा जुड़े रहेंगे।

इसके अतिरिक्त ई-विधान मोबाईल ऐप्स भाग-2 का कार्य भी प्रगति पर है तथा इसे भी शीघ्र माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु लाँच कर दिया जाए। इसका शुभारम्भ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर होगा। जिसके द्वारा माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को मोबाईल के जरिये जान सकेंगे। उसका

30/1515/2015/03/यूके/एजी/2

निपटारा करवा पाएंगे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक कार्यों की समीक्षा भी मोबाईल ऐप्स द्वारा अधिकारियों के साथ संवाद कर पूरी की जायेगी। निर्वाचन क्षेत्र के समस्त अधिकारियों तथा महत्वपूर्ण कार्यालय से सीधा सम्पर्क स्थापित होगा। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत पत्रो की स्थिति भी मोबाईल् पर उपलग्ध रहेगी। इस सुविधा के फलस्वरूप कागजों के इस्तेमाल में भारी कटौती होगी तथा विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता व अधिकारियों से सीधा संवाद कर सकेंगे। इससे माननीय सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र को सुचारू रूप से मैनेज करने की सुविधा होगी।

यह कार्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा, हिमाचल प्रदेश रकार, NIC, NICSI, और SBL के संयुक्त प्रयत्नों से सम्पूर्ण हुआ है। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप Wi-Fi Internet डोंगल, मोबाईल ऐप्स एवं इसका उपयोग करने की जानकारी ई-विधान ट्रेनिंग रूम से ले सकते हैं।

30/1515/2015/03/यूके/एजी/3

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

अब वर्ष 2015-2016 के बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा पर एवं मतदान होगा ।

अब वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों, मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। अब मैं मांग संख्या संख्या-10 को चर्चा एवं मतदान हेतु लेता हूं ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च , 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-10, लोक निर्माण विभाग, पुल एवं भवन के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त मु0 24,46,71,39,000 रुपए (राजस्व) एवं मु0 8,90,26,30,000 रुपए (पूंजी) की धन राशि सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

30.03.2015/1520/sls-ag-1

अध्यक्ष :...जारी

इस पर सर्वश्री ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, सुरेश भारद्वाज और बिक्रम सिंह की ओर से 2 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे या में इन्हें प्रस्तुत हुआ समझूं?

माननीय सदस्यगणः अध्यक्ष महोदय, हमारे कटौती प्रस्तावों को हमारी ओर से प्रस्तुत हुआ समझा जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों सर्वश्री ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, सुरेश भारद्वाज और बिक्रम सिंह की ओर दिए गए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

30.03.2015/1520/sls-ag-2

अध्यक्ष : मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध हैं।

अब श्री ईश्वर दास धीमान कटौती प्रस्ताव पर अपने विचार रखेंगे।

कृपया मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक सदस्य समय का थोड़ा-सा ध्यान रखे; समय सीमा के भीतर बोलें। कटौती प्रस्ताव पर आप अपनी बात पांच मिनट में रख सकते हैं क्योंकि बजट पर बोलते समय आपने इस सभी बातों पर बोला है। जो कमियां हैं और जो आप चाहते हैं, वह आप पहले ही बोल चुके हैं। आज यह सही नहीं होगा कि आप दोबारा से कटौती प्रस्ताव के ज़रिये कमियां दर्शाने लगें। आपने कमियों को देखते हुए ही कटौती प्रस्ताव दिए हैं। इसलिए इसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके आप संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, बजट में कुल 32 डिमांड्ज हैं जिनमें से हमने केवल 5 डिमांड्ज पर कटौती प्रस्ताव दिए हैं। इन 5 डिमांड्ज पर तो सदस्य अपनी बात रखेंगी ही न? हम सारे बजट पर तो कटौती प्रस्ताव डिसकस नहीं कर रहे हैं। हमने 5 मांगों पर अपनी प्रॉयरिटी आपको दी है। इसलिए सदस्यों को बोलने के लिए ठीक समय दिया जाए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष : ऐसा है, कटौती प्रस्ताव आज कोई पी.डब्ल्यू.डी. का ही नहीं है बल्कि और कटौती प्रस्ताव भी हैं। अगर हमने सब पर चर्चा करनी है तो, आखिरकार, समय की सीमा तो होनी ही चाहिए। अगर आप समय की सीमा निर्धारित नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अन्यथा जैसे आप कहते हैं, मैं करने को तैयार हूं। लेकिन आप ऐसा मत सोचिये कि जितना मरज़ी बोलते रहें। इसके लिए समय सीमा तो निर्धारित होनी ही चाहिए। आज केवल एक ही कटौती प्रस्ताव नहीं है, बल्कि और भी हैं। और मांगों पर भी कटौती प्रस्ताव हैं जिन पर आप लोगों ने बोलना है। आप स्वयं डिसाईड कर लीजिए कि कितना-कितना समय बोलेंगे, पांच मिनट लेंगे या दस मिनट लेंगे? लेकिन इसमें ज्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है।

30.03.2015/1520/sls-ag-3

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कट मोशन्ज जिन सदस्यों ने दिए हैं उन्होंने ही इन पर अपनी बात रखनी है। बजट चर्चा में आपको अधिकार है कि आप जब खत्म करना चाहेंगे तो गिलोटिन लग जाएगा। फिर हम चाहे बोलना चाहें या न बोलना चाहें, वह अपने आप बंद हो जाएगा। जिन-जिन विभागों की प्रॉयरिटी है, हमने 32मांगों में से उनपर 5के लिए कटौती प्रस्ताव दिए हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा भी बोला जा सकता है क्योंकि ज्यादा सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव नहीं दिए हैं। उसी में सभी के विचार आ जाते हैं। अगर इसमें आप लिबरल रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष : आप मेरा भावार्थ नहीं समझे। मैं लिबरल हूं। लेकिन अगर कोई आधे घंटे के बजाये 45 मिनट या एक घंटा लेता है तो उसे मैं अलाऊ नहीं करूंगा। कोई समय सीमा तो होनी ही चाहिए। कोई बहुत ज्यादा बोलने से बात का प्रभाव ज्यादा नहीं होता। कटौती प्रस्ताव का मतलब यही है कि आपने जो कमी दर्शाई है उसके लिए ही आपने कटौती प्रस्ताव दिया है। बजट पर आप पहले ही बोल चुके हैं। ...(व्यवधान)...

अब श्री ईश्वर दास धीमान जी अपनी बात रखेंगे।

श्री ईश्वर दास धीमान : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश के अनुसार थोड़ा-सा स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं। कटमोशन विपक्ष की तरफ से हैं। कोई ज्यादा समय लेता है तो कोई कम लेता है, यह विपक्ष के विधायकों पर निर्भर है। हम कम समय लेंगे तो ज्यादा मांगे डिसकम होंगी और ज्यादा समय लेंगे तो कम मांगें डिसकस होंगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी ज्यादा-से-ज्यादा मांगों पर चर्चा हो। हम स्वयं ही कम समय में अपनी बात रखना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई विधायक अपनी जानकारी देना चाहता है या आपकी सूचना में लाना चाहता है तो उस मामले में कृपया नरमी बरतें।

जारी...गर्ग जी

30/03/2015/1525/RG/AG/1

श्री ईश्वर दास धीमान-------क्रमागत

अध्यक्ष महोदय, मैं लोक निर्माण विभाग के 'सड़क, पुल एवं भवन', मांग संख्या-10 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा भोगौलिक पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी अपनी भोगौलिक परिस्थितियां अलग हैं। यहां हवाई जहाज या हैलीकॉप्टर से यात्रा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां

बहुत कम हैं और वैसे भी एक आम-आदमी के लिए हवा में सफर करना बहुत महंगा पड़ता है। इस कारण से यात्रा का यह साधन हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं होता। अब रेलवे की बात रही, तो वह भी बहुत देर से ज्यो-की-त्यों है। चलो, इस बार हिमाचल प्रदेश खुशकिस्मत निकला कि केन्द्र की तरफ से पहली बार हिमाचल प्रदेश को लगभग 360 करोड़ रुपये की रेलवे लाईन के लिए मदद मिली है। लेकिन इसमें समय लगेगा। कुछ रेलवे में भी हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना कि आजादी के बाद से होना चाहिए था। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता रेलवे लाईन का लाभ भी बहुत ज्यादा नहीं उठा सकती। अब सड़कों की बात रही, तो प्रदेश में सड़क ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमारा आना-जाना होता है, हमारा सामान इधर-से-उधर आता-जाता है और यदि मैं यह कहूं कि हम यहां निर्भर ही इन्हीं सड़कों पर हैं ,तो गलत नहीं है। इसलिए प्रदेश में सड़कों की आवश्यकता को सोचा और समझा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता भी सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा रही है और हमने बहुत हद तक इनको पूरा भी किया है। इस समय तक हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाइवेज़ 1,784 किलोमीटर, स्टेट हाइवेज़ 1,466 किलोमीटर ,मेज़र डिस्ट्रिक्ट रोड्ज 2,145 किलोमीटर और बाकी 621 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इस प्रकार यहां सड़कों की कुल लंबाई 33,736 किलोमीटर बनती है। लेकिन यह भी नाकाफी है। जिस वर्ष की हम बात कर रहे हैं मैं समझता हूं कि अभी तक तो अढ़ाई वर्षों में सड़कों के निर्माण में बहुत कम काम हुआ है। सड़कों की हालत बारिश के कारण, प्रतिकूल मौसम के कारण बहुत खराब है। आगे पक्की सड़कों का निर्माण भी नहीं हो सका, सड़कें पक्की भी नहीं हो सकीं और बरसात में जो सड़कों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई भी नहीं हो सकी। आज किसी भी क्षेत्र या जिले में सड़कों की हालत गड्ढों से बहुत खराब हो गई है। हां, कुछ नेशनल हाइवेज़ मेन्टेन हुए हैं ,कुछ ऐक्सप्रैस हाइवेज हैं जहां कमी रहती है, लेकिन अब कुछ नेशनल हाइवेज़ का सुधार होने लगा है ,उनकी शक्ल बदलने लगी है।

30/03/2015/1525/RG/AG/2

लेकिन हमारी अपने प्रदेश की सड़को की हालत बहुत ही खराब है। कई बार यह सरकार के ध्यान में भी लाया गया है---------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

श्री ईश्वर दास धीमान जारी-----
बहुत बार यह ध्यान में लाया भी गया है लेकिन हमें ज्यादातर सड़कें अगर नाबार्ड से न मिलती तो शायद स्थिति और होती। मुख्य मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि सन् 1947में हमारी केवल 288 किलोमीटर सड़कें थी जोकि आज 33 737,किलोमीटर हो गई हैं। हमने इसमें उन्नति की हैं और हम बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन उनकी मैंटीनैंस और बाकी भी सड़कों की जो जरूरतें हैं, जैसे नालियां बनानी या जो तारें/केबल बिछा रहे हैं, उसमें हम बहुत पीछे हैं। उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नाबार्ड से हमने 2000 करोड़ रूपये का ऋण लेकर 2381 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से भी सड़कें बनाई हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि इस बात का जिक्र बजट में नहीं आया, जबकि आना चाहिए था।

पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया गया ,जो छः साल तक इस देश के प्रधान मंत्री रहे। सन् 1998 तक इस बात का क्या किसी को भी ख्याल नहीं आया कि देश का हर कोना सड़क से जुड़ना चाहिए? यह पहले प्रधान मंत्री थे जिन्होंने ऐसा किया। कनैक्टिविटी और कम्युनिकेशन उनकी प्रायोरिटी रही और 60,000 करोड़ रूपये का प्रबंध करके उन्होंने देश के हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात की। लेकिन बजट में उसका वर्णन नहीं आया। यह आना चाहिए था क्योंकि बहुत कुछ जो हुआ है ,वह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू होने के बाद ही हिमाचल प्रदेश में हुआ है और हिमाचल प्रदेश में सड़कों का घनत्व बढ़ा है, उसको गति मिली है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं हुए हैं। हर सरकार ने काम किए हैं लेकिन जो काम इस योजना के बाद शुरू हुए ,वह शायद पहले नहीं हो सके और उन्होंने इसके लिए उस वक्त मदद की है। माननीय धूमल जी की सरकार के समय वर्ष 1998 से यह काम शुरू हुआ कि 1000 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए। उस वक्त के मुख्य मंत्री का यह प्रयत्न रहा कि 500 और 250 की आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ा जाए। क्या कारण है कि काम में गुणवत्ता और तेजी नहीं आ रही है?

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय सब जगह लोक निर्माण विभाग के सब-डिवीजन्ज काम कर रहे हैं और सब-डिवीजन में अगर एस0डी0ओ0 ही न हो तो

30/03/2015/1530/MS/AG/2

क्या काम होगा? मुझे लगता है कि 25 के करीब इस समय ऐसे सब-डिवीजन्ज हैं जिनमें एस0डी0ओ0 नहीं हैं। अगले कल 31 मार्च को 60 ऐसे सब-डिवीजन्ज हो जाएंगे जहां एस0डी0ओ0 ही नहीं होंगे। क्या इसका पहले प्रबंध कर लिया है? जहां सब-डिवीजन में एस0डी0ओ0 नहीं होगा, वहां सब-डिवीजन में काम नहीं होगा। क्योंकि सब-डिवीजन में एस0डी0ओ0 एक जिम्मेवार आदमी होता है। इसलिए जो यह स्टाफ की कमी है, इसको दूर कीजिए।

इसी तरह से अगर जे0ई0 की बात की जाए तो इस समय लगभग 100 जे0ई0 के पद खाली पड़े हैं। कौन ऐसे में काम करेगा और आने वाले 31 मार्च को 200 से ज्यादा पद जे0ई0 के खाली हो जाएंगे। जो सेवा विस्तार पाकर एस0डी0ओ0 काम कर रहे हैं, वे भी अब सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

30.03.2015/1535/जेके/एजी/1

श्री ईश्वर दास धीमानः----**जारी**-----
अगर ये लोग अपनी जगह पर नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि सब डिविजन और डिविजन का कोई विकास नहीं हो सकता है। मैं अपने ही डिविज़न की बात करता हूं। बड़सर डिविजन के बारे में मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वहां पर 7वें एक्सियन ने ज्वाईन किया है। हम टैलिफोन करते हैं और वे कहते हैं कि वे पिछले साल चले गए हैं, मैं तो अभी नया-नया आया हूं। कारण का मुझे पता नहीं है। कोई भी एक्सियन वहां पर 3-4 महीने से ज्यादा का समय नहीं काट सका। अब आप बताईए जिस डिविजन में दो वर्ष में 7वाँ एक्सियन आ जाता है तो उसमें क्या काम हुआ होगा? काम की क्या निरन्तरता होगी? जब दो-तीन महीने में एक्सियन काम को समझता है तब तक दूसरा आ जाता है। मैं यहां पर अपने चुनाव क्षेत्र की सड़कों के बारे में संक्षेप में बोलता हूं। मेरे क्षेत्र में जो थोड़ी सी लम्बाई नेशनल हाई वे में 10 किलो मीटर के करीब आती है और जो एक्सप्रैस हाई वे है उसमें तीन सड़कों के बारे में समझता हूं कि ओखली से अवाहदेवी, चन्दरोई और हमीरपुर से जाहू ,ये सड़कें अभी तक शायक डिस्ट्रिक्ट रोड़ में ही शामिल हैं। ये तीनों सड़कें बहुत पुरानी है। ये उन क्षेत्रों की लाईफ लाइन हैं। मैं अन्दर की सड़कों की यहां पर बात नहीं करता हूं। यदि इन सड़कों की

हालत ठीक हो जाए, इनकी अपग्रेडेशन ठीक हो जाए और इनमें जो मोड़ आदि हैं वे सीधे हो जाए इससे मैं समझता हूं कि इन सड़कों की प्रॉपर सुविधा वहां के लोगों को मिल पाएगी। कुछेक सड़कें तो एक बार मैटल हुई थी उसके बाद चाहे 15 वर्ष हो गए, चाहे 10 वर्ष हो गए और चाहे 6 वर्ष हो गए, जहां पर रीमैटलिंग होती रही वे सड़कें तो ठीक हैं। मुझे याद है वर्ष 2008 में कुछेक सड़कों की रीमैटलिंग हुई थी। वे सड़कें आज भी ठीक हालत में है। वे सड़कें दूसरी सड़कों से बेहतर है। अगर आप 6 सालों के बीच में प्रमुख सड़कों की रीमैटलिंग नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि वह कहां तक चलेगी? बहुत बुरी हालत है जो सफर हम 3 घण्टे में करते थे वह अब 4 घण्टे में होता है। जो सफर हम आधे घण्टे में करते थे उसमें अब घण्टा या डेढ़ घण्टा लग जाता है। इस तरह से गाड़ियों की हालत भी खराब होती है, दूसरी ओर समय भी ज्यादा लगता है और लोगों को

30.03.2015/1535/जेके/एजी/2

असुविधा भी होती है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि विभाग इस ओर ध्यान दें। यहां पर जैसे कि मैंने कहा कि रिक्तियों का होना, जो प्रभावी आसामियां हैं वे पोस्टें रहनी चाहिए। एक्सियन हर हालत में डिविजन में होना चाहिए। यदि वह वहां पर कम से कम एक वर्ष तक रहेगा तो वह प्रोग्रैस भी देगा यदि 4-5 महीने में ही बदल देंगे तो वह क्या प्रोगैस देगा? इसी तरह से एस.डी.ओ. की बात है और अगर यह 4 महीने तक ज्वाईन ही नहीं करेगा तो फिर उस सब डिविजन को कौन देखेगा? जहां तक फंडज़ की बात है और हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम टेलिफोन एस.डी.ओ, एक्सियन या एस.सी. को करेंगे, हर किसी अधिकारी से यही ज़वाब आता है कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है। यह पैसा पिछले साल के बजट का है वह कहां चला गया? जो पैसा मुरम्मत के लिए, मेंटिनैंस के लिए था वह पैसा कहां चला गया?

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

30.03.2015/1540/SS-AG/1

श्री ईश्वर दास धीमान क्रमागतः

वह पैसा कहां चला गया? वह पैसा कहां लगा और कहां नहीं लगा? क्या वह सड़कों की लम्बाई के मुताबिक दिया जाता है या केवल सब-डिवीजन या डिवीजन के आधार पर दिया जाता है? किस आधार पर दिया जाता है? यही आवाज़ अधिकारियों से आती है

कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हमें कहते-कहते साल हो गया लेकिन जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं उस पर भी 100 या 200 रुपये का काम नहीं होता। यह बड़े अफसोस की बात है। यह देखने वाली बात है। बजट का प्रबंध, पैसे का नीचे उतरना, कहां दिक्कत है, कहां दिक्कत नहीं है यह तो विभाग जाने। लेकिन हमारे कान में तो यही बात आती है कि पैसा नहीं है।

अब बेलदार आपके रिटायर हो रहे हैं। जो पक्के हो रहे हैं वे पक्के हो रहे हैं लेकिन उनकी जगह पर आपके पास दूसरे बेलदार नहीं हैं। अपनी तो फोर्स ही नहीं रह गई। आपका तो सारा काम आउटसोर्सिंग से हो रहा है। उसमें मैं नहीं कहता कि कोई सरकार दोषी है। वह ठेकेदार से करवाना ही पड़ेगा। लेकिन जहां ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतनी तो लेबर हर सब-डिवीजन में होनी चाहिए। इमरजैंसी के लिए होनी चाहिए। देखभाल के लिए होनी चाहिए। कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कोई भी बात घट जाती है। बेलदार भी जितने पक्के हो रहे हैं उनका काम कच्चा हो रहा है। जो कच्चे हैं वे पक्का काम करते हैं । लेकिन जब पक्के हो जाते हैं तब कच्चा काम करते हैं। वह भी नुकसानदेह है। लेकिन उनको फायदा पहुंचता है, उनको काम करना चाहिए। लेकिन वे करते नहीं। इस तरफ भी अगर विभाग ध्यान देगा कि बेलदारों की पोस्टें भी कम-से-कम फिक्स कर दी जाएं कि सब-डिवीजन के ऊपर इतनी होनी ही चाहिएं। उससे अगर ज्यादा हैं तो ठीक है। अगर कम होती हैं तो बढ़नी चाहिएं। इनसे देख-रेख में बड़ी मदद मिलती है।

मैं बहुत लम्बी बात न करते हुए एस0सी0 सब-प्लान के बारे में कहना चाहता हूं। एस0सी0 सब-प्लान में पीछे से सड़कें बनती आ रही हैं और पैसा भी दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद सरकार ने बंद कर दिया है। अब तो टोकन के हिसाब से कोई पैसा नहीं है। अब इससे ही तो हरिजन या दूसरे कमज़ोर तबके के सड़क से जुड़ने की बात होती थी। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाए कि क्या कारण है कि एस0सी0 सब-प्लान में पैसा कहां चला गया? जितनी भी हरिजन बस्तियां इस प्लान से जुड़नी हैं वे तो जुड़नी बंद हो गईं। उन सड़कों की हालत भी खराब हो गई,

30.03.2015/1540/SS-AG/2

उनको पक्का तो क्या होना है जो पहले बनी थीं। जिसके लिए पैसा था वह भी पैसा नहीं है। इस प्लान में नई सड़कें नहीं ली गईं और पुरानी जितनी ली गईं उन पर भी काम नहीं हो रहा। यह बड़ी गहराई से देखने वाली बात है कि इसके पीछे क्या कारण है।

मैं जाहू के पुल की बात करूंगा। जाहू का पुल बरसात में गिर गया। जाहू तीन जिलों का संगम है। वहां पर वैली ब्रिज लगा था। वह 4 साल पहले लगा था। उसके बाद आपकी डेढ़ साल सरकार रही, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। उसकी नींव कमजोर हो चुकी थी, वह तो इमरजैंसी में 6 महीने या साल के लिए लगाया गया था। उसको तो ठीक होना था लेकिन वह बरसात में गिर गया।

हम सीर खड्ड की चैनेलाइजेशन की बात करते रहे। मैं और कर्नल इंद्र सिंह जी भी सीर खड्ड के चैनेलाइजेशन की बात करते रहे। उसके लिए पैसा भी स्वीकृत हुआ लेकिन काम नहीं हुआ। अगर वह काम हो जाता तो लोगों की हज़ारों एकड़ की भूमि बच जाती और वे तीन जानें भी बच जातीं जोकि उस पुल के गिर जाने से तीन मौतें हुईं। वे भी बच जाते लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ..

जारी श्रीमती के0एस0

/1545/30.03.2015केएस/एजी/1

श्री ईश्वर दास धीमान जारी---
लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ और अब भी मैंने अपनी प्रायोरिटी को छोड़ कर जाहू पुल के लिए प्रायोरिटी दी है। मैं विभाग से यह अनुरोध करता हूं तथा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह बड़ा कॉम्युनिकेटिड एरिया है और तीन जिलों का है उस पुल का होना वहां बहुत जरूरी है। अगर आई.पी.एच. विभाग, जो पैसा स्वीकृत है उसको लगाने की कोशिश करें तो बाढ़ का नियंत्रण भी हो जाएगा।

आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय, आपने अक्तूबर अंत में मिनी सचिवालय का उद्घाटन कर दिया और यह नहीं देखा कि इसमें क्या खामियां है। ठीक है आपने उद्घाटन कर दिया लेकिन जो उस समय खामियां थी, वे आज भी है । उस वक्त तो न बिजली थी न पानी था, न फर्श पक्के थे, न गेट था, कुछ नहीं था।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, इतनी गम्भीर चर्चा इस डिमांड पर चली है और सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है। यहां पर कोरम ही पूरा नहीं है और वे बाहर गैलरी में बैठे हैं तो मेरा निवेदन है कि सदन के नेता को यह आदेश दिया जाए कि कम से कम कोरम् पूरा हो।

अध्यक्षः कोरम् तो पूरा ही लग रहा है।

श्री ईश्वर दास धीमानः अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि वहां पर जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करने की कृपा करें। बहुत सी कमिया वहां पर है । आप विभाग को आदेश करें कि वहां पर जो कमी रह गई है

/1545/30.03.2015केएस/एजी/2

उसको पूरा कर दें तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूंगा। वह पुल कूनाह खड्ड के ऊपर है जहां आपने पीछे उद्घाटन किया, जहां एक मज़दूर की मौत हो गई थी। वह भी जल्दी जल्दी में ही उद्घाटन कर दिया था और मुझे समझ नहीं आता कि विभाग या कुछ लोग अधूरे कामों के उद्घाटन क्यों करवाते हैं? तो वह कार्य भी अधूरा ही था। तो ये दो पुल है जिनकी तरफ मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। इसी तरह के और कार्य भी हो सकते हैं, मैं ज्यादा इस चर्चा को न खींचते हुए आपसे उम्मीद करता हूं कि जिन-जिन चीजों पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है और वास्तविकता बताने की कोशिश की है, उन पर सरकार पूरा-पूरा गौर करेगी और सड़कों की हालत को सुधारने में जितनी जल्दी हो सके कोशिश करें। अब तो मौसम लगभग ठीक ही रहेगा और मैटलिंग का मौसम भी है परन्तु जब गड्ढे मिट्टी से भरे जाते हैं और जब वर्षा होती है तो स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। इसलिए गड्ढे मिट्टी से न भरे जाएं । इससे टूरिज्म पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । कहीं-कहीं तो मेन सड़क को छोड़कर 20-20 किलोमीटर का चक्र लगाकर उस स्थान पर आना पड़ता है क्योंकि बीच का पोर्शन बहुत खराब होता है। गांव की कुछ सड़कें तो वैसे ही खत्म हो गई है । उनको विभाग देखेगा तभी उनमें कोई बेहतरी आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मांग को प्रस्तुत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस पर अमल होगा। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः क्या बाकी माननीय सदस्य भी इस पर बोलना चाहेंगें?

श्री रिखी राम कौंडलः जी, अध्यक्ष महोदय, हम इस पर बोलना चाहते हैं। जो कटौती प्रस्ताव

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

30.3.2015/1550/ag/av/1

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव मांग संख्या :10-लोक निर्माण विभाग-सड़क, पुल और भवन के बारे में माननीय श्री धीमान जी, मैंने और बाकी लोगों ने दिया है; आपने मुझे इस पर बोलने की अनुमति दी है। मैं इस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है और किसी भी प्रदेश में आवागमन के साधन या तो रेलवे के माध्यम से होते हैं या बाई एयर होते हैं। जहां पर ये दोनों ही सुविधा न हो वहां सड़कें ही आवागमन का मुख्य साधन होता है। हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी ऐसी है कि यहां रेलवे लाइन का जाल ज्यादा नहीं बिछाया जा सकता मगर फिर भी हम केंद्र सरकार के धन्यवादी है। इस बार केंद्र सरकार से 360 करोड़ रुपये रेलवे के सर्वे के लिए और 100 करोड़ रुपये ऊना से आगे लाइन बिछाने के लिए मिला है। जहां तक हवाई जहाज से आवागमन का प्रश्न है तो हम अकसर माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते रहे हैं। 'कुल्लू में जल्दी ही बाई एयर सर्विस शुरु कर दी जायेगी।' 'एयरपोर्ट शिमला (जुब्बड़हट्टी) में भी मार्च में शुरु कर देंगे।' वह अभी शुरु नहीं हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी जब इस डिमाण्ड की चर्चा पर उत्तर देंगे तो बताएं कि वह सर्विस अभी तक किन कारणों से शुरु नहीं हुई? हमारे प्रदेश में टूरिज्म की अपार सम्भावनाएं हैं। मगर हमारा पर्यटन तभी बढ़ेगा जब हमारी सड़कें ठीक होंगी। आज कोई भी पर्यटक मनाली आ रहा हो या नेशनल हाई-वे बिलासपुर से होकर स्वारघाट से गुजरता है या ऊना से होकर चिन्तपूर्णी जाता है, धर्मशाला जाता है, चामुण्डा जाता है। एक बार आने के बाद वह सोचता है कि हम दोबारा जाएं या न जाएं। हम यह मानते हैं कि यहां प्रकृति का प्रकोप ज्यादा होता है। इस बार बहुत ज्यादा बारिश के कारण सड़कें खराब हुई हैं। इसके लिए हम न तो सरकार को दोषी मान सकते हैं और न ही सरकार का सड़कें खराब होने में कोई दोष है। हम यहां 15 फरवरी के बाद सर्फेसिंग और टारिंग

का काम शुरु करते थे लेकिन इस बार अप्रैल माह शुरु होने पर भी हम वह काम शुरु नहीं कर पाये हैं। यह तो कुदरत की बात है इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब 15 फरवरी के बाद सड़कों को ठीक करने का

30.3.2015/1550/ag/av/2

टारगेट है और मौसम इजाजत दें तो उससे पहले-पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा बिचुमैन की सारी प्रोक्योरमैंट करनी चाहिए। होता क्या है, अप्रैल-मई महीने में जब सीजन खत्म होने वाला होता है तब ऑर्डर देते है। उसके बाद बिचुमैन पहुंचता है और वह टांरिग 15 दिन बाद उखड़नी शुरु हो जाती है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की दो-तीन बातों पर बाद में आऊंगा।

हिमाचल प्रदेश में जब से प्रजातांत्रिक सरकारें बनने लगी अपने-अपने कार्यकाल में हर मुख्य मंत्री ने औजस्वी / अच्छे काम किए। हर सरकार ने हिमाचल प्रदेश की भाग्य रेखा मानी जाने वाली सड़कों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। इसमें डॉ.परमार ने भी किए, माननीय शांता कुमार जी ने भी किए। माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने हर गांव को सड़क से जोड़ने का प्रयत्न किया। माननीय वीरभद्र सिंह जी छठी बार प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं। इन्होंने भी प्रदेश के हर क्षेत्र में चाहे ट्राइबल एरिया हो या हमारा निचला क्षेत्र हो; सड़कों को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किए हैं। सड़कों के जाल बिछाने के लिए हर पार्टी की सरकार ने पूरे प्रयत्न किए हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

30.03.2015/1555/negi/ag/1

श्री रिखी राम कौंडल ..जारी...

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में कुल 17449 गांव हैं जिनको सड़क से जोड़ने का सरकार का लक्ष्य है, अभी तक हम 10019गांवों को केवल सड़क से जोड पाए हैं और अभी भी 7430 गांव ऐसे हैं जिनको हमें सड़क से जोड़ना है। आज प्रदेश की कनैक्टिविटी 57.42 परसेन्ट है। सारे गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए हमें धन की आवश्यकता है। धन हम कहां से मुहैया करवाएंगे? प्रदेश में हम रिसोर्सिज कैसे

मोबिलाइज़ करेंगे ? किसी प्रदेश में डिवलपमैन्ट के लिए रिसोर्सिज मोबिलाइज करना अति आवश्यक है। हर बार माननीय मुख्य मंत्री, वीरभद्र सिंह जी जब आते है तो टैक्स फ्री बजट देते हैं। फिर चोर दरवाज़े से कभी बसों का किराया बढ़ाते हैं । लोगों की वाहवाही लूटने के लिए कर रहित बजट पेश करते हैं। जब आप रिसोर्सिज़ मोबिलाइज नहीं करेंगे तो आप डिपार्टमैन्ट के लिए धन ज्यादा अलॉटमैन्ट कहां से करेंगे? हम केन्द्र पर निर्भर है। अगर केन्द्र की सरकार हिमाचल प्रदेश को मदद करे तो हमारा ज्यादा विकास होगा। जैसे माननीय धूमल जी ने कहा कि इस बार हमें केन्द्र से हर क्षेत्र में धन मिला है । केन्द्र से धन के मिलने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी उदारता दिखाई है और हमारी विधायक निधि भी बढ़ाई है। उसके बाद और भी विकास कार्यों के लिए हम आने वाले बजट में देखेंगे कि यह सरकार क्या-क्या करिशमा दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने कनैक्टिविटि की आपके सामने बात रखी ।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इस समय स्टेट-हाईवेज़ की कुल लम्बाई 1466 किलोमीटर है। स्टेट हाईवेज की सर्फेसिंग व टारिंग स्टेट के बजट से होगी। लेकिन आज सबसे बड़ी दुर्दशा नेशनल हाईवेज की और स्टेट हाईवेज की हैं। जहां तक गांव के कनैक्टिविटि की बात है, गांव को सड़क से चाहे विधायक निधि से और चाहे सांसद विकास निधि से जोड़े गए हैं उनकी ओर सरकार ध्यान नही दे रही है। गांव के लोग थोड़ी सुध ले करके अपने पैसा इकट्ठा करके मशीन लगा करके कम से कम उन कच्ची सड़कों को आवागमन के लिए बना रहे हैं ।

30.03.2015/1555/negi/ag/2

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न भी किया है शायद आने वाले समय में वह प्रश्न भी लगेगा। जो ब्लॉक द्वारा सड़कें बनाई गई हैं, जो पी.डब्ल्यू.डी. के नार्म्ज़ के मुताबिक जो ग्रेड बनना चाहिए उसके मुताबिक विधायक निधि और एम.पी. निधि से सड़कें बनी हैं, उनको सरकार क्यों नहीं पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के अधीन करती है? उनको ठीक करने के लिए इस बजट में क्यों नही धन का प्रावधान किया गया? दूसरा, विधायक निधि और सांसद निधि से जो सड़कें बनी हैं उनकी रिपेयर के लिए हम पैसा नही दे सकते । अगर विधायक सड़क बनाता है अगर उसपर हम लिखेंगे कि repairing of such and such roads तो प्लानिंग वाले हमारा पैसा काट देते हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन है कि हम विधायक निधि से चाहे भवन हो, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, जो हमने किया है या सांसद ने किया है उसकी रिपेयर के लिए हम विधायक

निधि से पैसा दे सकें, इसके बारे में मुख्य मंत्री जी विचार करें। जहां तक कम्प्लीशन की बात है, कम्पलीशन में 30 परसेन्ट ही हम पैसा दे सकते हैं । अगर कोई नई सड़क बनाई और वह अधूरी रह जाए तो उसको हम 30 परसेन्ट से ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। ये सारी बातें विचारणीय हैं और इन बातों पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय थोड़ा ध्यान करें।

प्रदेश में जहां तक नाबार्ड के अधीन और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बन रही हैं। माननीय अटल जी के आने के बाद प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत हुई और उसके बाद सारे प्रदेश में एक लहर पैदा हुई कि हमें भी सड़क की आवश्यकता है और वॉरफुटिंग पर सड़कें बनी। लोग एक एप्लीकेशन पर एन.ओ.सी. देते थे लेकिन अब उसमें एक नई अमैंडमैंट कर दी गई है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़क बनेगी उसके लिए जो ज़मीदार है वह पहले ज़मीन म्युटेशन करवाये। वह ज़बानी तो बोल रहा है कि हमारे ज़मीन में से सड़क ले जाओ लेकिन वह अपनी मलकीयत ज़मीन पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के नाम कराने के लिए गुरेज़ करता है। मुख्य मंत्री...

श्रीमती यू.के. द्वारा जारी...

30/1600/2015/03/यूके/एजी/1

श्री --रिखी राम कौंडल-जारी ---

मुख्य मंत्री जी इस पर भी ध्यान दें । आज यदि हमारी PMGSY और नाबार्ड की सड़कों की हर वर्ष प्रोग्रेस्स कम हुई है तो यही एक कारण है कि हमारी वे सड़कें नहीं बन पाईं । जो RIDF में मैं थोड़े से आंकड़े आपको दिखाना चाहूंगा फिर उसके आधार पर मैं कहूंगा कि आपकी सरकार और पिछली 5 वर्ष की सरकार ने क्या-क्या काम किए हैं । वर्ष 2008-09 में टोटल ऐक्सपेंडिचर, 13,388.28 हमने किया । अगर आपकी वर्ष 2012-13 की फिगर बताएं तो 3039 केवल ऐक्सपेंडिचर आप RIDF में कर पाए हैं । कैसे मैं समर्थन कर सकता हूं इसका ? ये आंकड़े आपके विभाग के वैबसाईट पर डाले हुए हैं । ये मेरे आंकाड़े नहीं हैं । अगर यह प्रोग्रेस इतनी घटी है आपके कार्यकाल के अन्दर तो उस पर गहन विचार करिए, मुख्य मंत्री जी । यह क्यों घटी है? इसका एक ही कारण है कि आपने जो जमीन के म्यूटेशन वाला फंडा आपने डाला है, यह जब तक रहेगा आपकी सड़कों की प्राग्रेस और नीचे होगी । दूसरी, एक और बात कहना चाहूंगा कि PMGSY के तहत मॉनिटर आते हैं । वे यहां आ कर कुछ नहीं करते हैं । वे क्या करते हैं,

इसकी चर्चा मैं माननीय सदन के अन्दर नहीं करना चाहूंगा, मैं एक वरिष्ठ सदस्य हूं, मैं इतनी छोटी और हल्की बात इस सदन में नहीं करना चाहता । हमारे पास ई0एन0सी0 है, चीफ इंजीनियर हैं, जे0ई हैं, हमारे प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में टैक्नीकल लोग हैं । अच्छी क्रीम है, हमारे लोक निर्माण विभाग की । उसमें लोग सक्षम हैं । लेकिन कभी हैदराबाद या मध्य प्रदेश से कोई रिटायर्ड लोग आ जाते हैं । उनके लिए ए0सी0 गाड़ी भी चाहिए । इस पर भी ध्यान करें । माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यदि यह मॉनीटर्स के विषय को केन्द्र से भी उठाना पड़े तो इस को केन्द्र से उठाएं । हम भी कोशिश करेंगे इस विषय को प्रधानमंत्री से उठाने की । जब हमारे प्रदेश के अन्दर टैक्नीकल, ऐक्सपर्ट आदमी हैं जो कि सुबह से शाम तक काम करते हैं । परन्तु मध्य प्रदेश से कोई चीफ इंजीनयर आता है, सारी उम्र, 60 साल तक तो नौकरी वहां की, और यहां आ गए, मेहमान-नवाजी करने के लिए । मैं मॉनीटर के बारे में एक बिलासपुर का उदाहरण देना चाहूंगा कि एट हंर्डेड गाड़ी उसको दी, एक बिलासपुर के ऐक्सियन ने और वह सारे बिलासपुर के ठेकेदारों की जितनी भी सड़कें थी, उन में ऑबजैक्शन लगा कर चला गया जिससे उन सारे ठेकदारों के बिल रुक गए । इस पर भी ध्यान करिए । ये जो मॉनीटर बाहर से लगाते हैं, यह प्रदेश पर एक किस्म का बोझ है । हमारे प्रदेश का

30/1600/2015/03/यूके/एजी/2

मॉनीटर चाहे कोई हो, उसको लगाया जाए, उसको प्रदेश के प्रति दर्द है । उसको पता है कि I am son of the soil.मुझे इस प्रदेश से प्यार है । मैने प्रदेश के PWD विभाग मे सेवा की है और मैने PWD विभाग की सेवा करके ही अपने खानदान और अपने परिवार को ऊपर किया है । माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान करें ।

पुलों के बारे में कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार आने के बाद से बृजिज़ बनाने की स्पीड कम हो गयी है । ये आंकड़े आपके वैबसाईट पर डले हुए हैं । यह मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं ये नैट से निकाले हुए आंकड़े हैं कि आपकी बृजिज़ बनाने के बारे में स्पीड कम हो गयी है । ये आंकड़े कैसे कम हुए ? मैं दो पुलों का उदाहरण देना चाहूंगा । बैरीतरोला का पुल, आपने आनन-फानन में शिलान्यास कर दिया । बिलासपुर के लोग चाहते थे कि लुहणू मैदान से पुल बनना चाहिए । आपने पोगरहट्टी में शिलान्यास कर दिया । तीसरी डिमांड थी कि जो राजाओं के समय का पुल था उसको रिस्टोर किया जाए । आज उस पुल का झगड़ा पड़ा हुआ है। उस पुल पर मेरे चुनाव क्षेत्र में हर चुनाव में राजनीति होती है । मुख्य मंत्री महोदय, आप 25 अप्रैल को

बिलापुर गए थे । आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि बैरीतरोला पुल बनाना मेरी प्राथमिकता है । उस पर ध्यान दीजिए और उस पुल को सिरे लगा दीजिए क्योंकि पिछले समय जब हम सत्ता में थे तो आपके दल के लोगों ने राजनीति की । आप सत्ता में, सरकार में हैं, हम विपक्ष में हैं । हम वहां राजनीति करें, मैं ऐसी बात नहीं करता राजनीति के अन्दर । पिछली बार दूसरे भंगाल पुल का उदाहरण देना चाहूंगा मैं । जब भी मेरा चुनाव क्षेत्र आता है तो मेरे खिलाफ राजनीति करते हैं । आपने बड़े मधुर शब्दों में बिलासपुर में कहा कि मैने बड़े शौक से इस पुल का शिलान्यास किया है । मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं । आपने दोनों धारों को कोडधार और नैनादेवी धार को जोड़ने के लिए जो प्रयत्न और पहल की थी उसके लिए हमने आपका बहुत बड़ा स्वागत किया सन् 2004 में उसका शिलान्यास किया गया । 2004 में शिलान्यास करने के बाद ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

30.03.2015/1605/sls-ag-1

श्री रिखी राम कौंडल...जारी

2004में शिलान्यास करने के बाद गैमन एंड कंपनी को उसके टैंडर दिए गए। डिजाईन उनका था और उनका लंपसम टैंडर हुआ। उसके बाद, जो हमारे टैक्निकल अधिकारी थे; बजाये 45फुट नीचे जाने के उन्होंने उसकी फाऊंडेशन ऊपर ही रख दी गई। टैक्निकल खराबी की वजह से आज वह पुल अघर में है। आप भी महसूस करते हैं कि मेरे हाथों से हुए शिलान्यास वाले पुल का उद्घाटन करने के लिए मैं सक्षम नहीं हो रहा हूं। फिर आप आदेश दे आए कि दूसरा पुल बनाया जाए। मुख्य मंत्री महोदय, जो 22 करोड़ रुपया वहां खर्च हुआ है ,जिस कंपनी ने वह 22 करोड़ रुपया खर्च कर दिया , उस पैसे का क्या होगा? मैं मानता हूं कि दूसरी जगह पुल बनाने के लिए सरकार पैसा दे देगी। उन्होंने उसको स्ट्रैंथन करने के लिए विभाग से 74 करोड़ रुपये की मांग की जबकि 40 करोड़ रुपये में नई जगह पर दूसरा पुल बन सकता है। क्या, माननीय मुख्य मंत्री जी, उस गैमन एंड कंपनी के ख़िलाफ़ आप आर्बीट्रेशन की कार्यवाही शुरू करेंगे? वह पैसा रिकवर करेंगे जिस पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ? अगर दूसरा पुल दूसरी जगह बनेगा ,तो वह 22 करोड़ रुपया इस प्रदेश के गरीब किसान और मज़दूर तथा सब लोगों के टैक्स का पैसा था। माननीय मुख्य मंत्री जी, उसके बारे में भी ध्यान दें।

जहां तक सड़कों का प्रश्न है, आपके विधायक भी सड़कों पर घूमते हैं और हम भी घूमते हैं। हम यहां बोलेंगे तो आपके लोग बोलेंगे; दिल से तो वह भी महसूस करेंगे, सिर्फ़ दिखावे में बोलेंगे कि एक सैंसेशन क्रियेट करने के लिए कौंडल जी ने सड़कों की दुर्दशा के बारे में कहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई भी मुख्य मंत्री बनता है, चाहे हमारा बने चाहे तुम्हारा बने, वह हैलिकॉप्टर से आते-जाते हैं, सड़कों से कम जाते हैं। अगर मौसम खराब हो तो मज़बूरी में सड़क से जाते हैं। मुख्य मंत्री जी, आप 15 दिनों के लिए या महीने भर के लिए ज़रा सड़कों का दौरा करें, तो अपने आप सड़कें ठीक हो जाएंगी। जहां मुख्य मंत्री जाते हैं वहां, पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा,

30.03.2015/1605/sls-ag-2

चाहे जालन्धर से चाहे लुधियाणा से चाहे दिल्ली से बिचुमन लाना हो, सड़कें झट से ठीक हो जाती हैं। यही एक तरीका सड़कें ठीक करने का है। महीने दो महीने के लिए जरा हैलिकॉप्टर को विश्राम दीजिए। मैं मानता हूं कि एज फैक्टर की वजह से आपका बड़ा बिजी शैड्यूल है, टायरिंग शैड्यूल है। मुख्य मंत्री को हैलिकॉप्टर अथौराईज है; यूज भी करना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं कि आप यूज न करो। करिए, खूब दिल से करिए। पर सड़कों का सुधार करने के लिए या तो लोक निर्माण विभाग को आदेश दीजिए कि सड़कों का सुधार करो, नहीं तो मुख्य मंत्री जी, अगर आप सड़क से दौरा करेंगे, आधी सड़कें डर के मारे ही लोक निर्माण विभाग ठीक कर देगा। क्योंकि मुख्य मंत्री से ही अधिकारी डरते हैं। मंत्रियों से भी बड़े कम डरते हैं और विधायकों से तो डरते ही नहीं। बड़े अधिकारियों को पता है कि अगर मुख्य मंत्री लिख देंगे तो एक्स.ई.एन. यहां से केलाड़ चला जाएगा। अगर एक्स.ई.एन. के बारे में कोई एम.एल.ए. लिखेगा तो फाईल पर पुट अप होगा, फिर कोई अप्रोच मुख्य मंत्री के पास लग जाएगी। आज इस एंटी-डिफैक्शन एक्ट के बाद मुख्य मंत्री इतने ताकतवर हो गए हैं। वह चाहे हमारे दल का हो, या किसी भी दल का हो, विधायकों को इतनी तरजीह नहीं है। जब डॉक्टर परमार मुख्य मंत्री थे, उस समय डिफैक्शन एक्ट नहीं था। उस समय एक विधायक की कद्र होती थी। छः विधायकों को संभालने के उलिए एक मंत्री होता था। मैं मानता हूं कि आप बड़े डैमोक्रेट हो। माननीय मुख्य मंत्री जी, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए।

मैं अपने चुनाव क्षेत्र की दो-तीन सड़कों का ज़िक्र करना चाहता हूं। मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है कि अध्यक्ष महोदय घंटी बजाने

वाले हैं। मैं भी इस आसन पर सुशोभित हो चुका हूं और इशारे से ही पता लग जाता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, एक मेरी सड़क है। यह मेरी अपनी पंचायत की सड़क है। नाबार्ड में पम्प हाऊस से लेकर जोल परियान स्थान तक इस सड़क को बनाया गया। मेरा गांव जोल पीर/परियान है। आपके कार्यकाल में उस सड़क का काम हुआ। टैंडर हमारे कार्यकाल में हुए। 74 लाख रुपया हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुआ। पर जिसने काम किया, श्रेय उसको जाता है। Government is in

30.03.2015/1605/sls-ag-3

continuity. हमारी सरकार के समय में जो पुल अधूरे थे, उनको आपने पूरा किया और उनका उद्घाटन आप कर रहे हैं। हम उसका स्वागत करते हैं। मैंने तो आपको स्वयं निमंत्रण दिया कि मेरी कॉलेज की बिल्डिंग भी तैयार होने वाली है जिसपर झण्डूता के अंदर हमेशा राजनीति हुई। मेरी 4-5 पानी की स्कीमें हैं। मुख्य मंत्री जी, आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। अगर आपकी पार्टी का कार्यक्रम या सभा होगी तो हम वहां और विधायकों की तरह झगड़ा नहीं करेंगे; चुपके से अपनी गाड़ी में चले जाएंगे। जब मुख्य मंत्री जी किसी क्षेत्र में आते हैं तो वहां के विधायक द्वारा उनका स्वागत करना उसका दायित्व बनता है। हम आपको पलकों पर बिठायेंगे, आप वहां चलें। मैंने खुद निमंत्रण दिया। अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : झण्डूता में कॉलेज किसने मंजूर किया? उसको बनाने के लिए 5 करोड़ रुपया किसने दिया? आपने उस रुपये का दुरुपयोग किया। अब तक तो कॉलेज बन कर तैयार भी हो जाना था।

श्री रिखी राम कौंडल जी ..जारी...गर्ग जी के पास

30/03/2015/1610/RG/AG/1

श्री रिखी राम कौंडल-------क्रमागत

मैंने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि माननीय मुख्य मंत्री जी मैं उसी पर आ रहा हूं। झण्डुता का कॉलेज आपने स्वीकृत किया ,पैसा आपने दिया, हमारी सरकार आ गई , जो साइट बिल्डिंग के लिए रखी गई थी वहां मुसलमानों की कब्रें थीं ,साइट बदल दी गई। उसके पश्चात जैसा साइट का स्तर था उसके मुताबिक काम हुआ। आपने स्वयं काम का इन्सपैक्शन किया, आपको काम में कोई कमी नजर आई? उस कॉलेज पर

राजनीति की ,आपके आने के बाद उसके काम की गति बढ़ी है ,मैं यह मानता हूं और आपका स्वागत करता हूं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं स्पष्ट व्यक्ति हूं और विधान सभा में मैं वही बोलूंगा जो सच्चा बात होगी। चाहे मेरे दल की बात हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग वाले इस बात को नोट करें कि जोल परियान पम्प हॉऊस से लेकर मेरे चुनाव क्षेत्र में एक सड़क है। उसके लिए नाबार्ड में 74,00,000/-रु. स्वीकृत हुए। उस सड़क का काम हुआ। सड़क पर अभी बस भी नहीं चली थी कि 15 दिन के बाद उसकी सारी टारिंग उखड़ गई। शेडयूल्ड कास्ट कम्पोनेंट में कोसरिया से चौता रोड तक एक सड़क बनी है। उसमें बस चले हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे, बरसात पड़ गई और उसकी आज सारी-की-सारी टारिंग उखड़ गई। कोठी जगल मल्होर रोड है उसकी भी सारी-की-सारी टारिंग उखड़ गई। इसके अतिरिक्त मेरे चुनाव क्षेत्र में जहां-जहां सरफेसिंग हुई है, आप थोड़ा ठेकेदार लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये सोचते हैं कि हम रातों-रात करोड़पति बन जाएं ,ये सड़कों पर माल, बिचुमन ही नहीं डालते हैं। इसलिए यदि लोक निर्माण विभाग क्वालिटी कंट्रोल देखेगा ,तो इस प्रकार से ये सड़कें नहीं उखड़ेंगी। नहीं तो ये सड़कें इसी प्रकार उखड़ती रहेंगी। इसलिए इस ओर कृपया मुख्य मंत्री जी ध्यान दीजिए। जो जिस डिवीजन का ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, यदि आपको वहां थोड़ी सी भी कोताही नजर आती है, तो उसके खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्रवाई आप करें। यदि आप 2-4 लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, तो सारा प्रदेश अपने आप ठीक हो जाएगा। यही कुछ चन्द बातें मैंने आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखी हैं। सड़कों का प्रदेश में बहुत बुरा हाल है, सड़कें उखड़ चुकी हैं। मैंने आपका जिक्र किया कि हैलीकॉप्टर के द्वारा दौरा छोड़कर थोड़ा सड़कों के माध्यम से भी दौरा करें ताकि आपको सड़कों की हालत के बारे में पता चल सके कि उनकी हालत क्या है। मैंने यहां आंकड़े भी दिए कि इनके

30/03/2015/1610/RG/AG/2

कार्यकाल के बजाय हमारी सरकार के समय ज्यादा पुल बने ,सड़कों की सरफेसिंग हमने ज्यादा की, ये नैट की फिगर्ज आपकी डाली हुई हैं ,हमने टारिंग भी ज्यादा की। इसलिए जब हमारे पिछले पांच वर्ष के कार्यकाल में काम ज्यादा हुआ और आपकी गति धीमी पड़ी है। तो मैं इस मांग का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्ययवाद।

समाप्त

अध्यक्ष : अब श्री विजय अग्निहोत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विजय अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-10 पर जो कटौती प्रस्ताव यहां प्रस्तुत हुआ है मैं उसके विषय में बोलने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। लोक निर्माण- 'सड़क, पुल एवं भवन'। यदि हम इन सभी मदों में प्रदेश में नजर दौड़ाते हैं, तो सड़कों की हालत प्रदेश में बहुत ही दयनीय है। यह सच है कि जब से हम आजाद हुए, 268 किलोमीटर से 33,737किलोमीटर तक की सड़कों का निर्माण इस प्रदेश में हुआ है। जैसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में आवागमन का सबसे महत्वपूर्ण साधन सड़कें हैं, रेलवे लाइन्ज और हवाई पट्टियां या हवाई मार्ग बहुत कम हैं। यहां व्यक्ति एवं पूरा समाज ही सड़कों पर निर्भर है। कई बार हम यह कहते भी हैं कि हिमाचल प्रदेश में सड़कें प्रदेश की भाग्य रेखाएं या जीवन रेखाएं हैं और यदि सड़कें अच्छी हों, हर जगह जाती हों ,तो उसके पश्चात ही उस क्षेत्र का विकास शुरू होता है- ----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2015/1615/MS/AG/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी-----
सड़कें अच्छी हों, सड़क हर जगह जाती हों, उसके बाद ही उस क्षेत्र का विकास शुरू होता है या विकास संभव होता है। जहां सड़क जाती है वहां स्कूल, अस्पताल या कर्मचारी जाने की कोशिश करता है। अगर सड़क से दूर कोई संस्थान खोल भी दें तो उसकी हालत ठीक नहीं रहती है। इसलिए प्रदेश में सड़कों को ठीक करना बहुत महत्वपूर्ण काम है। यह भी सच है कि बरसात बहुत होने के कारण सड़कों की हालत में खराबी आई है। हम बहुत सा बजट और पैसा सड़कों पर खर्च करते हैं लेकिन उसके बावजूद सड़कों की हालत जैसी सुधरनी चाहिए थी नहीं सुधर पा रही है। अब पता नहीं योजनाओं में कमी रहती है, उनकी इम्प्लीमैंटेशन में कमी रहती है या जो आउटसोर्सिंग से काम होता है, उसमें ठेकेदारों की कमी रहती है लेकिन कमी कहीं-न-कहीं जरूर है।

जहां तक नेशनल हाइवे की बात है। जब हम यहां से धर्मशाला को जाते हैं तो बीच में थोड़ा सा रास्ता ठीक होने के बाद कहीं उसकी चौड़ाई ठीक नहीं है और कहीं कुछ और समस्या है। यहां से धर्मशाला जाते-जाते जितनी पुलियां आती हैं हालांकि

नेशनल हाइवे चौड़ा बना है, ठीक बना है और लोग स्पीड से जाते हैं। लेकिन जब बाहर के लोग आते हैं तो पुलियों पर क्योंकि सिंगल गाड़ी ही निकल सकती है इसलिए जब वहां कोई गाड़ी सामने से आ जाती है तो रात को कई बार पता नहीं चलता और दुर्घटना घट जाती है। अध्यक्ष जी, पीछे दधोल में एक पुलिया तंग होने के कारण दिल्ली के 7-8 पर्यटकों की गाड़ी वहां गिरी और उनकी मृत्यु हुई। हमीरपुर के पास पीछे बरसात में पुल टूटा और उस पुल को हमने टैम्प्रेरी अरैंजमैंट, स्टॉप गैप अरैंजमैंट से चलाया हुआ है लेकिन इनके परमानैंट सुधार हेतु कुछ किया जाना चाहिए। जो पुलियां बिल्कुल नेशनल हाइवे के स्टैंडर्ड की नहीं हैं, उनको जितने दिनों में बन जाना चाहिए था आज तक नहीं बन पाई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जहां नेशनल हाइवे को ठीक कर रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं या उनकी मुरम्मत कर रहे हैं वहीं साथ-साथ उन पर बने पुलों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए ताकि एक अच्छा सड़क मार्ग बनाकर हम सब लोगों को दे सकें।

30/03/2015/1615/MS/AG/2

यहां पीछे प्रश्नों के माध्यम से भी और बजट भाषण पर हुई चर्चा के दौरान भी ध्यान में आया कि कुल्लू और सिरमौर में बड़े-भारी पर्यटक आते हैं। मेरे भी दिल्ली में जानने वाले कई टैक्सी का काम करते हैं। पिछले साल वे कह रहे थे कि अगर कोई मनाली के लिए हमें बोलता है तो हम दिल्ली से ही इन्कार कर देते हैं क्योंकि स्वारघाट से होता हुआ जो नेशनल हाइवे है, जो गाड़ी 10 चक्कर लगाने से खराब होती है ,उसमें उससे भी ज्यादा नुकसान एक चक्कर में वहां गाड़ी का हो जाता है। यानी एक तरफ इससे पर्यटन पर असर पड़ रहा है और दूसरे हमारी गाड़ियां कभी बिलासपुर से कीरतपुर की तरफ चलें तो एक्सीलेटर पर कम और ब्रेक पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है।

ऐसे ही बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान नालागढ़ के विधायक महोदय ने नेशनल हाइवे 21 - नालागढ़ से स्वारघाट का जिक्र किया कि उसकी बहुत बुरी हालत है। उन्होंने वहां आंदोलन भी किया और 200 लोगों के ऊपर केस बनें। उस चर्चा में उनको यह कहना पड़ा कि यदि आने वाले समय में जल्दी ही उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, ठीक स्टैंडर्ड का काम नहीं हुआ तो नालागढ़ से हजारों की संख्या में लोग सचिवालय की ओर कूच करेंगे और वहां से नामी-गिरामी व्यक्तियों के साथ वहां का विधायक भी सचिवालय के सामने सेल्फ-इमोलेशन करेगा। यानी आज सड़कों की बुरी

हालत के कारण एक विधायक को सदन के बीच में ऐसा कहना पड़ रहा है। इस करके जो नेशनल हाइवे पर रि-सरफेसिंग की जाती है या की जा रही है, वह पौने इंच की की जाती है जो साथ ही उखड़ जाती है। उसका भी स्टैंडर्ड ठीक किया जाए। उसको सवा इंच का किया जाए। जो उस सड़क पर लोड है, उसके हिसाब से वहां काम हो। अध्यक्ष जी, ऐसा निवेदन मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से करना चाहता हूं। जहां तक नेशनल हाइवे पर बनने वाले पुलों की बात है, उसको स्पीड-अप करने की जरूरत है। उसके ऊपर विभाग को स्पैशल ध्यान देने की आवश्यकता है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

30.03.2015/1620/जेके/एजी/1

श्री विजय अग्निहोत्रीः----जारी-------

और कहीं न कहीं हम इन सब कामों को समयबद्ध करें ताकि उनके जो पैरामीटर्ज हैं, जो उनके ऊपर काम होता है वह समयबद्ध हो जाए। उसके ऊपर बजट की कम खपत हो तथा साथ-साथ उनका स्टैंडर्ड भी ठीक हो। उनकी ठीक तापमान में मैटलिंग हो। कभी बारिश के महीने में मैटलिंग होती है और दूसरे महीने फिर वह सड़क साफ हो जाती है। नादौन-हमीरपुर हाई वे का काम पांच साल से चला है। मैंने पीछे प्रश्न भी किया था। उस प्रश्न के उत्तर में आया कि वहां पर 76 प्रतिशत काम हो गया है। लेकिन जो 76 प्रतिशत काम पहले हुआ था वह सारे का सारा टूट गया है। जहां पर उनका प्लांट लगा है वहां आस-पास की सड़कों की बुरी हालत है। अगर 5 साल के बीच में कोई फर्म, ठेकेदार या विभाग काम नहीं करवा पा रहा है उसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। आज अगर वहां से जाया जाए तो सबसे बुरी हालत उस सड़क की है। करोड़ों के हिसाब से उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, लेकिन काम अच्छा नहीं हो पा रहा है। काम समयबद्ध नहीं होता है। ऊपर से बी.एस.एन.एल. वाले पहले ही सड़क को उखाड़ना शुरू कर देते हैं। आज भी वहां पर ऐसी हालत है। मैंने इस बारे में बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों से बातचीत की कि आप लोग इन रोड़ज को बार-बार खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक किलोमीटर नेशनल हाई-वे की रिपेयर के लिए 11 लाख रूपया विभाग को देते हैं और तब इसको उखाड़ते हैं। अगर वह पैसा मिल रहा है तो साथ-साथ रिपेयर क्यों नहीं हो पा रही है? इसके साथ-साथ पूरे प्रदेश के विषय यहां पर आए हैं। मैं भी अपनी विधान सभा क्षेत्र में जो सड़कें हैं उनकी बुरी हालत है उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले

समय में उन सड़कों के रख-रखाव व उनकी रिपेयर के लिए काम किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी, जैसे कौंडल जी ने कहा कि आप यदि सड़कों का दौरा करेंगे तो उन सड़कों का सुधार होता है। वहां के अधिकारियों/कर्मचारियों या वहां के जो पार्टी के नेता हैं उनको भी यह बोल रखें कि जहां-जहां आवश्यकता है वहां-वहां काम हो जाना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी पीछे मेरे चुनाव क्षेत्र में गए। इन्होंने बसारल के

30.03.2015/1620/जेके/एजी/2

पुल का उदघाटन किया। बसारल के पुल में जिस तरफ इन्होंने उदघाटन किया उस तरफ की सड़क तो पक्की कर दी गई और पुल की दूसरी तरफ कच्चा रास्ता रख दिया गया। उस तरफ माननीय मुख्य मंत्री को ले जाया ही नहीं गया। वह रास्ता आज भी कच्चा है। मुख्य मंत्री जी को शॉर्टेस्ट रोड़ से ले जाने की विभाग कोशिश करता है ताकि अन्य सड़कों का पता ही न चले। नादौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जितने भी रोड़ हैं। मैंने बजट अनुमानों के ऊपर चर्चा करते हुए उन सभी सड़कों का जिक्र किया था। लेकिन मैं एक बार दोबारा विस्तार से उन सड़कों की हालत को आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हमीरपुर से नादौन चुनाव क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और रंगद से जो सड़कें जाती है वहां से जीर्ण होते हुए सुजानपुर की ओर जाती है जो बड़ूक होते हुए जाती है। उस सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। नादौन से बड़ा की ओर जाएं उस सड़क की भी बहुत बुरी हालत है। नादौन से धरेटा होते हुए जो सड़क बंगाणा की ओर जाती है उसमें सड़क कम और गड्ढे ज्यादा है। वह सड़क दिल्ली के लिए बहुत ही शॉर्टेस्ट रूट में है। उस रूट से एच.आर.टी.सी. पालमपुर की बसें हरिद्वार के लिए जाती हैं। हमीरपुर डिपू की बस दिल्ली के लिए चलती है और भी कई लाँग रूट की बसें चलती है। ऊना के लिए वह सबसे अच्छा रोड़ है लेकिन उस रोड़ की हालत बहुत दयनीय है। एक रोड़ कांगू से मारक होते हुए, जसाई होते हुए धलेटा जाता है। उसकी पिछले कई वर्षों से रिपेयर/ मेंटिनैंस नहीं हुई है। मैंने पीछे प्रश्न किया था और उसमें बताया गया था कि वहां पर करोड़ों रूपए नादौन विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत खर्च हुए हैं। लेकिन सड़कों की हालत क्यों नहीं सुधर पा रही है? या तो वहां पर पैसे ठीक ढंग से खर्च नहीं हो पा रहे हैं या वहां पर कोई चैक नहीं है या वहां पर कोई उसकी इवैल्युएशन करने वाला नहीं है या उनको कोई पुछने वाला नहीं है कि पिछले साल जो इतना पैसा खर्च किया वह सड़क कहां गई? वहां से लोगों का पिछले कल मुझे फोन आया था कि उस सड़क का कुछ करो क्योंकि उस सड़क में जो दो प्राईवेट बसिज चलती हैं उन्होंने कह दिया कि अगर सड़क की हालत नहीं सुधरती है तो हम इन बसों को वहां चलाना बन्द कर देंगे।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

30.03.2015/1625/SS-AG/1

श्री विजय अग्निहोत्री क्रमागतः

तो जहां बस नहीं चल पा रही है वहां छोटे व्हीकल कैसे चलेंगे? वहां पर अगर कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलैंस या टैक्सी मंगवाते हैं तो वे इंकार कर देते हैं कि हम उस सड़क में गाड़ी नहीं डाल सकते।

इन सब बातों के बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता है। पनयाली से एक धनेटा सड़क जाती है वाया मांजरा होते हुए, उसकी कई सालों से रिपेयर नहीं हो पाई है। वह खड्ड की तरह लगती है। इंद्र दत्त लखनपाल जी भी उस सड़क से जाते होंगे, आपने देखा होगा। ये छोटी-छोटी सड़कें हैं। हम पैसा भी खूब खर्च कर रहे हैं लेकिन हम उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इन विषयों पर चिन्ता करने की आवश्यकता है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने की आवश्यकता है। धनेटा से बंगाणा का जो रोड़ मैंने बताया उस पर एक पुली फरवरी, 2014 में टूटी। उसका काम नहीं हो पा रहा था। बड़ी जद्दोजहद के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने प्लानिंग की बैठक में प्रार्थना की तो इन्होंने एस0ई0 को खड़ा करके कहा उसके बावजूद भी तीन महीने के बाद अब वह काम शुरू हो पा रहा है। टेंडर हुए चार महीने हो गए लेकिन हम उसका काम शुरू नहीं करवा पा रहे। कहीं-न-कहीं इसमें अधिकारियों की कमी है। ठेकेदारों को भी सख्त निर्देश होने चाहिए। उस काम को समयबद्ध किया जाए ताकि वहां पर जो काम होना है वह काम ठीक ढंग से हो और लोगों को उसका लाभ मिल सके। हमीरपुर से जब गलोड़ को जाएं तो उस सड़क की हालत भी बहुत खराब है। गलोड़ से जितने रोड जाते हैं जैसे फाहलप्लासी होते हुए टिप्पर को रोड जाती है उसकी हालत खस्ता है। 14-2013में वहां पर 20 या 22 लाख रुपया खर्च किया हुआ भी बताया है। उसके बावजूद भी वह उखड़ी हुई सड़क है। बदरान चौंक से आप गालियां होते हुए जब दांदड़ू को जाते हो तो उस सड़क की हालत भी ठीक नहीं है। वहां पर भी बताने के लिए खर्चा बहुत हुआ है। लेकिन उन सड़कों की वस्तुस्थिति क्या है? लोगों के घरों के पास डंगे गिर जाते हैं उन डंगों को नहीं बनाया जा सकता। और तो और जहां हम आज रह रहे हैं कार्ट रोड भी एक तरफ से बंद करना पड़ा है। उस कार्ट रोड की भी सुध लेनी चाहिए। पिछले कई दिनों से वहां जाम लग रहा था लेकिन अब रोड इतना टूट गया है कि बंद ही करना पड़ा। गलोड़ से

सलोनी की तरफ चलें तो भी रोड की हालत ठीक नहीं है। भट्टा से लेकर सलोनी तक, जिसकी चार-पांच साल पहले पूरी मैटलिंग हुई थी वह भी जगह-जगह

30.03.2015/1625/SS-AG/2

से टूट गया है। इस करके पनयाली, खतरोहड़ ,चराड़ा, गलोड़ से झरमाणी-बाहल , कड़साई, अमरोह इन सब सड़कों की हालत खराब है। कश्मीर-तुहणी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां पिछली टर्म में पुल का उद्घाटन किया। सामने सड़क नहीं बनी थी। पिछली बार वह सड़क बनी। वह सड़क ऐसी है कि छोटी-सी बारिश हो तो वह टूट जाती है। उसका विकल्प होना चाहिए। उसकी ग्रेडिंग ठीक नहीं है या क्या चीज़ ठीक नहीं है, वह सड़क चलती नहीं है। उसको चाहे रिपेयर करो लेकिन 10 दिन के बाद वह फिर टूट जाती है। उसी दौरे के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी ने कश्मीर की सीनियर सकैण्डरी स्कूल की लैब की तब एनाउंसमैंट की थी लेकिन वह आज तक पूरी नहीं हो पाई है। बहुत-सी जो नयी सड़कें बन रही हैं उन सड़कों की बनने की गति बहुत धीमी है। धूमल जी के समय में 3 करोड़ 17 लाख से वटराण से बल्ह पटियाला होते हुए बसारल के लिए रोड बननी थी। तब से काम चल रहा है अभी भी उसके ऊपर बहुत काम होना बाकी है। मैंने पीछे एक प्रश्न डोहग-बेहा-हथोल रोड़ का किया था। उसमें उन्होंने कहा कि पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत बनाई है। उसके ऊपर जितना बजट था वह खर्च कर दिया है। लेकिन वह सड़क हथोल पहुंचनी थी वह नहीं पहुंची। वह बेहा तक बनी। उसके आगे का क्या है उसका कुछ पता नहीं। आज मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा फॉरैस्ट पड़ता है, फॉरैस्ट क्लीयरैंस के लिए अभी केस जाना है। वह कई सालों से बनी हुई सड़क है। उसमें एक पुली बननी है और साथ में वह हथोल से जुड़ जायेगा। 15-20 पंचायतों को उससे लाभ होगा। अगर उसके ऊपर फॉरैस्ट क्लीयरैंस की जरूरत है, ये जा रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब भेज रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो भी उसमें बरसों लग रहे हैं। उसको स्पीड अप करने की आवश्यकता है। ऐसा मुझे लगता है। एक और बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। वह यह है कि कुछ छोटे-छोटे रास्ते जो खराब हो जाते हैं कई बार हमें लगता है कि विभाग को देर हो गई तो हम विधायक निधि से भी उस रास्ते को ठीक करने या बनाने के लिए पैसा दे देते हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

/1630/30.03.2015केएस/एजी/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी---
छोटे-छोटे रास्ते जो खराब हो जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि विभाग को देर हो गई तो हम विधायक निधि से भी उस रास्ते को ठीक करने या बनाने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. को पैसा दे देते हैं। मैंने पहले भी कई बार बात रखी कि डेढ़ वर्ष पहले भी जो पैसा मैंने दिया है डरोल -चुनहान सड़क को ठीक करने के लिए, दो लाख रुपये दिए हैं एक अन्य सड़क के लिए सम्पर्क मार्ग बनाने के लिए एक लाख रुपया दिया है, ऐसे ही चार-पांच लाख रुपये पी.डब्ल्यू.डी. के पास पड़े हैं लेकिन डेढ़-दो वर्षों में वे टैण्डर भी नहीं करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, उसका कारण मुझे राजनीतिक ज्यादा लगता है क्योंकि वहां के स्थानीय नेता कहते हैं कि यह काम नहीं होने चाहिए, इनको लटकाए रखो और इसका एक ताजा उदाहरण अभी सामने आया है कि एक जगह पैसा सेंक्शन हुआ, कांग्रेस सरकार ने पैसा सेंक्शन किया, जहां हम आपको कहते हैं कि बुरी हालत है और वह आप ठीक कर देते हैं तो हम जरूर मानेंगें कि ठीक हो गई लेकिन वहां जब लोगों ने कहा कि पैसा सेंक्शन हो गया है और आप काम शुरू करवाओ तो मैंने बात की, वहां के लोग भी गए तो वहां एस.डी.ओ. ने कहा कि फलां नेता से फोन करवाओ तब इसका काम शुरू होगा, प्रदेशाध्यक्ष बोलेंगें तब काम शुरू होगा। तो ऐसा हस्तक्षेप भी आपकी फंक्शनिंग को प्रभावित करता है और इसका अगर उस एरिया के लोगों को नुकसान होता है तो आपकी सरकार को और पार्टी को भी नुक्सान होता है इसलिए मेरा आपको परामर्श रहेगा कि इन बातों के ऊपर चैक लगाया जाए।

/1630/30.03.2015केएस/एजी/2

अध्यक्ष महोदय, दाड़-टैहली-जसाई रोड़ का कार्य बहुत धीमी गति से चला है। दो वर्षों से और कई वर्षों से जो हमने विधायक प्राथमिकता में स्कीमें दी है या उससे पहले भी बहुत सी स्कीमें चल रही हैं, उनकी डी.पी.आर. बनकर तैयार नहीं हुई है। एक सड़क जिसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च हो गए हैं, पनसाई-रामनगर-मंझेली-तरकेहड़ी-भूम्पल रोड़, उस रोड़ पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया है, सड़क बन गई है । तरकेहड़ी के पास भूम्पल के लिए पुल बनना है और पन्साई में पुली बननी है। कई वर्षों से वह काम नहीं हो रहा है। जहां तक तरकेहड़ी के पुल की बात है, वहां चार-पांच ठेकेदार आए, काम छोड़कर चले गए, पता नहीं क्या बात है? विभाग इसको गम्भीरता से लें और साथ में बजट की वहां कमी थी तो एस.सी.सी.पी. से पैसा लिया जा रहा है उसके लिए भी

जल्दी से पैसे का प्रावधान करवाया जाए। जो दूसरा पुल है, जिसके कारण से उस सड़क की पूरी रैलीवैंस खत्म हो जाती है , उस पुल के बारे में विभाग का जो यह उत्तर है कि वहां जमीन न मिलने के कारण, वहां किसी ने ऑब्जैक्शन कर दिया है इस करके वह नहीं बन पा रहा है और वह नहीं बनेगा तो उसके लिए वैकल्पिक जगह ढूंढी जाए ।जब हम किसी को कहते हैं कि डी.पी.आर. नहीं बन पा रही है तो कहते हैं कि हमारे पास सड़क के लिए जमीन का प्रावधान नहीं है, हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे एफिडेविट मांग रहे हैं, उनको गिफ्ट डीड बनाने के लिए बोल रहे हैं । तो यह जो डी.पी.आर्ज़. बन गई हैं, उनमें जमीन नहीं है, ऐसा मुझे समझ नहीं आता। कुछ पी.एम.जी.एस.वाई. के रोड़ हैं । उनमें फेज़-i का काम हो गया है,

/1630/30.03.2015केएस/एजी/3

सात साल पहले हो गया है लेकिन आज तक फेज़-ii का काम शुरू नहीं हो पा रहा है, पत्राचार भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि बोलते हैं कि अब उसके ऊपर फोरैस्ट आ गया है। सड़क बन गई, सब कुछ हो गया। एक बार मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा था कि इनकी फोरैस्ट क्लीयरेंस करवा दी जाएगी लेकिन एक साल हो गया है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो फोरैस्ट क्लीयरैंस के केसिज़ पैंडिंग हैं, उन सबको भी अब जल्दी से ठीक करेंगें तो सड़कों की हालत सुधर सकती है। एस.सी.सी.पी. की सड़कों में बजट की कमी है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री विजय अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन पुलों के बारे में बात करके समाप्त कर रहा हूं। मालग-खतरोड़-जसाईं रोड़ है उसके ऊपर चराड़ा में नाले के ऊपर पुल बनना है, उसकी डी.पी.आर. भी बनकर तैयार हो गई है लेकिन कई दिनों से टैण्डर नहीं हो पा रहा है, उसको जल्दी से करवाने की कृपा करें। इसी तरह से मैड़-टिक्कर रोड़ वाया जैना सुकराला उसका कई वर्षों से काम चल रहा है। ठेकेदार को कई बार पैनल्टी भी पड़ चुकी है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है । विभाग उसका संज्ञान लेना, ऐसा मेरा निवेदन है और उसके ऊपर तीन पुल बनने हैं और उन तीन पुलों की डी.पी.आर. भी जल्दी बनकर तैयार हो ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

श्री विजय अग्निहोत्री जारी----------
डी.पी.आर. जल्दी से बनकर तैयार हो, ऐसा मैं निवेदन करना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त कोटलू के पास भतनेहड़ी पुल की डी.पी.आर. अप्रूव हो गई है। इसके टैंडर होने हैं मगर कई महीनों से वह टैंडर नहीं हो पा रहे हैं; उसको भी स्पीड-अप किया जाए। इसके अतिरिक्त बटराण-हथोल -जसाई-गोण पत्थर रोड दोनों तरफ से बना है मगर इसमें हथोल में पुल का निर्माण होना है। उस हथोल के पुल की डी.पी.आर. जल्दी से बने और उसके ऊपर काम हो; मैं ऐसा निवेदन करता हूं। साथ में, मैं इस मांग के अंतर्गत मशीनरी / उपकरण की क्रय व आबंटन नीति पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नदौन और धनेटा सब डिविजन में (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। ऐसा है, आप एक-एक आइटम पर मत बोलिए। आपने सारे पुल और मशीनरी गिना दी हैं।

श्री विजय अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। सारी कंस्टिचुएंसी पैरालाइज्ड हो चुकी है।

अध्यक्ष : आप इस पर जनरल बात कीजिए। आपने सारे पुल गिना दिए।

श्री विजय अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, और कहां बोलेंगे? अधिकारियों के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि फलां नेता से बात करो। यहां पर हमें माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं मांग के ऊपर अपना पक्ष रखना चाहता हूं। जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में दोनों सब डिविजन में मशीनरी की बात है वहां जे.सी.बी. की हालत खराब है। मैंने जब भी अपनी शिकायत की कि फलां रोड पर स्लाइड आया है उसको ठीक करने की आवश्यकता है तो जवाब आया कि इसका टायर पैंचर है या मशीन खराब हो गई है। कई बार मनरेगा से लेबर लेकर उसको ठीक करवाया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर नई जे.सी.बी. भेजी जाएं। वहां चाहे

30.3.2015/1635/ag/av/2

कर्मचारियों की कमी है, सर्वेयरों की कमी है या कोई और कमी है; उनको पूरा किया जाए। जब डी.पी.आर. के बारे में पूछा जाता है तो उत्तर आता है कि हमारे पास सर्वेयरों की कमी है। वहां पर सर्वेयर लगाये जाएं। पूरे प्रदेश में लगाए जाएं मगर जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगने हैं उनको भी लगाया जाए। जहां-जहां, जिस-जिस चीज की आवश्यकता है वे पूरी की जाए तभी इस प्रदेश की सड़कों की हालत सुधर सकती है। आज सड़कों की हालत पर बहुत गहन विचार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमारे बाजार और कस्बों में ऐज़-टू-ऐज़ सड़कें पक्की की जाएं ताकि उनकी ड्युरेबिलिटी बढ़े। वे सड़कें ऐज़-टू-ऐज़ पक्की नहीं होती है और बीच में से उखड़नी शुरु हो जाती है।

मैं इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से ये सारे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिस तरह पूरे प्रदेश के विकास की ओर ध्यान देंगे नदौन और हमीरपुर जिले के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

30.3.2015/1635/ag/av/3

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या : 10, लोक निर्माण- सड़क, पुल तथा भवन से सम्बंधित है। इस विषय में कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

यहां पर हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी, आप किसी भी स्थान का दौरा करने के लिए हैलिकॉप्टर छोड़ दो और सड़क से चलो तो वह सड़क लोक निर्माण विभाग पक्की कर देगा। मगर मैं पिछले दो वर्षों से यह देख रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी जिस सड़क से चलते हैं उस सड़क पर पैच वर्क नहीं होता है। सड़क पर पड़े गड्ढे मिट्टी से भर दिए जाते हैं। मुख्य मंत्री जी चले जाते हैं और बाद में वह मिट्टी वर्षा के पानी से बह जाती है। हर बार बजट में पैसा रखा जाता है लेकिन काम

नहीं होता है। शायद बाद में वह पैसा बच जाता है और आगे दिया जाता है। जिन ठेकेदारों ने सड़क का काम किया है उनकी पुरानी पेमैंट भी आज तक नहीं हो पा रही है। हिमाचल प्रदेश में सड़कें हमारी जीवन रेखा है--------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

30.03.2015/1640/negi/ag/1

श्री सुरेश भारद्वाज़ ...जारी...

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में सड़कें हमारी जीवन रेखा है। रेलवे के लिए हिमाचल प्रदेश में जो अंग्रेज़ों के समय रेल लाईन शिमला तक आई थी इससे आगे नहीं बनी और जोगिन्द्र नगर तक रेल लाईन आई थी, उससे आगे नही बनी । एक रेल लाईन 1973 में प्रारम्भ हुई थी नंगल से तलवाडा के लिए उसमें अभी तक हम अम्ब तक पहुंचे हैं। तत्कालीन प्रधान मंत्री, डॉ0 मनमोहन सिंह जी शिमला आए थे, नाथपा-झाकड़ी प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया और उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि इस बार हम इस रेल लाईन को पूरा कर देंगे। लेकिन दूसरे वर्ष उसमें कोई पैसा ही नहीं रखा गया। इस वर्ष हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो सरकार बनी है ,उसने उस रेलवे लाईने के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और बाकी की रेलवे लाईनों के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है। शायद यह आगे बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन अभी तक तो जो सड़कें हिमाचल प्रदेश में बन रही हैं उन सड़कों पर काम हो, वे बन करके तैयार हो जाएं और जो बनी हुई सड़कें टूट जाती हैं उनकी दोबारा से मुरम्मत नही होती है इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस दृष्टि से एक मुख्य सड़क की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । शिमला जिला का यह हमारा सौभाग्य है कि यहां से हमारे मुख्य मंत्री हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के जो उच्च-पदाधिकारी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वह भी शिमला जिला से संबंध रखते हैं। लेकिन अगर आप ठियोग से रोहडू के लिए चलेंगे तो जिसमें पहले केवल 2 घंटे लगते थे, आज उस सड़क पर चलते हुए रोहडू पहुंचने में आपको 9 घंटे लगते हैं। 6-5 दिन पूर्व, पी.जी.आई. की एक एम्बुलैंस ने डेड बॉडी ले करके रोहडू पहुंचना था लेकिन खड़ा पत्थर में, मिट्टी जो वहां पड़ी हुई है उसमें एक ट्रक धंस गया जिसके कारण दोनों तरफ के ट्रैफिक वहां पर जाम हो गई और वह डेड-बॉडी जो पहले दिन पहुंचनी थी वह जा करके दूसरे दिन पहुंच पायी। मुझे नहीं मालूम कैसे काम हो रहा है । वर्ल्ड-बैंक का काम है। पिछली फर्म,

चाइनिस फर्म थी और उसका काम रिसाइंड कर दिया गया। 2वर्ष हो गए हैं नए काम को दिए हुए,

30.03.2015/1640/negi/ag/2

जो दो ठेके अलग-अलग दिए गए थे, ठियोग से लेकर खडा-पत्थर तक एक कम्पनी करेगी और खड़ा-पत्थर से आगे का काम दूसरी कम्पनी करेगी, लेकिन दोनों के दोनों काम एक ही कम्पनी को दे दिए गए- सी. एण्ड सी., चढ्ढा एण्ड चढ्ढा को। चढ्ढा एण्ड चढ्ढा का शायद टैक्निकल बिड तो ठीक होगी लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी उसकी फाइनैंशियल बिड आप देख लें, उसने स्वयं यह कहा था कि मैं फाइनैंशियल क्राइसिज में हूं, जो कम्पनी स्वयं फाइनैंशियल क्राइसिज़ में है उसकी फाइनैशियल बिड कैसे स्वीकार हो गई और कैसे उस सड़क का काम उसका अलॉट हो गया? वह सड़क जो पहले कम से कम चलने लायक थी आज वहां पर चलना मुश्किल हो गया है। आज अगर कोई वहां जाए तो बिना वर्कशॉप जाए वह गाड़ी रह नही सकती। कोई गाड़ी वहां पर आसानी से चल नही सकती । आज खडा-पत्थर की तरफ जाने से पहले कोटखाई में थरोला-टाहू से होते हुए लोगों को अगर रोहडू जाना हो तो उधर से जाना पड़ता है और खडा-पत्थर से नीचे सिंगल रोड पर पटसारी पहुंचना पड़ता है क्योंकि मुख्य सड़क पर जाने की हिम्मत कोई नही कर सकता है। इसके ऊपर क्यों काम नही हो रहा है? सेब सीजन दो बीत गए हैं । इस कम्पनी को जब से काम दिया है अभी तक भी वहां पर किसी प्रकार का कोई काम नही हो रहा है। ठियोग से छैला के बीच में एक जे.सी.बी. लगी है। एक जे.सी.बी. और एक बुलडोज़र हाटकोटी से रोहडू के बीच में खड़ा है ,जो काम नही कर रहा है। छैला के पास उनका छोटा सा काम चला है, वहां पर उनका एक ट्रक खड़ा रहता है बाकी पूरे रोड़ पर कोई काम नही हो रहा है।

श्रीमती यू.के. द्वारा जारी...

30/1645/2015/03/यूके/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाज---जारी ---

कोई काम नहीं हो रहा है । इस तरह आपकी सड़कें हैं । हमारा निवेदन यह है कि उस एरिया को जब सेब का सीजन होता है, तो उसमें यदि आप यह सड़क नहीं बना पा रहे हैं । इसमें क्या कारण है, क्यों नहीं बना पा रहे हैं ? तो कम से कम ऑल्टरनेटिव रोड्ज को ठीक कर दीजिए । आप रोहडू से शिमला के लिए वाया खदराला रोड को ठीक कर

सकते हैं । नारकंडा से खदराला किसी समय में स्टेट हाईवे नम्बर-वन होता था । आज उसकी हालत इतनी खराब है कि उसमें खच्चरें भी चलने से गुरेज करती हैं । इसी तरह से आप मुख्य हाटकोटी रोहड़ू सड़क को बनाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के लोन के बावजूद भी, तो आप रोहड़ू से वाया टिक्कर अणासी धार होते हुए, उस सड़क को आप ठीक कर दीजिए । लेकिन वह भी कच्चे रोड हैं । शिमला जिला का यह दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पैसा बहुत दिया है, आप छठी बार मुख्य मंत्री बने हैं, इन्होंने कोई कमी नहीं रखी । लेकिन वहां जमीन पर काम नहीं हुआ है । कोई भी सड़क देख लीजिए, रोहड़ू की या पूरे शिमला जिले की वहां जो सड़कें पक्की हुईं भी थी, आज वह कच्ची से भी बदतर होती जा रही हैं । जब ऐसे हालात शिमला जिला, जो माननीय मुख्य मंत्री जी का अपना जिला है, वहां पर हों तो सारे प्रदेश के लिए जो यहां पर बजट का प्रावधान और मांग की जा रही है, उसका समर्थन करना असंभव है । शिमला शहर हिमाचल प्रदेश की राजधानी है । आज ही मैने प्रश्न किया हुआ था अरबन डवेलपमैंट मिनस्टिर महोदय से ,नम्बर नहीं आया कि पिछले दो वर्षों में शिमला शहर की सड़कों की टारिंग व मैटलिंग पर कितना पैसा खर्च हुआ?, कौन-कौनसी सड़क पर मैटलिंग और टारिंग हुई है । पिछले दो वर्षों से एक भी सड़क पर मैटलिंग व टारिंग नहीं हुई है । यहां पर उसका जवाब भी आया है । इक्की-दुक्की जो लिंक्स जाते हैं, कही किसी इन्फलूएंशियल व्यक्ति के घर तक जाते हैं, उस पर रिसरफेसिंग हुई है । जब कि पूरे प्रदेश में रिलायंस या दूसरी कम्पनियां जो मोबाईल टॉवर्स लगाती हैं, मोबाईल की कम्पनियां हैं, उन्होंने सारे प्रदेश में सड़कें खोद रखी हैं । शिमला शहर, लोअर बाजार, राम बाजार की सड़कों के साथ-साथ सारी की सारी सड़कें, हिमाचल प्रदेश में खोदी हैं । जैसा यहां कहा गया कि 11 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलता है । लेकिन उसके बाद सड़क की फिर से रिसरफेसिंग नहीं होती है । वह जो आपको डिपोजिट वर्क का आ रहा है, उस पैसे का भी आप उपयोग

30/1645/2015/03/यूके/एजी/2

नहीं कर रहे हैं । हिमाचल प्रदेश की राजधानी के यह हाल हैं कि दो वर्षों से यहां पर मैटलिंग और टारिंग नहीं हुई हैं तो प्रदेश की बाकी सड़कों के क्या हाल होंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेश्नल हाईवेज़ हैं, उन पर काम नहीं हो रहा है । क्या कारण हैं? यहां पर फोर-लेनिंग भी हो रही है, कालका से शिमला और स्वरघाट-नैरचौक से फोर लेनिंग का काम हो रहा है । उसमें भी बीच में अड़चनें आती जा रही हैं ।

उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है । जहां नेश्नल हाईवेज़ हैं, उसमें काम होना है । शिमला का बायपास रोड जो नेश्नल हाईवे है । उसमें दो पुल बहुत पहले टूट गए । एक पुल पर काम हो रहा है वह भी बहुत धीमी गति से हो रहा है । दूसरा पुल बनना ही प्रारम्भ नहीं हुआ है । वहां सड़क पर चलना मुश्किल है । बीच में हाई कोर्ट के पास हमारी एक सड़क का डंगा गिर गया । उस डंगे के गिरने से उसका काम दिसम्बर में शुरू होना चाहिए था । कच्चा डंगा लगा, वह गिर गया । अब पूरी तरह से दूसरा डंगा वहां लगाया जा रहा है । यह डंगा तो तभी लगेगा जब वहां पर ट्रांसपोर्ट रुकेगी । लेकिन जब यह पहली बार गिरा था, तब इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया । उसी वक्त अगर पक्का डंगा लग जाता, एक दीवार लगाने की बजाय पक्का काम हो जाता तो शायद आज यह मुश्किल नहीं आती । जब टूरिस्ट सीज़न सिर पर है, अप्रैल-मई में ही तो टूरिस्ट सीज़न होता है, शिमला में बिजनैस होता है, उसी समय सड़क बन्द रहेगी जिससे सारे बिजनैसमैन और सारी जनता का नुकसान होगा । हमारे यहां पर वर्किंग सीजन कम होता है । हम 6 महीने से भी कम काम कर पाते हैं, कभी बरसात होती है और कभी बर्फ आ जाती है । तो उसके लिए एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है । अगर आपको एक अप्रैल से मैटलिंग और टारिंग करनी है तो उसके लिए बिचुमैन आदि का प्रबन्ध पहले कर दिया जाना चाहिए ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

30.03.2015/1650/sls-ag-1

श्री सुरेश भारद्वाज...जारी

जब वर्किंग सीजन शुरू होगा, अगर आप उसके बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वह मई-जून के अंत तक आएगा और उसके बाद काम बंद हो जाएगा क्योंकि बरसात शुरू हो जाएगी। इस हिसाब से ऐसा लगता है कि आप सारा पैसा खर्च नहीं करना चाहते और उस पैसे को आगे ले जाते हैं। बजट में पैसा दिखा देते हैं कि हमारी सड़कों पर, पुलों पर और मुरम्मत पर बहुत ज्यादा पैसा रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में आज हमारी बिल्डिंग्ज में भी कहीं भी मुरम्मत का काम नहीं हो रहा है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहूंगा लेकिन शिमला शहर में जितनी भी बिल्डिंग्ज हैं, उनमें कहीं पर भी मुरम्मत का काम नहीं हो रहा है। इनके पास ठेकेदार काम करने नहीं आ रहे हैं क्योंकि शायद पेमैंट नहीं होती होगी ,या फिर कोई और

कारण है। मज़दूर लोक निर्माण विभाग में हैं नहीं, क्योंकि अब आप मस्ट्रौल पर मज़दूर नहीं रख सकते। जो पक्के मज़दूर होते हैं, उनसे काम करवा नहीं सकते, इसलिए काम नहीं हो रहा है। एक मकान के कीचन के काम में नौ महीने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम कह रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। आप कहीं पर भी चले जाएं, सारे प्रदेश की यही स्थिति है। चाहे आप सिरमौर में चले जाएं, सभी सड़कें आपको कच्ची मिलेंगी। मैटलिंग टॉरिंग का तो लगता है कि शायद हिमाचल प्रदेश में बिजुमन आना ही बंद हो गया है जिसके कारण सारा काम बंद पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि शिमला शहर में न तो नाबार्ड के माध्यम से सड़कें बनती है ,न यहां पर पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़क बनती है। यहां पर छोटे-छोटे लिंक्स बनाने की आवश्यकता होती है या फिर मुख्य सड़कों की मेंटेनैंस की आवश्यकता होती है। म्यूनिसिपल कापोरेशन के पास कोई पैसा नहीं है। उनको अगर विधायक निधि या एम.पी.लैड का पैसा दिया जाए तो वह उनकी तनख्वाहों पर खर्च हो जाता है और काम नहीं हो पाता। मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि इसके लिए आप सैपेरेट कैपिटल फंड्ज किसी भी हैड में दे दीजिए। डी.सी. के पास उसको रखिए ताकि काम हो

30.03.2015/1650/sls-ag-2

सकें। जो स्पैस्फिक सड़कें बननी हैं या बिल्डिंग्ज का काम होना है, उसमें उस फंड को यूज किया जा सकता है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि शिमला शहर हिमाचल प्रदेश की राजधानी ही नहीं ,एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल है। किसी समय यह हिंदुस्तान की राजधानी रहा है। आज वर्ल्ड मैप पर हिमाचल प्रदेश को शिमला के नाम से जानते हैं, शिमला को हिमाचल प्रदेश के नाम से नहीं जानते। अगर शिमला अच्छा रहेगा और यहां लोगों को विकास दिखाई देगा ,यहां सड़कें अच्छी मिलेंगी तो यहां पर पर्यटक आएगा और पर्यटक के आने से हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या भी कम होती जाएगी। इन बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो शिमला शहर और शिमला जिला की सड़कें हैं ,उनकी ओर ध्यान दिया जाए। जो मैंने हाटकोटी से रोहड़ू सड़क

की पीड़ा व्यक्त की है ,मैं समझता हूं कि उसको देखने के लिए विधान सभा की कमेटी बना दी जाए ताकि वह वहां जाकर उस सड़क का आकलन कर सके। आकलन करने के बाद माननीय मुख्य मंत्री और इस सदन को बताए कि उस सड़क का क्या हाल है। उस सड़क पर जाने का मतलब है कि अगली बार स्पौंडेलाइटस हो जाएगा या कमर में बैक एक हो जाएगी। आज तो बरसात है। वहां जाने पर आपको आज कीचड़-ही-कीचड़ मिलेगा, गाड़ियां वहां नहीं निकल सकती। मारूति तो वहां कतई डूब जाती है। इसलिए उस सड़क पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप शिमला में विकास कर लीजिए या जो मरजी काम कर लीजिए ,माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर वह सड़क नहीं बनेंगी तो शिमला का विकास कहीं पर भी नहीं माना जाएगा। उस सड़क के बहुत बुरे हाल हैं। उसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि चाहे सी. सी. कंपनी है या और कंपनी है, उसको वॉरफुटिंग पर काम करने के लिए कहा जाए। उसको अगर मशीनरी या दूसरी चीजों की आवश्यकता है ,अगर वह देनी पड़ती है तो वह भी दी जाए। उसके लिए रूल्ज बदलने पड़ते हैं तो .. जारी...गर्ग जी

30/03/2015/1655/RG/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज-------क्रमागत

यदि कोई मशीनरी देनी पड़ती है, तो वह भी दी जाए, यदि आपको नियम बदलने की आवश्यकता हो, तो वे भी बदले जाएं। लेकिन उस सड़क को कंपलीट करें। यही आज की आवश्यकता है। इन सारी चीजों के मद्देनजर मैं लोक निर्माण विभाग के जो कार्य देख रहा हूं चाहे वह मरम्मत का काम है ,चाहे पुलों का काम है ,चाहे नेशनल हाइवेज़ या स्टेट हाइवेज़ का काम है या शिमला शहर की सड़कों का काम है उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि सारी-की-सारी विकास की गाड़ी बिल्कुल ठप्प हो गई है। मुख्य मंत्री महोदय जिस मार्ग से जाते थे, वहां सड़क बनती थी ,पूरी सड़क भी बन जाती थी , लेकिन आज तो जब मुख्य मंत्री जी भी जाते हैं, केवल गड्ढे मिट्टी से भर दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी सड़कों पर चलते हैं , शिमला में तो कभी-कभी चलते हैं, लेकिन निचले क्षेत्रों का प्रवास करते हैं और वहां की सड़कों का हाल आप स्वयं जान सकते हैं। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि इस सारी स्थिति को देखते हुए इस मांग का समर्थन करना संभव नहीं है। इसलिए मैं इस मांग संख्या 10 का विरोध करता हूं और अपना कटौती प्रस्ताव यहां रखता हूं। धन्यवाद।

समाप्त

अध्यक्ष : अब श्री बिक्रम सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे। जितना कम बोल सकें, अच्छी बात है।

श्री बिक्रम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या-10, 'लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन' पर जो कटौती प्रस्ताव आया है आपने मुझे इस पर बोलने के लिए समय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सड़कों के विषय में माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक तरफ पंजाब लगता है । जिस समय पंजाब से कोई टैक्सी या टैम्पो चिन्पुरनी की तरफ आता है, वह तलवाड़ा के बाद जिस

30/03/2015/1655/RG/AG/2

समय हमारे क्षेत्र में पहुंचता है और उसमें कोई सवारी या यात्री गहरी नींद में सोया हो, तो उसको पता चल जाता है कि हिमाचल प्रदेश शुरू हो गया। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत दयनीय है। यहां बड़ी-बड़ी सड़कों के विषय में चर्चा हुई है ,लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज श्री ईश्वर दास धीमान, श्री रिखी राम कौंडल, श्री विजय अग्निहोत्री जी इस पर बोलें हैं और अब मेरा नंबर लगा है। हम सभी लोग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है। इन 6-7 में से 5-6 तो हम लोग ही बोल रहे हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब यही है कि वहां सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। कई बार यदि इसको राजनैतिक दृष्टिकोण से देखें, तो ऐसा लगता भी है। क्योंकि वर्ष 1998 के बाद से वहां से कांग्रेस का कोई सांसद नहीं जीता। लगतार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत वहां से हो रही है और मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनीति कारणों से भी हमारे क्षेत्र में इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है। जब हम अपने विधान सभा क्षेत्रों की डी.पी.आर. की बात करते हैं ,जब से हम विधायक बने हैं तब से एक भी डी.पी.आर. आज तक नहीं बनी। प्लानिंग की मीटिंग में जाते हैं, वहां चर्चा करते हैं ,तो पूरे-के-पूरे विभाग का केवल एक ही जवाब होता है कि कुछ दिनों में आपकी डी.पी.आर्ज. बन जाएंगी, कुछ दिनों में हम इन सड़कों को क्लीयर करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में एनुअल सरफेसिंग पहले से

कम हो गई है ,हमारे यहां स्टेट फण्ड्ज के नाम से कुछ नहीं होता और कई बार तो बहुत अजीब परिस्थिति हो जाती है कि कई-कई सड़कों की जो वर्ष 2003 में हमारी प्राथमिकता पर थीं उन सड़कों की फॉरेस्ट क्लीयरैंस ही 11 साल के बाद हो रही है। उसके बाद नाबार्ड से पैसा आया है, लेकिन आज तक उसका टैण्डर नहीं हो रहा। जिस समय हम विभाग से बात करते हैं, तो विभाग की हालत भी ऐसी है। इसीलिए मैं वही कह रहा हूं कि राजनैतिक कारण इसके लिए जिम्मेवार हैं। वहां जो मेरे मित्र सत्ता पक्ष से हैं उनको पैसा भी एकदम मिलता है ,डी.पी.आर. भी एकदम बनती है और टैण्डर्ज भी एकदम लगते हैं।--------- जारी

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2015/1700/MS/AG/1

श्री बिक्रम सिंह जारी-----

टैण्डर भी एकदम लगते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप देहरा सब-डिवीजन के अन्दर जितनी भी डी0पी0आर्ज 0बनी हैं, जितने भी टैण्डर्ज हुए हैं ,उन्हें देखें। अगर आप विधानसभा क्षेत्रवाइज देखेंगे तो आप इस बात का एनालाइसिज कर सकते हैं कि जसवां-परागपुर विधान सभा क्षेत्र और देहरा विधान सभा क्षेत्र के अंदर सौतेला व्यवहार हो रहा है। यह बड़ी अच्छी बात है कि भाई रतन जी की स्पीड बड़ी तेज है। अच्छी बात है लेकिन जहां पर हमारा बनता है, वहां पर होना चाहिए। आज मैं देख रहा था ,... माननीय मुख्य मंत्री जी अधिकारियों से बातचीत में व्यस्त हो गए हैं। मैं तो इनको एक बात सुनानी चाहता था। परन्तु चलो...। जब मेरी बारी बोलने की आती है तो मुख्य मंत्री जी ऐसा ही करते हैं।

अध्यक्ष जी, अभी इस सत्र में एक प्रश्न लगा है। मैंने इनसे सात सड़कों की स्थिति पूछी है और प्रश्न के दूसरे भाग में यह भी पूछा है कि कितनी सड़कों की स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मिली है। मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि सभी सातों सड़कों के बारे में यही जवाब आया है कि फॉरैस्ट क्लीयरैंस नहीं हुई है। सातों सड़कों के बारे में यह जवाब आया है कि गिफ्ट डीड नहीं हुई है। यह बड़े दुःख का विषय है। मुझे यह बताया जाए कि कौन सा अधिकारी उस गांव के अंदर गिफ्ट डीड करने गया? मैंने जिन गांवों की बात पूछी है, मैं उन गांवों में 15 दिन या महीने में जाता रहता हूं और इस विभाग का कोई भी XEN, SDO या JE वहां नहीं गया है। उनके पास

समय नहीं है। वे कभी भी इस विषय के लिए नहीं गए हैं। अगर किसी विषय के लिए गए हैं तो मुख्य मंत्री जी जिस समय इसका जवाब दें तो यह टिप्पणी भी करें कि कौन से गांव के अंदर कौन सा अधिकारी गया है। क्योंकि अधिकारियों के पास समय ही नहीं है।

मेरे क्षेत्र के अंदर संसारपुर टैरेस एक सब-डिवीजन पड़ता है। वहां पर एक जे0ई0 राजेश कुमार जी लगे हैं। पिछले दो साल से कभी भी वह हैडक्वार्टर पर नहीं बैठे हैं। वह देहरा में रहते हैं। उन्होंने अपना हैडक्वार्टर 70किलोमीटर दूर देहरा में फिक्स किया हुआ है। मैंने इस बारे में चीफ इंजीनियर धर्मशाला से बात की थी। मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे आपके जे0ई0 को संसारपुर टैरेस में बैठना चाहिए लेकिन वह

30/03/2015/1700/MS/AG/2

देहरा मैं बैठ रहे हैं। तो उन्होंने विधान सभा लगने से एक-दो दिन पहले वहां बैठना शुरू किया है। लेकिन पिछले छः दिन से वह फिर वहां नहीं बैठ रहे हैं। मैं हररोज उनकी रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि वह क्या कर रहे हैं। इसका ऐसा विशेष क्या कारण है? उसके पीछे का विशेष कारण राजनीतिक है। आपके वहां से कोई-न-कोई फोन कर देगा कि उसको वहीं रिटेन करने दो, रहने दो लेकिन उस कारण से पूरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों के ऊपर बहुत बुरी गुजर रही है। लोगों को सड़क नहीं मिल रही है। देश आजाद हुए कितना समय हो गया है? हिमाचल प्रदेश के बारे में जिस समय चर्चा होती है तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मैंने यह भी कर दिया, वह भी कर दिया। लेकिन आप यहां बताइए कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के साथ ऐसा क्यों हो रहा है ?जहां पर काम पिछले एक या डेढ़ साल पहले काम खत्म हो जाना चाहिए था, वहां मेरी दो-तीन सड़के ऐसी हैं। स्यूल कोटला वाया बस्सी मलोट, उसका कम-से-कम छः महीने पहले समय पूरा हो गया है, वहां काम पूरा होना चाहिए था लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। जो ठेकेदार वहां पर काम कर रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। डाडासीबा लडयाला रोड,वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत यहां पैसा आया हुआ है, टाइम पीरियड पूरा हो गया है लेकिन ठेकेदार ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। इसी तरह से स्वाह से कानपुर के लिए एक सड़क बननी है उसके लिए पैसे आए हुए हैं लेकिन उसका टैण्डर आज तक नहीं हुआ। तो जो इस प्रकार के विषय हैं ,उन विषयों पर जानकारी क्यों नहीं मिलती? क्यों वहां पर काम नहीं होता? अगर आप संसारपुर टैरेस से लेकर तलवाड़ा तक जाएंगे या टैरेस से लेकर डाडासीबा तक जाएंगे तो आपको कोई सड़क नहीं मिलेगी। सड़कों की इतनी बुरी हालत है। अभी यहां

माननीय सदस्य कह रहे थे कि जहां मुख्य मंत्री जी जाते हैं वहां सड़कें पक्की हो जाती हैं । हमारे तो उल्टा हो गया। जिधर से मुख्य मंत्री जी जा रहे हैं वहां सड़कें कच्ची हो गई हैं ,वे सड़कें टूट गई हैं। अभी कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री जी वहां जाकर आए हैं। सर, आइए आप तो जा रहे हैं?(मुख्य मंत्री जी को बाहर जाते हुए पीछे से सम्बोधित करते हुए)।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बोलते रहिए।

30/03/2015/1700/MS/AG/3

श्री बिक्रम सिंहः सच्ची बात कड़वी होती है क्योंकि यहां पर सच बड़े कम लोग बोलते हैं। लेकिन चलो विभाग के लोग बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि ये यहां इन बातों के ऊपर गौर करें।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

30.03.2015/1705/**जेके/एजी**/1

श्री बिक्रम सिंहः-------**जारी**------

अभी एक प्रश्न लगा था और उस प्रश्न में माननीय अध्यक्ष जी पूछा गया था कि इंटर स्टेट कनैक्टिविटी रोड़, इंटर स्टेट कनैक्टिविटी ब्रिजिज और सी.आर.एफ. में कौन सी सड़कें हमारे विधान सभा क्षेत्र की आए? इसके दो ज़वाब आए हुए हैं। दिनांक 1.4.2013 को पी.डब्ल्यू.डी ने ज़वाब दिया। उस ज़वाब में लिखा है कि 24 जुलाई, 2012 को हमने केस भेज दिया है और उसकी स्वीकृति आने वाली है। अभी मैंने इस बार भी प्रश्न किया उसमें इन्होंने क्या ज़वाब दिया? इन्होंने उसमें अप्रैल, 2014की डेट डाली है। पहले आपने 2012 में भेजा और फिर ज़वाब 2014 में भेजा। यह देखने में अक्सर आता है कि जब पी.डब्ल्यू.डी. कहीं पर भी कुछ भेजता है उस बारे में हमने प्लानिंग की मीटिंग में भी बोला है कि जितने भी आब्जैक्शन्ज लगते है और एक बार आब्जैक्शन लगा करके आप फाईल को नीचे भेजें। मैंने अभी ई.एन.सी. साहब से भी रिक्वैस्ट की थी कि पी.एम.जी.एस.वाई. का केस इसलिए डिले हो गया कि उसमें दो महीने के अन्दर 6 बार अमैंडमैंट करनी पड़ी। क्या कारण है एक बार में अमैंडमैंट क्यों नहीं की जाती है? अगर आप एक बार में काम करेंगे तो हमें भी आपकी बार-बार रिक्वैस्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यह देखने में आया है कि हमारी सड़कों और पुलों के जो काम डिले होते हैं उसके बेसिक रीज़न यह भी है कि जो डी.पी.आर. होती है उसके ऊपर बार-बार

ऑब्जैक्शन्ज लगते हैं और वापिस आती है। मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह निवेदन रहेगा कि यहां पर टैक्निकल लोग बैठे हुए हैं। उनको मालूम है कि जिस समय सी.आर.एफ. का पैसा लगेगा या इंटरस्टेट कनैक्टिविटी ब्रिज बनेगा और जब वह ब्रिज सड़क के साथ जुड़ेगा तब वह जो सड़क है वह मेज़र डिस्ट्रिक्ट रोड़ होना चाहिए। जब तक हमारे जैसा व्यक्ति जिसको टैक्निकल नॉलेज नहीं है वह इनको चिट्ठी लिखेगा कि हम यहां पर पुल बनाना चाहते हैं लेकिन इसके पीछे जो 6 किलोमीटर की सड़क है वह मेज़र डिस्ट्रिक्ट रोड़ नहीं है। जब तक वह मेज़र डिस्ट्रिक्ट रोड़ नहीं बनेगा तब तक आप सी.आर.एफ. का केस नहीं

30.03.2015/1705/जेके/एजी/2

भेज सकते हैं यानि स्टेट कनैक्टिविटी ब्रिज का केस नहीं भेज सकते हैं। हमारा जो 20-25 साला पुराना काम करने का जो तरीका है उस तरीके को अब बदलना चाहिए। यहां पर जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने इसमें ऑब्जैक्शन किया और यहां पर बार-बार कहा है कि आप अगर वहां पर एन्वल सरफेसिंग करते हैं और वह एन्वल सरफेसिंग 15 दिन के बाद उखड़ जाती है, उसकी ज़वाबदेही कोई नहीं होती। मैंने बजट भाषण में भी बोला है और यहां दोबारा लिख कर दिया कि आपने सड़क बनाई पी.एम.जी.एस.वाई. में बठरा से समहानता। वह सड़क दो महीने के बाद उखड़ गई। अखबारों में भी आ रहा है कि वहां से जो पंचायत के प्रतिनिधि है वे भी वहां से लिख करके भेज रहे हैं और वहां का विधायक भी आपको बार-बार बोल रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सड़क ठीक नहीं की जा रही है। इसी प्रकार से पिछले वर्ष जिन-जिन सड़कों पर एन्वल सरफेसिंग हुई है वे सारी की सारी सड़कें उखड़ गई हैं। इसलिए यह ज़वाबदेही बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल सड़कों में गड्ढे इतने ज्यादा हैं वहां पर उन गड्ढों को भरने के लिए ठेकेदार से थोड़ा बहुत काम करवाया और 5 दिन के बाद वह काम वैसे का वैसा ही हो गया। मैं यहां पर पर्टिकुलरली मैंशन करता हूं, टैरेस से डाडासीबा घाटी रोड़। लेकिन जिस समय हमने बोला कि उस ठेकेदार ने किया और उस ठेकेदार की पेमैंट रोकी जाए। लेकिन ठेकेदार की पेमैंट कैसे रोकी जाएगी? उस ठेकेदार की पेमैंट तब रूकेगी क्योंकि उस ठेकेदार के वहां पर राजनीतिक क्षेत्र में लोग हैं। उनको उसने पूरा पटाया हुआ है कि हमारी पेमैंट होनी चाहिए। मेरे बोलने के बावजूद भी वह पेमैंट हो गई। एन्वल सरफेसिंग आपने जिन-जिन सड़कों के ऊपर की है उनके ऊपर भी 15 दिन के अन्दर सड़क नज़र नहीं आ रही है। मैंने मेन-मेन सड़कों के नाम लिखे हैं। अध्यक्ष जी अभी केवल बोलते हुए मुझे 11 मिनट हुए हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी 11 मिनट नहीं हुए हैं बल्कि 13 मिनट हुए हैं और अब एक-दो मिनट में खत्म करें।

30.03.2015/1705/जेके/एजी/3

श्री बिक्रम सिंहः माननीय मुख्य मंत्री जी, यदि आप बैठे होते तो मैंने बोलना ही नहीं था और 5 मिनट में खत्म कर देना था। इसलिए मुझे बार-बार रिपीट करना पड़ा है। आप यहां पर बैठो मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा। मुख्य मंत्री महोदय, ऐसा है पहले आप मुझे साथ लेकर ही जाते थे लेकिन अब आपने मुझे साथ ले जाना छोड़ दिया है। नैनपुखर से चलाली वाया नसुआ। रक्कड़ से शातला वाया बड़ौली, क्टोह,टिक्कर कोटला घाटी और टैरेस का मैंने नाम मैंशन कर दिया है। डाडासीबा से टैरेस और चिन्तपुर्णी से तलवाड़ा। कलोहा से तुतड़ू वाया डोगरी। कोटला से अमरोह सड़कों की हालत बहुत ज्यादा पतली है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

30.03.2015/1710/SS-AG/1

श्री बिक्रम सिंह क्रमागतः
सड़कों की हालत बहुत पतली है। माननीय मुख्य मंत्री जी, कारण केवल एक है कि हम काम की इवैल्यूशन नहीं करते और हम उन अधिकारियों को शाबासी देते हैं जो अच्छा काम नहीं करते। जब तक हम इस नीति से चलेंगे तब तक ये सड़कें, पुल और इनका रख-रखाव ठीक प्रकार से होने वाला नहीं है। अभी आप मेरे बिल्कुल साथ विधान सभा क्षेत्र में थानाकलां में गए। अब आपको पता नहीं है, शायद लोग बताते नहीं हैं। वहां पर एक खेल स्टेडियम है। अभी तक उसकी सीढ़ियां बनी हैं। 55 लाख रुपया उसके लिए मंजूर हुआ है। अधूरे काम का आप उद्घाटन करके आ गए। पता नहीं, आपको लोग बताते नहीं है और हमें बुरा लगता है कि हमारे मुख्य मंत्री, जिन्होंने पिछले कई सालों से कितने ही शिलान्यास कर दिए, कितने ही उद्घाटन कर दिए, उनको तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जल्दी है कि जो बना नहीं है उसका उद्घाटन कर देंगे। लेकिन वही बात आ गई। फिर मैंने पंजाबी में बोलना तो आपने नाराज़ हो जाना। आपको लोग नहीं जीने देते। जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं वे आपके साथ नहीं होते और इस प्रकार की बातें करके जो काम पूरा नहीं हुआ उसका उद्घाटन करवा रहे हैं। इसके पीछे पता नहीं क्या कारण है?

मुख्य मंत्रीः आप किस उद्घाटन की बात कर रहे हैं?

श्री बिक्रम सिंहः मुख्य मंत्री महोदय, थानाकलां में स्टेडियम बनना था। उस स्टेडियम के लिए 55 लाख रुपया मंजूर हुआ है। उसकी केवल सीढ़ियां बनी हैं और वहां आप उद्घाटन कर आए। बाकी सारा काम पड़ा हुआ है। यह मैं आपको as a well wisher बता रहा हूं। आपको किसी ने नहीं बताना। यह सभी कहेंगे कि ठीक है। मैं बताऊंगा।

Chief Minister: I have to verify your version. आप यहां खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं।

श्री बिक्रम सिंहः सर, ऐसा नहीं है। मैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर से बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा। एक गैर-सरकारी संकल्प विंटर सैशन, धर्मशाला में लगा था कि जो लिंक रोडस हैं, विधायक निधि ,एम0पी0 लैड, मनरेगा या जन-सहयोग में बनाई जाती हैं उनके रख-रखाव के लिए फंड का प्रावधान करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस समय जवाब दिया तो कहा इसमें फंड का प्रावधान

30.03.2015/1710/SS-AG/2

16-2015में किया जायेगा। लेकिन बजट बुक में कहीं ऐसा देखा नहीं गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी अधिकारियों को निर्देश दें कि अगर इस प्रकार की कमी पेशी रही है तो उसको ठीक किया जाए। मेरा एक बार फिर आपके माध्यम से निवेदन है कि यह विषय बार-बार आता है क्योंकि मेरे क्षेत्र के अंदर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडस बहुत कम हैं तो मैं चाहूंगा कि जिन-जिन सड़कों के साथ पुल बनने हैं, इंटर-स्टेट ब्रिजिज़ बनने हैं वहां पर उनको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडों के साथ जोड़ा जाए। जो सड़कें लम्बे समय से चल रही हैं, जिनके ऊपर वाहन चल रहे हैं, बसें चल रही हैं लेकिन कुछ लोगों के द्वारा गिफ्ट डीड नहीं किया जा रहा। जितनी उसकी रिक्वायर्ड विडथ है उसके ऊपर काम किया जाए। कई बार गांव के अंदर लोगों को बोला जाता है कि आप इसको रहने दो, बाद में आपको मुआवजा मिलेगा। यहां पर ऐसी स्थिति है। जितनी उसकी रिक्वायर्ड विडथ है उसके ऊपर काम किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, जो मांग-10 हमने यहां पर रखी है मैं चाहूंगा कि जिन-जिन विषयों के ऊपर हमने अपने सुझाव दिए हैं उन सुझावों को इम्प्लीमैंट करने में विभाग ध्यान दे। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

30.03.2015/1710/SS-AG/3

अध्यक्षः इस मांग संख्या पर श्री महेश्वर सिंह जी की भी बोलने के लिए रिक्वैस्ट आई है। मैं चाहूंगा कि वे पांच मिनट के अंदर अपनी बात रखें। इस मांग पर बोलिये।
श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। --(व्यवधान)—

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। कटौती प्रस्ताव पर जिसने कटौती प्रस्ताव दिया हो, उसी सिक्वैंस में वह बोलता है। अगर अध्यक्ष जी की यह रूलिंग है कि बिना कटौती प्रस्ताव के भी कोई बोल सकता है तो हमारे भी कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। जिस विषय पर हम नहीं बोलना चाहते कुछ और लोग बोलना चाहते हैं उनको भी एलाऊ किया जाए।

अध्यक्षः कटौती प्रस्ताव के साथ-साथ मांग भी आई है।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, हमारे को भी एलाऊ किया जाए। --(व्यवधान)-

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक कटौती प्रस्ताव का संबंध है, यह सही है कि जो कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करेंगे उनको प्राथमिकता मिलेगी। जहां तक चर्चा का संबंध है, चर्चा में भाग लेना हमारा अधिकार है। --(व्यवधान)—

अध्यक्षः आप बताईये कि क्या आप कटौती प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं या वैसे ही बोलना चाहते हैं? --(व्यवधान)--

जारी श्रीमती के0एस0

/1715/30.03.2015केएस/एजी/1

अध्यक्षः महेश्वर सिंह जी, आप कटौती प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं या ऐसी ही कोई आपकी मांग है?

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव पर जब चर्चा चली है तो ये किस चीज़ पर बोलेंगें?

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जो लोकसभा में भी थे। कटौती प्रस्ताव सदस्य देते हैं और वे उसी पर चर्चा करते हैं लेकिन उसके बाद चर्चा में भाग लेने का अधिकार है और आपने मुझे समय दिया, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार जब बजट सत्र चल रहा था, इन्होंने बहिष्कार किया। तो इसका अर्थ यह तो नहीं था कि मांग पर कोई चर्चा ही नहीं हो सकती और उस चर्चा में मैंने आपकी कृपा से भाग लिया है। मैं इनके कटौती प्रस्तावों का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हूं ।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय ,हमें कोई एतराज़ नहीं है, महेश्वर सिंह जी अपनी बात रखें। आप इनको भी समय दीजिए क्योंकि हमने कटौती प्रस्ताव दिए हैं और आपने खुद रूलिंग दी है कि जिसके नाम से कटौती प्रस्ताव आए हैं वे ही बोलेंगें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल उठा है, मेरा यह अनुभव है कि जब कट मोशन होते हैं, जिन्होंने कट मोशन के लिए नोटिस दिया होता है, वही इसमें बोलते हैं और उसके बाद the issue is closed and matter is put to vote. कट मोशन के बाद कोई जनरल डिस्कशन नहीं हो सकती। The stage has gone. The stage of general discussion is

/1715/30.03.2015केएस/एजी/2

over. Now, they are Cut Motions and only the people who have given notice to the Cut Motions, they can participate.

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, हम भी यही कह रहे हैं।

Speaker: That is why I am asking Shri Maheshwar Singh are you speaking on Cut Motions or something else.

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, मुझे कुछ सुझाव देने हैं। इन्होंने भी तो अपनी बातें कही।
श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने भी स्पष्ट कर दिया और यह हाऊस उनके आदेश के मुताबिक चलता है।

अध्यक्ष :कौंडल जी, कृपया आप बैठ जाएं। मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।
मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, या तो महेश्वर सिंह जी को जनरल डिस्कशन में भाग लेना चाहिए था मगर अब वह स्टेज खत्म हो गई है। Now, we are going towards voting. और यह कट मोशन पर जिसने नोटिस दिया है, उनको ही बोलने का अधिकार है।

Speaker: He is right. I thought you are speaking on Cut Motions also. If you are not speaking, time will not be given to you. मांग संख्या-10 पर कटौती प्रस्ताव पर श्री ईश्वर दास धीमान जी और बाकी मैम्बर्ज़ ने चर्चा की है। अब इसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री देंगें।

/1715/30.03.2015केएस/एजी/3

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-10 जो लोक निर्माण-सड़क पुल तथा भवन से सम्बन्धित है, के बारे में जो चर्चा हुई है, उसका उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस चर्चा में श्री ईश्वर दास धीमान, श्री रिखी राम कौंडल, श्री विजय अग्निहोत्री, श्री सुरेश भारद्वाज और श्री विक्रम सिंह ने भाग लिया। इन्होंने अपनी बातें रखी है और मैं समझता हूं कि बहुत सी जो बातें हैं वे बढ़ा-चढ़ा करके की गई हैं। यह बताने की कोशिश की गई है कि इनके कार्यकाल में ज्यादा सड़कें बनी थीं, ज्यादा मैटलिंग-टारिंग हुई थी और हमारे दो साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हो रहा है लेकिन यह सच्चाई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, keeping in view the geographical conditions and negligible availability of other transport facilities, roads play an important role in the development of our State. The Government has always been giving top priority to the construction, repair and maintenance of the roads and it has

been the policy of the Government to allot more funds for the construction of roads, bridges and buildings.

Continued by AG in English . . .

30032015/1720/ AG/1

Hon. CM Continues . . .

During the financial year 2015-2016, budget provision (General Plan, SCSP, TASP and BASP) of Rs. 884.20 crores has been made for the construction of roads, bridges and buildings and procurement of machinery which is 8.20 per cent more than the budget for the previous year. These figures indicate that the Government is giving priority to this sector and particularly focussing on works of roads and bridges.

The present Government is committed to connecting every Gram Panchayat with roads. There are 3243 Panchayats in the State out of which 3117 have already been provided road connectivity. Now, only 126 panchayats are to be linked with roads, for which a special budget provision of Rs. 6.18 crores has been proposed during the financial year 2015-2016. The criteria for the allotment of the budget for the construction of the roads is as under:

Attaining increase in road length throughout the State thereby increasing the road density. The present density of the roads in the State is about 60.72 km per 100 Sq. kms of the area.

Many Members also mentioned about the bridges, I would like to say that the Demand for financial allocation for construction of bridges is huge. In view of the limited financial resources of the State, these construction activities can only be carried out in a planned and phased manner.

30032015/1720/ AG/2

At present, we have 1903 number bridges in the State and the Government intends to construct 24 bridges during the next financial year 2015-2016 with an allocation of Rs. 15.25 crores.

I would like to mention here that 632 kms road length was declared as National Highways during 2014-2015 and now the State has a length of 1783 kms as National Highways and estimate of Rs. 508 crores under National Highways appeared during the current financial year. Estimate of Rs. 286 crores appeared for National Highway - 38 - Shimla-Mator and Section between Kandrori-Hamirpur will be widened and 11 bridges would be made double lane and these are some of the works which are underway.

Mr. Speaker, Sir, I would also like to say that mention has been made about the maintenance of the roads. This year particularly we have a very bad weather, whether it is during the winter, during the spring and now summer has started and even now we are not get rid of rains. With torrential rains, the roads get damaged and the repair and re-metaling work cannot be taken under these climatic conditions.

Continued by AG in English . . .

30.03.2015/1725/negi/ag/1

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा... जारी...

But we have been able to repair the roads. I think many Members say कि बिल्कुल सड़क की हालत बहुत खराब है । वहां पर रोडी नही पड़ती, मिट्टी से गड्ढे भरे जाते हैं I This is exaggeration and I do admit may be many roads are repaired and due to climatic conditions they get damaged and they require re-repairs and that process has to go on. I have instructed the PWD Department so many times then whenever you do repair work, it should be done in a manner that the work of repair hold good for a long period time. But this has

happened many times. I remember once when Dhumal Sahib was the Chief Minister, I along with some friends was coming by road from Ghagas to Namhol. The road from Ghagas to Namhol was being re-metalled and the re-metaling process was about to reach Ghagas, only one kilometre was more to reach Ghagas. What we saw that the remetaling work was in place by the contractor and behind that from Ghagas there were some workers who were filling the potholes. The road was black. It had been just metalled. मगर पीछे क्या हो रहा था कि कुछ लोग पीछे से गड्ढे भरते हुए जा रहे थे । अभी रोड़ बनी थी I What shocked me more was I asked them who you are, they say, Sir, we belong to PWD. हम गड्ढों को भर रहे हैं। मैंने कहा, आपका काम तो नहीं है गड्ढे भरना । अभी सड़क पक्की होती जा रही है, मैटलिंग हो रही है और ठेकेदार अभी नम्होल नही पहुंचा है और पीछे से आप लोग उस सड़क पर गड्ढे भरते जा रहे हैं। So, lapses do take place. I don't say that exception can be a rule. But the department has to be very cautious about these things and quality of work is there. Personally, I don't care whom the contract is granted and whosoever is the contractor must perform his job properly and if he does not do work according to the norms and does a shabby work, I think such people

30.03.2015/1725/negi/ag/2

should not be given contract again. They should be blacklisted by the department so that the work is done properly. Few months back, I had an opportunity to visit Chopal for three-four days. There I found and I was told by the people that one contractor had awarded contract totalling Rs. 40 crores but he done nothing. This type of work cannot be tolerated whether it is in Chopal, whether it is in Rohroo, whether it is in Rampur, Una, Chamba, Kangra or anywhere else. We must see that proper type of contract is given and those who do good work should be encouraged and those who do shabby work should be shunted out and should be debarred from taking Government contracts in the future. We cannot be a party to their wrong doings.

Shri Inder Singh: Who will ensure that the job is done properly?

Chief Minister: I ask the department to do it. It is my duty not only as Chief Minister but also as a Minister of Public Works Department and if it still happens, this is intolerable. Similarly, Sir, mention was made of Baghsal Bridge by Hon'ble Member, Shri Rikhi Ram Kaundal.

श्री रिखी राम कौंडल : सर, आप मेरा नाम भूल गए।

मुख्य मंत्री : बात यह है कि आप इतनी दूरी में रहते हैं कि शक्ल तो याद रहती है मगर हम नाम कभी भूल जाते हैं।

कौंडल साहब ने यह कहा कि he is pained about it so am I.

श्रीमती यू.के. द्वारा जारी...

30/03/2015/1730/यूके/एजी/1

मुख्य मंत्री---जारी ---
बड़े शौक साथ लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उस इलाके की सही मांग को ध्यान में रखते हुए इस पुल को हमने मंजूर किया है और कुछ वर्षों पहले 24- 25करोड़ रूपए का इस पुल के लिए धनराशि मंजूर हुई है । सारे काम, गेबन कम्पनी जो कि एक मशहूर कम्पनी है, पुल बनाने के क्षेत्र में, उस को दिया गया । डिजाईन भी उन्होंने ही किया और उन्होंने इसको बनाया । मगर बाद में कहा गया कि जिस जगह यह पुल बन रहा है वह साईट ठीक नहीं है । अब हमने फैसला किया है कि साईट को बदला जाए । हम उस कम्पनी के खिलाफ आरबिट्रेशन में जाएंगे, ऐक्शन लेंगे । मगर हम आरबिट्रेशन के नतीजे का इन्तजार नहीं करेंगे । साइमलटेनियसली, साथ-साथ हम दूसरे पुल का निर्माण करेंगे ताकि वहां लोगों को सुविधा मिल सके । वह बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है । वहां यदि वह पुल बन जाता है तो कोटधार से स्वारघाट तक जाने के लिए बहुत कम फासला रह जायेगा । वरना उनको बहुत लम्बा चक्कर काट कर आना पड़ता है ,यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है । इसी तरह से और भी कई पुल बनाए जा रहे हैं । मैने नेश्नल हाईवेज़ के बारे में भी कह दिया है कि इसी एक वर्ष के अन्दर कितने और मेन नेश्नल हाईवेज बढ़े हैं । बाकी जो भी पुल है चाहे छोटा है या बड़ा है, प्रदेश के चाहे किसी भी

हिस्से में हैं वह महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे यातायात में सुधार होता है ,फासले कम होते हैं । सड़कों की तरह जो पुल बन रहे हैं उनको भी हमारी सरकार की तरफ से टॉप प्रायोरिटी मिलेगी और जितने भी पुल बन सकते हैं, तेजी के साथ बनाएंगे । और हम यह कहना चाहेंगे कि दो साल के अन्दर जो काम हुआ है उतने पुल पिछले 5 सालों में नहीं बने हैं । I have got name of those bridges but I don't want to waste the time of the House by giving or reading of the list of the bridges. और सड़कों का काम भी तेजी के साथ चल रहा है । मगर मौसम की खराबी की वजह से बीच-बीच में सड़कों की मरम्मत और उनके रख-रखाव में कमी आयी है और मैं चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग को भी मैं यहां खड़े हो कर इस सदन से कह रहा हूं कि पहले जो बनी हुई सड़कें हैं जहां उनका रख-रखाव करना है उसके साथ-साथ उसी प्राथमिकता के साथ नयी सड़कों का निर्माण करना है । । I don't want to score any point on this issue. और यहां पर आज हमारी सड़कों की फोर-लेनिंग तथा थ्री-लेनिंग हो रही है, बृजिज़ बन रहे हैं, बड़े पैमाने पर काम हो रहा है ।

30/03/2015/1730/यूके/एजी/2

अंत में भारद्वाज साहब ने बात की, ठियोग, हाटकोटी-रोहड़ू सड़क के बारे में। यह सचमुच में यह मेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए एक दुख का विषय बन गया है। यह तो ऐसी बात हुई कि एक मुसीबत से निकले और दूसरी मुसीबत में फंस गए । पहले एक चीनी कम्पनी को काम दिया गया और इतना मैं कह सकता हूं कि जितना भी काम उन्होंने किया, आज तक भी वह खड़ा है, ठीक ढंग से हुआ है । मगर किसी कारणवश उन्होंने काम करने से इन्कार कर दिया । It was a semi Government Company of the Chinese Government.और किसी वजह से उन्होंने ड्रॉप कर दिया और उसके बाद रिटेंडरिंग हुई है । रिटेंडरिंग के बाद ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

30.03.2015/1735/sls-ag-1

माननीय मुख्य मंत्री ... जारी

री-टैंडरिंग के बाद जो उसका प्रोसैस है, उसकी स्वीकृति वर्ल्ड बैंक से मिलती है। फिर एक दूसरी कंपनी को काम दिया गया जो सी.सी. कंपनी नाम से है - चड्ढा एंड चड्ढा

कंपनी। इस सड़क के दो हिस्से थे। एक ठियोग से लेकर खड़ा पत्थर और दूसरा खड़ा पत्थर से रोहड़ू तक। अच्छा होता अगर दोनों हिस्से अलग-अलग ठेकेदारों को दिए जाते। तब उनमें आपस में कंपीटिशन होता और काम भी जल्दी से होता। मगर किसी कारण वह एक ही आदमी को दिए गए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं whatever the department may say, I am not satisfied with the working of this company. अच्छी कंपनी होगी, तजुर्बेकार कंपनी होगी, लेकिन इस सड़क में हम जो उम्मीद करते थे कि जिस तेजी के साथ काम होगा, जिस दक्षता के साथ काम होगा, जिस प्रोफैशनलिज्म के साथ काम होगा, वह नहीं हुआ है जिसकी वजह से सड़क का कार्यक्रम, उसका प्रोग्राम पीछे रह गया है। हम कोशिश करेंगे; वैसे तो 2016 तक उनका टाईम है, मगर उससे पहले-पहले यह सड़क अच्छी तरह से बने। उसके अलावा आलटरनेटिव रूट, जिसका ज़िक्र अभी भारद्वाज जी ने किया कि टिक्कर, खदराला, बागी और नारकण्डा होते हुए वाहनों को वहां से निकाला जाए। वह सड़कें बहुत अच्छी हालत में थीं लेकिन क्योंकि वहां से ट्रैफिक आनी शुरू हो गई, इसलिए उनकी भी और ज्यादा मुरम्मत करने की ज़रूरत है। इसलिए सेव सीजन से पहले-पहले इन सड़कों को रिपेयर किया जाएगा ताकि ट्रैफिक आसानी से उनके द्वारा चलती रहे और जो सेव उत्पादक हैं उनको अपने सेवों के निकास में किसी प्रकार की बाधा न आए। मगर यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जो मेन सड़क है, वह जल्दी-से-जल्दी बने , according to specifications बनें। उसमें किसी किसम की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह मैं आपको कहना चाहूंगा। I have also lost my patience on this road बाकी बहुत-सी बातें हैं।

30.03.2015/1735/sls-ag-2

जो स्थानीय सड़कों और पुलों के बारे में बात की, I am writing to each and every Member who have participated in the debate about the issues raised by them. Thank you, Sir.

मैं उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने यह कट मोशन मूव किए हैं, उनसे मैं यह अनुरोध करूंगा कि वे मेरे इस उत्तर के दृष्टिगत अपने कट मोशन वापिस लें।

अध्यक्ष : क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगे?

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, माननीय धीमान जी ने कुछ विषय रखे, बिक्रम सिंह जी ने भी कुछ बातें रखीं, मैंने भी 7-8 बातें रखीं और उनमें से केवल एक बात यानी बग्छाल पुल का ज़िक्र किया गया; इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस उत्तर में हमारी बातों का कोई जवाब नहीं आया and we are not satisfied with the reply of the Hon'ble Chief Minister इसलिए हम अपने कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं करेंगे।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री ,सुरेश भारद्वाज एवं बिक्रम सिंह ने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए?

(कटौती प्रस्ताव अस्वीकार।)

प्रस्ताव गिर गया।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या 10 'लोक निर्माण - सड़क, पुल एवं भवन' के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजी के निमित्त क्रमशः 24,46,71,39,000/- तथा 8,90,26,30,000/- रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से दे दी जाएं?

30.03.2015/1735/sls-ag-3

(प्रस्ताव स्वीकार।)
मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या 10 'लोक निर्माण - सड़क, पुल एवं भवन' के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजी के निमित्त क्रमशः 24,46,71,39,000/- तथा 8,90,26,30,000/- रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से दी गईं।

अगली मद ..गर्ग जी

30/03/2015/1740/RG/AG/1

अध्यक्ष-------क्रमागत

अब हम मांग संख्या-9, 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' को लेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को वर्ष 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-9-'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' के अन्तर्गत राजस्व व पूंजी के निमित्त क्रमशः धनराशियां मु.15 ,07,31,63,000/- रुपये(राजस्व) व मु. 51,54,00,000/-रुपये(पूंजी) संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इस पर सर्वश्री ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल ,विजय अग्निहोत्री ,सुरेश भारद्वाज व श्री बिक्रम सिंह जी की ओर से तीन कटौती प्रस्ताव आए हैं। क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं या उनकी ओर से प्रस्तुत हुआ समझूं?

माननीय सदस्यगण : इन्हें प्रस्तुत हुआ समझा जाए।

अध्यक्ष : तो सर्वश्री ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, सुरेश भारद्वाज व श्री बिक्रम सिंह जी की ओर से इनके कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए जो इस प्रकार हैं:-

(कटौती प्रस्ताव लगना है)

30/03/2015/1740/RG/AG/2

अब मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध हैं। अब श्री ईश्वर दास धीमान जी अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्री ईश्वर दास धीमान : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-9',स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ है, तो प्रदेश एवं देश भी स्वस्थ है। लेकिन अगर विभाग ही अस्वस्थ होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश का क्या हाल होगा? हमारी प्राथमिकता सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की रही है। आपकी तो प्राथमिकता ही कोई नहीं है। इसलिए यह विभाग भी स्वस्थ नहीं है। ठीक

है कि इसका ढांचा तो सारे प्रदेश में है। मैडिकल कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज ,डिस्ट्रिक्ट हॉस्पीटल्ज, सिविल हॉस्पिटल हैं ,सी.एच.सी. और अन्य स्वास्थ्य केन्द्र हैं। पहले तो आपने बहुत थोड़े से अर्से में सात सी.एच.सी. से सिविल हॉस्पीटल बना दिए और दस आपने सी.एच.सी. बना दिए ,लेकिन न तो किसी में स्टाफ दिया ,न ही इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया और न ही उनमें कोई सुविधा दी। इनके नॉर्म्ज तो बनाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं इनमें नॉर्म्ज के मुताबिक क्या है? इसके अतिरिक्त यह भी किसी को नहीं पता कि ये 50, 100 या 150 बैडिड हैं। लेकिन अगर यह ढांचा है, तो आपने बहुत जल्दी की है। हॉस्पीटल तो बिना स्टाफ एवं बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के चल हीं नही सकते। शिक्षा संस्थाएं तो कुछ समय के लिए चलाई भी जा सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य संस्थान नहीं चलाए जा सकते। यह ढांचा जो प्रदेश में बना हुआ है ,तो अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं कह रहे थे कि लगभग 300 मैडिकल ऑफिसर्ज की कमी है ,सुपर स्पेशलिस्ट की बात ही न करो, यहां तो इनके पास पूरे मैडिकल ऑफिसर्ज ही नहीं हैं। ये ही स्वयं यह बात कहते हैं और इस चीज को समझते भी हैं। स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य संस्थाओं में बहुत परेशानी है----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2015/1745/MS/AG/1

श्री ईश्वर दास धीमान जारी-----

तो स्टाफ की कमी की वजह से स्वास्थ्य संस्थानों में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहीं पर मेडिकल ऑफिसर्ज की जगह फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं और कहीं पर फार्मासिस्ट भी नहीं है तो उसकी जगह पर चपड़ासी काम कर रहा है। अच्छा नहीं लगता है और कम-से-कम PHC से लेकर ऊपर तक डॉक्टर्ज का होना बहुत आवश्यक है। आपने सब-सेंटर्ज खोले हैं। क्या कभी आपने एम0पी0डब्ल्यू0 को चैक किया है ?बहुत दिनों के लिए कोई होता ही नहीं है। यह ठीक है कि सुबह कोई और है और शाम को कोई और है। पूछो तो कहते हैं कि क्षेत्र में है। जिसने क्षेत्र में जाना है, वे कह रहे हैं कि वहां सी0एच0सी0 में है।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

इसी तरह की शिकायतें आ रही हैं। गांव में यह आम बात है कि सब-सेंटर्ज में जितने भी एम0पी0 डब्ल्यू0 किसी भी सूरत में लगे हैं ,वे वहां पर मिलते नहीं हैं। वहां भी कई बार क्लास-फोर ही दवाइयां बांटते हैं। यह भी इस महकमे में एक बहुत बड़ी बात है।

अगर स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों की बात करें तो मुझे लगता है कि कुछेक सब-सेंटर्ज ऐसे हैं जहां पर अपने भवन नहीं हैं। विभाग ने किराये पर भवन ले रखे हैं। यहां तक की पी0एच0सीज0 में भी भवनों की बड़ी कमी पाई जाती है। अगर PHC या CHC के अपने भवन नहीं हैं, तो ये कैसे चलेंगी? यह भी देखने की बात है। अभी जैसे मैंने स्टाफ की भी बात कही है। कृपया एक तो डैपुटेशन के सिस्टम को बन्द कीजिए। इससे बहुत नुकसान होता है और मरीज को कोई फायदा नहीं होता। जब एक जगह पर स्टाफ नहीं होता तो दूसरी जगह से आप स्टाफ उधर भेज देते हैं जिससे न तो पिछले अस्पताल में काम होता है और न ही अगले में जहां पर भेजा होता है, वहां काम होता है। डैपुटेशन से बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। समझ में नहीं आता जब आपके पास ट्रेंड नर्सिज हैं, चाहे आर0के0एस0 में है या कहीं और हैं तो आउटसोर्सिंग क्यों किया जा रहा है? आप आर0के0एस0 में ट्रेंड नर्सिज को रखिए। अगर उनको रखेगें तो रोजगार वाली बात भी हो जाएगी और आगे जाकर सेवाएं भी

30/03/2015/1745/MS/AG/2

ठीक मिलेंगी और खर्च भी कम होगा। यदि कहीं पर ट्रेंड लोग आपके पास नहीं हैं तो आउटसोर्सिंग कीजिए परन्तु जब उपलब्ध है और उसके बावजूद भी आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो यह सही नहीं है। तकनीकी स्टाफ को बहुत से अस्पतालों में आउटसोर्स किया है। खासकर यहां आई0जी0एम0सी0 में जो लोग स्टाफ के थे या जैसे पहले काम चलता था, वह आपने बन्द कर दिया और आउटसोर्स करके विभाग के ऊपर और बोझ डाल दिया। यह आउटसोर्स वहां पर कीजिए जहां पर कोई अलटरनेटिव नहीं है लेकिन जहां अलटरनेटिव है, वहां मत कीजिए। एमरजैंसी सेवाओं के लिए मैं समझता हूं कि विजीलैंस की आवश्यकता है और जो भी आपकी एमरजैंसी सेवाएं हैं ,आपके जिला में जिला अस्पताल दीन दयाल उपाध्याय है। यहां पर मरीज को चैक करने का सामान नहीं है। एक्स-रे नहीं है। रेडियोलोजिस्ट नहीं है। यहां दो घण्टे इंतजार करने के बाद अगर आई0जी0एम0सी0 में जाते हैं तो वहां लाइट नहीं है। अगर एक्स-रे करने के लिए इतनी एडवांस स्टेज में अगर तीन घण्टे लग जाएं,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

30.03.2015/1750/जेके/एजी/1

श्री ईश्वर दास धीमानः------जारी------

एक्सरे करने के लिए इतनी एडवांस स्टेज में अगर किसी मरीज को तीन घण्टे लग जाएं तो मुझे नहीं लगेगा कि वह बचेगा। यह बातें आपके लिए छोटी हैं लेकिन मरीज के लिए तो जान और मौत का प्रश्न बनता है। ये लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के लिए ठीक नहीं है। जो वहां पर अवेलेबल स्टाफ है वह कम से कम अपनी ड्यूटी पर रहे। खास करके जब वर्किंग डे होता है, एमरजैंसी होती है उसमें जो पैरा मेडिकल स्टाफ है वह ठीक ढंग से काम करे। आर.के.एस. से पी.डब्ल्यू.डी. को पैसा काम करने के लिए दे रखा है। रोगी कल्याण समिति में कुछ निर्माण करने के लिए आपने पी.डब्ल्यू.डी. के पास पैसा जमा करवा रखा है। वहां पर काम ही नहीं हो रहा है। उसकी देखभाल कौन करता है? उसके मापदण्ड क्या हैं? उसकी सुपरविज़निंग कौन करता है?अगर उसकी देखभाल नहीं है ,सुपरविजन नहीं है और पी.डब्ल्यू .डी. काम नहीं कर रहा है तो किसी दूसरी एजैंसी को काम दीजिए। मैं समझता हूं कि यह तो पैसे का दुरूपयोग है। ग्रांट-इन-एड आर.के.एस. को समय पर नहीं मिल रही है। 6-6 महीने से इन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही हैं। जितना भी आपने कॉन्ट्रेक्चुअल आधार पर स्टाफ रखा है उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। जो आर.के.एस. का सिस्टम है वह इस लापरवाही की वजह से ग्रांट-इन-एड समय पर न मिलने की वजह से और लोगों को तन्ख्वाहें न मिलने की वजह से यह सारे का सारा काम तबाह हो रहा है। अगर 6-6 महीने से सैलरी न मिलें तो आप सोच सकते हैं कि उनकी हालत क्या होगी? ये जो संस्थाएं आपने खोली हैं कुछ नॉर्म्ज के अन्तर्गत ही खोली हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज में जब भी आपकी मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया की टीम आती है तब आप उधार ले करके डॉक्टर्ज को खड़ा कर देते हैं या कोई दूसरा जुगाड़ कर देते हैं। इस तरह से आप इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी करते होंगे। यह कब तक चलेगा? आप जब सशक्त हो रहे हैं अब नहीं लगता है कि यहां के एम.बी.बी.एस. का भविष्य अधर में लटक रहा है। अगर वहां से मान्यता नहीं मिलती है तो आप लोगों को इसका पहले से ही प्रबन्ध करना चाहिए। इस तरह का सिलसिला आपका होता ही रहा है। जब यहां पर मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया

30.03.2015/1750/जेके/एजी/2

की टीम आती है तो टांडा से स्टाफ मंगवा लिया जाता है। टांडा में यदि टीम आ जाए तो यहां से स्टाफ मंगवा लिया। कहीं से स्टाफ उधार ले लिया और कहीं से जुगाड़ कर लिया। इसलिए आज यह मुसीबत पड़ी है कि यदि इसको पूरा नहीं करेंगे तो आपकी मान्यता खतरे में है। मैं तो समझता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से ले करके किसी न किसी तरीके से बच्चों के भविष्य को बचाने की आवश्यकता है। अब एम.बी.बी.एस.के बच्चे कड़ी सलैक्शन के बाद टेलेंटिड बन कर आते हैं। लेकिन आपके पास लाईब्रेरी ही नहीं है। लाईब्रेरी जहां 200 लोगों को चाहिए वह 120 लोगों को भी नहीं है। आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। आपके पास लेबोरेटरीज़ नहीं है। जब तक इन सारी शर्तों को आप पूरा नहीं करोगे तब तक मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया आपको कहां मान्यता देगी? बार-बार यह मामला यहां पर उठता है। बार-बार यहां पर बच्चों को कितनी परेशानी होती होगी और पेरैंट्स को कितनी परेशानी होती होगी? इन बातों का ध्यान माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय रखेंगे ताकि बच्चों को कोई तकलीफ न हो।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

30.03.2015/1755/SS-AG/1

श्री ईश्वर दास धीमान क्रमागतः

बच्चों को कोई तकलीफ न हो, इस करके अति आवश्यक है कि स्टाफ की पूर्ति की जाए और ठीक-ठीक वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्प किया जाए। आपका बहुत-सा ऑपरेटस है, बहुत-सी मशीनें हैं, चाहे वे आई0जी0एम0सी0 में हैं या टांडा में हैं बेकार पड़ी हुई हैं। उनको चलाने वाले टैक्निशियन नहीं हैं। स्टडी करने वाले डॉक्टर नहीं हैं। इसका ध्यान किसने रखना? वह ध्यान आपने रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो स्थिति खराब हो जायेगी। यह विभाग अति संवेदनशील है। मनुष्य के स्वास्थ्य का कोई पता नहीं लगता कि कब खराब हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ठीक नहीं होगा। अगर किसी प्रदेश का नौजवान स्वस्थ नहीं होगा, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी नहीं होंगी तो प्रदेश को आगे चलने में कठिनाई आयेगी। खेलों में ही देख लीजिए। खेलों में जब बच्चे जीत कर आते हैं तो वे वही बच्चे होते हैं जो स्वस्थ होते हैं। ड्रग्ज़ वगैरह पर कंट्रोल भी आपके अधीन है इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे करके अगर आप बच्चों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो अच्छा रहेगा।

आप नेशनल हैल्थ मिशन का पूरा फायदा नहीं उठा सके। आपके जितने भी प्रोजैक्टस बने, उसमें कुछ कामयाब हुए और कुछ कामयाब नहीं हुए। कुछ ड्रॉप करने

पड़ते हैं। उस मिशन का शत-प्रतिशत फायदा नहीं उठाया जा रहा। उसको भी उठाने का आपका प्रयत्न रहे। मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि अगर आपका स्टाफ पूरा हो जाए, अगर आपको टैक्निकल या पैरा-मेडिकल स्टाफ पूरा मिल जाए तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं। आपके भवनों की हालत, आपकी लैबोरेटरी की हालत सुधर जाए, टैक्निशियन वगैरह मिल जाएं तो मैं नहीं समझता हूं कि यहां पर बहुत ज्यादा कमी स्वास्थ्य विभाग में रहेगी। आपने प्रयत्न किया है, हर सरकार प्रयत्न करती है जब भी आती है लेकिन उन प्रयत्नों में बहुत कमी आ गई है जो पिछली सरकार किया करती थी। आप उस गति को पकड़ें।

अब नेशनल तौर पर स्वच्छता का मिशन चला। सबसे पहली बात स्वच्छता है। स्वच्छता अगर होगी तो ही जाकर आप स्वस्थ रह सकेंगे। स्वच्छता लाने के लिए भी विभाग को अपने तरीके से कोई-न-कोई काम करना चाहिए ताकि आपके विभाग द्वारा भी यह मिशन गांव तक पहुंचे। इसके लिए कुछ लोगों को मदद भी मिले। अगर स्वच्छता के अभियान को आप राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तर पर कामयाब कर देते हैं तो

30.03.2015/1755/SS-AG/2

वह आपके स्वास्थ्य विभाग को मदद करेगा। जितने मरीज कम होंगे आपका काम अच्छा रहेगा।

अब स्वाईन फ्लू की बात थी। नेशनल स्तर पर तो बड़ी भारी मौतें हुईं। आपके यहां आपने काम सम्भाला लेकिन अगर आप और भी पहले सतर्क हो जाते तो 20 मौतें भी नहीं होतीं। आने वाले समय में कौन-सी कैसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए उसके लिए विभाग को थोड़ा तैयार भी रहना चाहिए। आपके पास एक्सपर्टस भी होने चाहिएं। यह तो हमारी समझ में नहीं आया कि इतनी देर से आपका मेडिकल कॉलेज, शिमला चल रहा है तो क्या यहां पर बाईपास सर्जरी बंद हो गई? यह भी सारे प्रदेश में बात है कि यहां पर ऑपरेशन बंद हो गए। आपने जवाब में भी दे रखा है। मिसलीड करने की कोशिश न कीजिए। अगर कोई ऐसी बात है तो कह दीजिए कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। हम यह कह नहीं सकते। लेकिन नॉर्म्ज़ हैं। आपने बनाएं। आपने दिए। ये सी0एच0सीज़0 के भी हैं और सिविल हॉस्पिटल के भी हैं तो उसमें 24 पोस्टें हैं। मैं लम्बी बात नहीं करूंगा।

जारी श्रीमती के0एस0

30.03.2015/1800/केएस/एजी/1

श्री ईश्वर दास धीमान जारी---
मैं लम्बी बात नहीं करूंगा ,16 पोस्टें जो ऐड हुई हैं और 16 की जगह अगर आप 2 पोस्टें देंगें तो आपत्ति तो होगी और लगता है कि उसमें भेदभाव भी होता होगा। इसमें लगता है कि आप कोई राजनीति भी खेलते होंगें। मेरे प्रश्न के उत्तर में जो आपने कहा है मैं उस बारे में ही बोल रहा हूं और आप जब मुझे दूसरे ढंग से संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो ठीक नहीं लगता। जिम्मेवार आदमी के लिए जिम्मेवार बात ही करनी चाहिए। कुल मिलाकर ठाकुर साहब आपके विभाग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर आप अपने विभाग का स्वास्थ्य ठीक रखेंगें तभी प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक होगा । आप कोशिश करते हैं, हमें इस बात का विश्वास है लेकिन वह कोशिश पूरी कोशिश नहीं होती, अधूरी कोशिश होती है । यह लोगों की जान बचाने का एक विभाग है, अति आवश्यक है और किसी भी प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का चुस्त-दुरुस्त होना जरूरी है और अगर किसी प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग चुस्त-दुरुस्त होगा तो उस प्रदेश के नागरिक भी चुस्त-दुरुस्त होंगे और फिर प्रदेश आगे बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

30.03.2015/1800/केएस/एजी/2

उपाध्यक्षः अब श्री रिखी राम कौंडल जी, चर्चा में भाग लेंगें।

श्री रिखी राम कौंडलः उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-9 जिस पर हमने कटौती प्रस्ताव दिए और जिस पर माननीय ईश्वर दास धीमान जी ने बड़े विस्तार से चर्चा की है, उसमें मैं भी कुछ बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है । 80-85 प्रतिशत लोग यहां गांव में रहते हैं और 15 प्रतिशत शहरों में रहते हैं ।जब से देश आजाद हुआ, पंचवर्षीय योजना बनने लगी। शुरू से ही हर काम के लिए चाहे वह कृषि हो, स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली-पानी हो, हमेशा पंचवर्षीय योजनाओं में शहरों का ध्यान रखना शुरू

किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपैयी जी का, जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न का अवार्ड मिला, वे इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं है और हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने अपने समय के अंदर जो पंचवर्षीय योजना बनाई उसमें चाहे कृषि का बजट हो या स्वास्थ्य का बजट हो, शहरों को छोड़कर गांव की तरफ मोड़ा और स्वास्थ्य विभाग में भिन्न-भिन्न योजनाएं शुरू की। मैं यह नहीं कहता कि इससे पहले योजना शुरू नहीं थी। इससे पहले भी थी। हमेशा जब तक राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति हो, वह अन्तिम समय तक सीखता रहता है। यह सोच लिया जाए कि मै बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हूं, अब मैं सबकुछ सीख चुका हूं तो जब तक शरीर है, जिस क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है, वह अन्तिम समय तक नई-नई बातें सीखता है। आज विधान सभा के अंदर ई-विधान शुरू हो

30.03.2015/1800/केएस/एजी/3

गया है और जब 1985 में यहां आए थे तो हम यहां कैसे काम करते थे? आज स्वास्थ्य विभाग में भी, मैं यह नहीं मानता कि सुधार नहीं हुआ, सुधार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें टैक्निकल स्टाफ की आवश्यकता होती है। जब पंचवर्षीय योजना बनना शुरू हुई तो उन योजनाओं में ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए थी कि हम ज्यादा से ज्यादा मैडिकल कॉलेज खोलें, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ नर्सिज़ हमारी निकले और जो गांव के अंदर---

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

30.3.2015/1805/ag/av/1

श्री रिखी राम कौंडल जारी----------
और गांव के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो इनफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था उसकी पूर्ति हो सके। मगर ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1977 के बाद जब सारे देश के अंदर थोड़ा सा बदलाव आया तो उसके पश्चात प्लानिंग डिपार्टमैंट ने भी थोड़ा सोचना शुरु किया। उन्होंने सोचा कि राजनैतिक क्षेत्र में हमारी और पार्टियों की सर्वाइवल तभी होगी जब हम शहरों को छोड़कर गांव की तरफ जायेंगे। गांव की तरफ आये। स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज नैट का युग है। मैंने सुबह बैठकर घंटाभर

नैट को ऑपरेट किया और देखा कि प्रदेश में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य कैसा है। सारे प्रदेश के अंदर कितने डॉक्टर्ज और नर्सिज हैं। मैंने नैट पर आधा-पौना घंटा ढूंढा मगर आपने वैबसाइट पर अभी तक स्टाफ पैटर्न ही नहीं डाला है। जब हम असैम्बली में प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब आता है मगर वह पर्टिकुलर जवाब होता है। इस देश व प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को वैबसाइट पर हर विभाग की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का अधिकार है। कौल सिंह जी, आप धड़ाधड़ प्रमोशन कर रहे हैं जबकि आपकी वैबसाइट पर प्रमोशन रूल्ज ही नहीं हैं। आपने किस आधार पर स्टाफ नर्सिज की प्रमोशन करनी है, आपने किस आधार पर ऐसिस्टैंट डायरैक्टर की प्रमोशन करनी है? पिक एण्ड चूज के आधार पर जिसकी ए.सी.आर. अच्छी होती है उसकी प्रमोशन कर दी जाती है। मैं आपको यहां एक इण्डियन नर्सिंग कौंसिल का उदाहरण देना चाहता हूं बाकी मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में बाद में बोलूंगा। The whole of the country is governed by the Indian Nursing Council for the appointment of Nurses, for the promotion rules of the Matron, for the promotion rules of the Ward Sister, for the promotion of Deputy Superintendent, for the promotion of Superintendent, for the promotion of Deputy Director, and for the promotion of Director. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस मान्य सदन का ध्यान केवल

30.3.2015/1805/ag/av/2

डिप्टी ऐसिस्टैंट नर्सिंग और डिप्टी नर्सिंग पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। Essential Qualifications - Registered Nurses and registered Midwife - this is essential qualification. Diploma in Nursing Education and Administration, (DSC) for the post basic degree for Nursing, five years experience as Assistant Nursing Superintendent, प्रमोशन के लिए यह क्राइटीरिया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप बताएं कि आपके आई.जी.एम.सी. और टांडा में जितनी नर्सिज सुपरइनटैनडैंट और डिप्टी सुपरइनटैनडैंट हैं क्या वे क्वालिफिकेशन्ज को फिलअप करती है? आपके विभाग ने कभी इस ओर ध्यान किया? आप इस ओर ध्यान दीजिए, अभी और प्रमोशन्ज होने वाली हैं। मैं रूल्ज की वकालत कर रहा हूं कि एशैंशियल क्वालिफिकेशन के आधार पर प्रमोशन होनी चाहिए। मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि रूल्ज में प्रोविजन है। Relaxation of approved qualification may be given while considering the person for promotion who have worked for at

least eight years in a probatory or permanent capacity in the immediate next lower scale in the concerned cadre, relaxation is approved should be given only for laid down academic qualification. अगर आप रिलैक्सेशन देंगे तो उसमें आप दूसरी चीजों को रिलैक्स कर सकते हैं मगर ऐकेडैमिक क्वालिफिकेशन में आप रिलैक्सशेसन नहीं दे सकते। It is reiterated that relaxation of qualification cannot be given while making appointment or at the entry point of the cadre. There shall be no relaxation of qualification relating to the technical expertise while making appointment or either promotion. आपका स्वास्थ्य विभाग कैसे ठीक होगा? यहां तो धर्मशाला बनी हुई है, जिसकी अप्रोच है उसको फटाफट प्रमोशन दी जा रही है। आपके आई.जी.एम.सी. और टांडा में जितनी भी पोस्टें भरी गई हैं और प्रमोशन्ज हुई हैं क्या वे नियमों के अनुसार हुई है? हम यह ---

श्री बी.जे.द्वारा जारी

30.03.2015/1810/negi/ag/1

श्री रिखी राम कौंडल ..जारी...

क्या ये प्रोमोशन्ज़ रूल्ज़ के मुताबिक हुई हैं? हम कैसे मान सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य विभाग ठीक है। यह तो मैंने थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस दिया है। आपका स्टॉफ पैटर्न वैवसाइट पर नही है और रूल्ज़ आपके नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैं एन.एच.आर.एम. का उदाहरण देना चाहूंगा। एन.एच.आर.एम. की गाइड लाईन्ज़ गवर्नमैन्ट ऑफ इण्डिया की है। इसके तहत एन.आर.एच.एम. चलता है और आप इसको फोलो कर रहे हैं। आर.के.एस. से कैसे होगा, Finance control by the RKS. मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता। एन.आर.एच.एम. में जो आशा वर्कर लगाने की बात है। यह बात हमारे समय में भी आई थी ।भले ही हमारे मुख्य मंत्री जी के ध्यान में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लाया, हम भी वहां थे, इन्होंने कहा कि 500 रूपये में एक महिला को इंगेज करेंगे तो उसको एक दिन के कितने पैसे मिलेगे? हमने उस चीज़ को लागू नहीं किया। हम यह सोच रहे थे कि इसमें कैसे सुधार किया जाए और कैसे एन.आर.एच.एम में पैसा बढ़ाया जाए ताकि इनको हम भर्ती करें। आपने 5 00रूपये में इनको भर्ती कर दिया। क्या यह उनके साथ मज़ाक नही है कि 500 रूपये में गांव में महिला सारा दिन काम करे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अब उनको 1000 रूपये मिलते हैं।

श्री रिखी राम कौंडलः रूल्ज़ में तो 500 रूपये है, शायद आपने अमैंड करके 1000 रूपये किया होगा। लेकिन 1000 रूपये भी कम है। अगर आप 1000 रूपये देंगे तो 30 दिन में कितनी दिहाड़ी पड़ेगी? मजदूरों की दिहाडी भी ज्यादा है। वैसे तो आप रोजगार देने का बड़ा दावा करते हैं । .....(व्यवधान)... आप(श्री नीरज भारती) बहुत उछल-कूद मत करों, अगले तीन साल के बाद पता लगेगा कि आपकी औकात क्या है? आप जब बोलते हैं तो मैं इन्टरवीन नही करता।

Deputy Speaker: Please don't interrupt.

30.03.2015/1810/negi/ag/2

श्री रिखी राम कौंडल : मैंने आपको कभी भी डिसटर्ब नही किया।...(व्यवधान) ... बिल्कुल नहीं। I have never disturbed any-body. आप बात सुनिये, मंत्री जी जवाब देंगे। आप या तो स्वास्थ्य विभाग का कैबिनेट मंत्री बन जाइये तब बीच में इन्टरवीन कीजिए । .....(व्यवधान).... हमारी बात छोड़िए। अच्छा नहीं लगता। आप ऐसी पॉलिटिकल फैमिली से संबंध रखते हैं । अपने बाप का ध्यान रखिए और इस मान्य सदन में जब वह सुशोभित होते थे तो उनकी बात सुनने के लिए सारा सदन स्तब्ध हो जाता था, वह कार्यप्रणाली थी उस व्यक्ति की । उसको सींचिए आप। आप अपने पेरेन्ट्स से संस्कार सीखिए।

Deputy Speaker: Please don't disturb.

श्री रिखी राम कौंडल :उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें जो मैंने रखी उस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। इसके बाद मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। ....(व्यवधान)... बम्बर ठाकुर जी आप बैठ जाइये। आपने जब बोलना होगा तो बोलना। ...(व्यवधान).. आप जितना मर्ज़ी बोलें, मैं फ्रस्ट्रैक नही हुंगा। मैं कभी आऊट ऑफ ट्रैक नहीं जाता । । am not going out of track.

उपाध्यक्षः प्लीज आप इनको बोलने दीजिए।

श्री रिखी राम कौंडल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहूंगा , माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हमें 3 पी.एच.सीज. दी है। मेरा प्रश्न भी था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री कौल सिंह जी ने ए.एम.ओ और एम.पी.डब्ल्यू. पर ऐसा कहा और मैंने कहा कि ए.एम.ओ. आयुर्वेदा का होता है और एम.पी.डब्लयू. दूसरा होता है। इन्होंने भी गलत सोचा होगा और मैंने भी गलत समझा और हमारी आपस में नोकझोंक हो गई। आपके उत्तर में है कि गवाडकोटी में ए.एम.ओ. पोस्टिड है लेकिन असलियत में वह वहां नहीं है। मेडिकल ऑफिसर आपने गवाड़ में पोस्टिड हैं लिखा है लेकिन वहां है नहीं । झंडूता में 3 डॉक्टरों की कमी है। हमारे बरठी में डेन्टल की

30.03.2015/1810/negi/ag/3

एक पोस्ट थी, मुख्य मंत्री जी ने हमें यह पोस्ट दी थी । स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया, हमें डेन्टल की पोस्ट मिली। आपकी सरकार आते ही बरठीं से डेन्टल की पोस्ट उठा ली। वहां से वह कुर्सी भी उठा करके ले गए और सारा ताम-जाम उठा करके ले गए। ऐसा करने से विपक्ष का जो विधायक होता है उसके बारे में लोग सोचते हैं कि विपक्ष का विधायक था तभी पोस्ट चली गई। इससे कंफ्युजन होती है। प्रजातन्त्र में सबको अपने-अपने चुनाव क्षेत्र की बात रखने का अधिकार है। जो चीज़ एक बार किसी ने दे दी उसमें आपकी बड़ाई नहीं हुई, उसमें भले ही हमारा राजनीति दृष्टि से फायदा जरूर हुआ। परन्तु मेरा आपसे निवेदन है कि जो चीज एक बार चुनाव क्षेत्र में दे दी , सरकारें आती -जाती रहती है, कभी हम आएंगे और कभी आप आएंगे, लेकिन जो इंस्टीट्युशन है उसकी आप कद्र करिये और वहां से कोई पोस्ट न विदड्रा कीजिए और न दीजिए। एक मैं कल का प्रश्न देख रहा था । एक छोटी सी बात मेरे ध्यान मे आई, एक दूसरे जिले से मण्डी के लिए आपने डेपूटेशन पर क्लास-फोर कर्मचारी भेज दिया। आप इतने कमजोर मंत्री है कि क्लास-फोर की भी ट्रांसफर नही कर सकते कि उसको ट्रांसफर से भेज देते। आपने उसको डेपूटेशन पर भेज दिया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : कहां की बात कर रहे हैं आप?

श्री रिखी राम कौंडलः आपने पधर के लिए डेपुटेशन पर भेजा है। इस मान्य सदन में एक क्वैश्चन लगा था और उसके जवाब में यह आया है।..

श्रीमती यू.के. द्वारा जारी...

30/03/2015/1815/यूके/एजी/1

श्री रिखी राम कौंडल---जारी ---
प्रश्न का जवाब आया है उसमें । तो माननीय मंत्री जी, मेरा एक निवेदन है कि तालियां दोनों हाथों से बजती हैं । थोड़ा तालमेल सबके साथ रखो । मुख्य मंत्री का भी ध्यान करो । तभी तो आपको डेपुटेशन पर भेजना पड़ा । अगर मुख्य मंत्री जी के साथ आपके सम्बन्ध ठीक होते तो ऑर्डर आप ही कर सकते थे । इसलिए प्रजातंत्र में भरोसा रखिए, चुने हुए प्रतिनिधि का सम्मान करिए । मैं आपको एक बात के लिए धन्यवाद देता हूं, आप मेरे चुनाव क्षेत्र में गए, आपने हमें पूरा मान-सम्मान दिया । पर यह जो चोर दरवाजे से हमारी पोस्टों को इधर-उधर कर रहे हैं । इसको मत करिए । ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं । प्रोमोशन रूल आपके वैबसाईट पर नहीं हैं । आपकी पोस्टों का अपडेट डाटा आपका नहीं है । प्रोमोशनें आपकी आई0जी0एम0सी0 और टांडा में बिना रूल के हुई है । उसकी छानबीन करिए । इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर-9 का समर्थन कदापि नहीं कर सकता । आपने समय दिया, आपका धन्यवाद ।

30/03/2015/1815/यूके/एजी/2

उपाध्यक्ष :अब श्री विजय अग्निहोत्री जी, चर्चा में भाग लेंगे ।

श्री विजय अग्निहोत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर जो कटौती प्रस्ताव आया है, मैं उसके विषय में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें स्वास्थ्य विभाग के बारे में कही हैं जिससे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् वैल्फेयर डिपार्टमैंट में व्यक्ति को, देश और प्रदेश की जनता को और समाज को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, डैथ रेट कम हो और व्यक्ति स्वस्थ हो कर इस समाज में देश में काम करे ताकि यह देश आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास किया गया । इसके चलते बहुत से संस्थान खुले, बहुत सी नयी-नयी खोंजें भी हुईं और उसके कारण से अनुसंधान होते हुए आज बहुत सी बीमारियों के इलाज भी शुरू हुए, जो कभी असाध्य माना जाता था । प्रदेश में भी स्वास्थय केन्द्रों का, स्वास्थ्य संस्थानों का जाल बिछना आरम्भ हुआ लेकिन इस भागमभाग में जहां संस्थान हमने ज्यादा खोलने की कोशिश की लेकिन उसमें अपेक्षित स्टाफ हो, डॉक्टर्स का प्रबन्ध किया जाए । मेडिकल

कॉलेजिज़ ज्यादा खोले जाएं, उनमे सीटें बढ़ाई जाएं । इनका प्रावधान हम जितनी अपेक्षा थी उतना नहीं कर पाए हैं । आज प्रदेश में जहां दो प्रमुख मेडिकल कॉलेजिज़ हैं, IGMC और TMC हैं । वहीं 78के लगभग CHCs हैं । सैंकड़ों PHC हैं लेकिन उनमें बहुत सी कमियां हैं । चाहे मैडिकल आफिर्सस की कमी है ,फंक्शनल स्टॉफ की कमी है । अगर मेडिकल कॉलेज के ही बारे में हम देखते हैं तो जहां हमने सुविधाएं भी दी हैं, वहां गरीब व्यक्ति को यह सुविधाएं लेने में बहुत दिक्कत और असुविधा हो रही है । क्योंकि प्रदेश बहुत लम्बा-चौड़ा है । केवल2 -3 जगहों पर ही सुपर स्पेशियलिटी है और वहां जब गांव का व्यक्ति उठ कर जाता है तो वहां बहुत भीड़ होने के कारण और अन्य असुविधाओं के कारण उसे उन सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है । जहां मेडिकल ऑफिर्सस की, डॉक्टर्स की कमी है, वहीं फंक्शनल स्टॉफ चाहे वह स्टॉफ नर्सिज़ की बात है, चाहे मेल हैल्थ वर्कर चाहे फिमेल हैल्थ वर्कर या मल्टी परपज़ वर्कर की बात है हर जगह पिछले कई वर्षों से बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हैं । पीछे एक प्रश्न भी लगा था और श्रीमती आशा कुमारी जी ने भी यहां एक चर्चा लाई थी कि फंक्शनल पोस्टों को कब तक भर दिया जाएगा ?

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

30.03.2015/1820/sls-ag-1

श्री विजय अग्निहोत्री...जारी

लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से स्वास्थ्य सस्थानों में सुविधाओं की बहुत कमी है। टाण्डा मैडिकल कॉलेज में सुपर स्पैस्लिटी, जिसका अभी उद्घाटन हुआ है, उसमें बहुत से विभाग शुरू ही नहीं हा पा रहे हैं। वहां सुपर स्पैस्लिटी में सुपर स्पैस्लिस्ट डॉक्टर वहां रुकें, उसके लिए सरकार क्या सुविधाएं दे रही है? वहां कोई रुकता नहीं है। वहां कार्डियोलोजी का अभाव है। एक डॉक्टर सप्ताह में एक या दो दिन बैठता है। निचले क्षेत्र के लोग जब किसी अस्पताल में जाते हैं तो उनको फर्स्ट एड देने के बाद टाण्डा मैडिकल कॉलेज में रैफर किया जाता है। लेकिन जब वहां उनको पता चलता है कि यहां सुपर स्पैस्लिटी सुविधा नहीं है तो उसके बाद वह पी.जी.आई. या लुधियाणा, जालंधर में सी.एम.सी., डी.एम.सी. में महंगी जगह पर जाकर ईलाज करवाने के लिए मज़बूर होते हैं।

जहां तक भर्तियों की बात है, इस प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन और सुबोर्डिनेट सलैक्शन बोर्ड हैं। उसके बावजूद हम कई निजी संस्थाओं के माध्यम से

भर्तियां कर रहे हैं। जिनको आर.के.एस. के माध्यम से रखा है उनको रैगुलर नहीं किया जा रहा है। एम.पी.डब्ल्यू. और एफ.एच.डब्ल्यू. का जो बड़ा कॉडर प्रदेश में है ,जिनकी बहुत सी पोस्टें खाली हैं, क्या हम उनको मैरिट के आधार पर या टैस्ट के आधार पर भरने के साथ-साथ बैचवाईज भरने की भी कोशिश कर सकते हैं?

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। अभी आशा वर्कर्ज की बात हुई। ठीक है कि जो उनको मानदेय दिया जा रहा है, वह कम होगा; उसको ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो उनकी भर्ती हुई ,उसमें क्या क्राईटेरिया रहा, किस ढंग से किया गया ,वह हम सबके सामने है। मैंने ब्लॉक मैडिकल ऑफिसर गलोड़ का एक उदाहरण पेश किया था कि वहां इनके इंट्रव्यू हुए। उसके बाद उनकी लिस्ट लगी। फिर कुछ लोगों को अप्वायंटमैंट लैटर दे दिए। उसके बाद उनके अप्वायंटमैंट लैटर वापिस बुला लिए। इसके कारण वहां के बी.एम.ओ. को लंबी छुट्टी पर भी जाना पड़ा। इन सारी चीजों के बारे में अगर आप ध्यान रखेंगे तभी अच्छी

30.03.2015/1820/sls-ag-2

स्वास्थ्य सुविधाएं इस प्रदेश में दी जा सकेंगी। अगर मैरिटोरियस व्यक्ति आगे आएगा तो वह अच्छी तरह से सेवा कर सकता है और जो उसकी ड्यूटि होगी, उसको पूरा करेगा।

यह हमारा और आपका आज का विषय नहीं है फिर भी मैं बोलना चाहता हूं कि वैल्यूज में कमी आई है। आज व्यक्ति के चरित्र में कमी आई है। इसी कारण से डॉक्टर्ज़ के चरित्र में भी कमी आई है। आज ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि मरीज आप्रेशन थियेटर में होता है और कहा जाता है कि इतने पैसे जमा करवाओ नहीं तो आप्रेशन नहीं किया जाएगा। कई बार ऐसे लोग भी देखे गए कि अस्पताल में रोगी मर गया, उसके बावजूद अटैंडैंट से हजारों का सामान मंगवा लेते हैं और आधे घंटे के बाद उसको डैड डिक्लेयर कर देते हैं; सामान वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। चाहे इसमें विभाग का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता लेकिन इसको कैसे चैक किया जा सकता है ताकि गरीब से गरीब तक और ज़रूरतमंद तक हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें?

मैं आपके माध्यम से एक बात और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो यह सारी सुविधाएं हैं, जैसे पी.एच.सी. और सी.एच.सी. के लिए हमने क्राइटेरिया रखा है कि 80,000 की जनसंख्या होगी उसके बाद सी.एच.सी. खोला जाएगा, इन सब

संस्थानों के खुलने के बावजूद भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं, उनमें कमियां हैं। रोगियों की भीड़ बढ़ रही है क्योंकि हमारा लाईफ स्टाइल भी बदल रहा है। पिछली सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया था। हम डॉक्टर एकदम से पैदा नहीं कर सकते। माननीय धूमल जी की सरकार ने स्वामी रामदेव को यहां मौका दिया था कि वह यहां पर अपना सैंटर खोले ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। आपने उसको भी डिस्टर्व किया। वहां व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ कर सकता था और आपका वर्डन कम होना था।

इसके साथ-साथ बहुत-सी सेवाएं आपने आऊटसोर्स की हैं। चाहे वह टैस्ट की बात है। बेशक उसमें क्वालिटी की भी बात हो लेकिन.. जारी...गर्ग जी

30/03/2015/1825/RG/AG/1

श्री विजय अग्निहोत्री-------क्रमागत

बेशक उसमें क्वालिटी की भी बात हो, उससे भी हजारों लोगों की रोजी-रोटी पर प्रश्न खड़ा हुआ है। लेकिन जहां गांवों में इन्टीरियर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी.एच.सी. छोडू अच्छा भवन है वहां डॉक्टर है, लेकिन लैब नहीं है, वहां कोई टैस्ट नहीं हो सकता, वहां कोई जाता ही नहीं है ,ओ.पी.डी. वहां बहुत नगण्य हो गई है। इसी प्रकार बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां बहुत अच्छी ओ.पी.डी. थीं ,लेकिन आपने वहां से कुछ फंक्शनल पोस्ट्ज ही उठा दीं ,चाहे धनेटा की पी.एच.सी. है वहां से फार्मासिस्ट को विद पोस्ट ही उठा दिया। हालांकि मैं उसका इसलिए विरोध नहीं कर पाया कि आपने उसको गलोड़ भेजा। वह भी मेरे चुनाव क्षेत्र में है। लेकिन धनेटा में भी उसकी आवश्यकता है ,सी.एच.सी. गलोड़ के लिए आप नया दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में दो स्वास्थ्य भवनों का निर्माण हो रहा है एक सी.एच.सी. नदौन और दूसरा पी.एच.सी. कांगू का। पी.एच.सी., कांगू का निर्माण लगभग पूरा हो गया है ,लेकिन पता नहीं उसमें क्या शेष बचा है कि उसको शुरू नहीं किया जा रहा है। बाकी जो हमीरपुर हॉस्पीटल है जिसको हम कभी जोनल हॉस्पीटल या कभी रीजनल हॉस्पीटल का नाम दे देते हैं। उसमें भी एक गाइनॉकॉलॉजिस्ट है और वहां पूरे जिले का इतना बर्डन है कि हर दूसरी-तीसरी महिला जिसकी डिलीवरी होनी होती है, उसको टांडा रैफर कर दिया जाता है। यहां विभाग में भी डॉक्टर्ज की कमी है और सबसे ज्यादा कमी इमरजैंसी के समय की है।

रात को केवल एक डॉक्टर डियुटी पर होता है बाकी डॉक्टर्ज को कॉल करके बुलाना पड़ता है। जो ऐसे पी.एच.सी., सी.एच.सी. या रीजनल हॉस्पीटल हैं उनमें एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि डॉक्टर के निवास स्थान वहां से नजदीक हों ,साथ में ही बनें ताकि रात में हर रोगी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। क्योंकि आधी रात को यदि कोई रोगी रैफर होकर वहां जाता है, अगर उसको वहां प्राथमिक उपचार भी नहीं मिले और वहां उसे कहा जाए कि आप रोगी को टांडा ले जाओ, यहां डॉक्टर नहीं है, तो उसके परिवार वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो केन्द्र सरकार का धन्यवाद है कि ऐम्स और मैडिकल कॉलेजिज भी यहां खुलने जा रहे हैं। वैसे पीछे इस पर चर्चा भी हुई कि हमीरपुर में मैडिकल कॉलेज बनेगा ,सिरमौर या चम्बा में खुलेगा। लेकिन कब तक

30/03/2015/1825/RG/AG/2

खुलेगा, इस बारे में बहुत कन्फ्युजन है। उसमें कितना पैसा है, उसमें कन्फ्युजन है। इसलिए इन सारे विषयों का आज मंत्री महोदय यहां जवाब देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में हमीरपुर में बहुत सी कोशिश हुई हैं, वैसे इस सरकार के समय में भी हुई हैं, चाहे वह 'बेटी है अनमोल ,'सैक्स रेश्यो ठीक हो, स्वास्थ्य सेवाओं ठीक हों। पीछे प्रश्नकाल में स्मार्ट कार्ड के बारे में एक प्रश्न भी लगा था। मैं कहना चाहूंगा कि स्मार्ट कार्ट का लाभ बहुत ज्यादा लोगों को नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आपने 'आशा' वर्कर्ज रखे हैं और फील्ड वर्कर्ज आपके पास हैं। उनके माध्यम से समाज को शिक्षित करने की जरूरत है। किसी का स्मार्ट कार्ड बन जाता है, तो वह रिन्यु ही नहीं करवाता है। इस प्रकार उसके लाभों से वह वंचित रह जाता है, कोई उसमें इन्क्लूड नहीं हो पाता है।' जन-धन योजना' जो चली है कई बार उसमें अकॉउन्ट खुलवाना भी लोग भूल जाते हैं ,तो इन सारी चीजों को देखना चाहिए। पिछले दिनों जब मैं घर गया था, तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके छोटे-छोटे पांच बच्चे हैं, लेकिन उसका जन-धन योजना में खाता नहीं है इसलिए उसको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल सकती है। ऐसे जो जन-कल्याण के कार्य हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए ,अपने फील्ड वर्कर्ज के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना चाहिए। 108 और 102 की सुविधा इस प्रदेश में है, लेकिन अब 108 सेवा को चले हुए काफी दिन हो गए हैं और गाड़ियां पुरानी हो गई हैं। आप कंपनी से इस बारे में बात करें ताकि उनका रख-

रखाव भी हो सके। इन गाड़ियों के खराब होने के कारण भी लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक सब-सेन्टर बधेड़ा-सनाही है उसके लिए पैसा बहुत दिनों से गया हुआ है, लेकिन उसका काम नहीं चल रहा है, सब-सेन्टर सनोह जनसूह में जमीन है, भवन नहीं बने हैं। लोग चाहते हैं कि उसमें जल्दी से भवन बने। इसी प्रकार पी.एच.सी. कांगू के भवन के बारे में अभी मैंने कहा है। प्रदेश में एम.बी.बी.एस. की सीटें बढ़ें जिससे ज्यादा लोग डॉक्टर्ज बनें और पी.जी. की सीटें बढ़ें, इस बारे में भी हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या कारण है कि टांडा मैडिकल कॉलेज की एम.सी.आई. की ओर से जब भी कोई इंसपैक्शन होती हे, तो कई बार बाहर से और कई बार आई.जी.एम.सी. के लोगों को वहां कुछ दिन के लिए ट्रांसफर करके उसकी इंसपैक्शन करवाई जाती है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए

30/03/2015/1825/RG/AG/3

ताकि वहां सीटें बढ़ती रहीं। इसके अलावा ये जो तीन प्रस्तावित मैडिकल कॉलेजिज हैं इनमें जल्दी-से-जल्दी काम शुरू हो ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। कई बार दूर-दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें इसके लिए सरकार प्रयासरत भी है , लेकिन उसके बावजूद बहुत सी कमियां हैं। सी.एच.सी. शिलाई में केवल दो डॉक्टर्ज हैं और उसकी ओ.पी.डी. में लगभग 300-350 रोगी की है------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2015/1830/MS/AG/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी-----

सी0एच0सी0 शिलाई में केवल दो डॉक्टर्ज हैं और उनकी ओ0पी0डी0 300-350 है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए और मरीजों को रैफर करके पौंटा भेजा जाता है तो वहां के लिए ढाई-तीन घण्टे लगते हैं। इस करके वहां डॉक्टर का प्रबंध किया जाए। वहां पर ओ0टी0 का कोई काम नहीं होता है। स्पैशलिस्ट वहां है नहीं और माननीय मंत्री जी ने पहले भी एक बार बातचीत में कहा था कि हम अब डैपुटेशन नहीं करते हैं। लेकिन वहां

पी0एच0सी0 क्वारी-गुणा में जो डॉक्टर काम करता है, उसको वहां 15 दिन बाद डिप्यूट कर दिया जाता है और यह बहुत दूर-दराज की पी0एच0सी0 है। इसलिए वहां के लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सिरमौर में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़नी चाहिए। पी0एच0सी0 चलोग, पी0एच0सी0 बगथान और कोटी-फलोग में डॉक्टर्ज की कमी है। वहां पर कोई डॉक्टर काम नहीं करता है। इन सब विषयों की ओर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं तथा फंक्शनल पदों को जल्दी-से-जल्दी भरने की कोशिश की जाए। इस पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर प्राइवेटाइजेशन और उनकी भर्तियां किन्हीं संस्थाओं के द्वारा की जा रही हैं उसको रोका जाए क्योंकि उसके कारण से प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इस कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए, मैं इस मांग का समर्थन नहीं कर सकता। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब श्री सुरेश भारद्वाज जी चर्चा में भाग लेंगे।

30/03/2015/1830/MS/AG/2

श्री सुरेश भारद्वाजः उपाध्यक्ष जी, मांग संख्या-9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की मांगों पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

स्वास्थ्य विभाग जैसा कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और सोशल सरोकारों का विभाग है। लेकिन ऐसा लगता है जितना विभाग में पैसा रखा हुआ होता है, वह भी ठीक प्रकार से खर्च नहीं होता है। वर्ष 2014- 15में आई0जी0एम0सी0 के लिए 13291 लाख रूपये रखा था लेकिन दिनांक31 . 12. 2014तक 4199लाख रूपये ही खर्च हुए। ऐसे ही टांडा के लिए 6626.41 लाख रूपये का प्रोविजन था लेकिन 31 दिसम्बर तक 2686.14 लाख रूपये ही खर्च हुए। यह फीगर मैं केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह सारी साल का बजट होता है और 31 दिसम्बर तक एक तिहाई भी खर्च नहीं होता है। जिसका अर्थ है कि लास्ट के दो महीने में या अगर ठीक कहें तो जो बजट का मार्च महीना होता है, उसी में सारे खर्चे होते हैं या फिर जो अनस्पेंट मनी रह जाता है, उसको अगले वर्ष के लिए बदल दिया जाता है। जिसका अर्थ यह है कि (व्यवधान) उसको कैरी फॉरवर्ड करते होंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि यह विभाग आम जनता के लाभ के लिए हैं। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं सरकारें और वेल्फेयर स्टेट्स उपलब्ध करवाती हैं। इसलिए जो पैसा सरकार ने अपने बजट में रखा

होता है, उसको प्रौपर वित्तीय वर्ष में बांटकर के आप कहें, एक तिमाही के हिसाब से करते हैं। अब सारे का सारा लास्ट के महीने में खर्च करेंगे तो जो लोगों को साल भर में सुविधाएं मिलनी चाहिए ,वे नहीं मिल पाती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम बहुत सारे प्रदेशों से आगे हैं। बहुत सारे प्रदेशों जैसे पंजाब इत्यादि में अधिकांश प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास लोग जाना चाहते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं हेतु हरेक व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में ही जाने के लिए आतुर रहता है,

जारी श्री जे0के0द्वारा------

30.03.2015/1835/जेके/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाजः------जारी-----

और वहां पर मिलती भी हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर बहुत समय से हमारी स्थिति यह हो गई है कि आपको वहां पर डॉक्टर्ज नहीं मिलते हैं। उसमें कारण कई हो सकते हैं। डॉक्टर को प्राईवेट हॉस्पिटल में ज्यादा सैलरी मिलती है। वहां पर दूसरी सुविधाएं नहीं होती हैं इसलिए वे सरकारी हॉस्पिटल को ऑप्ट नहीं करते हैं। यदि वे सरकार के हॉस्पिटल्ज में आए तो उनको रूरल एरियाज में जाना पड़ता है। ट्राईबल एरियाज़ में जाना पड़ता है। वहां पर उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। रहने के लिए सुविधा नहीं मिलती है, सर्च करने की सुविधा नहीं मिलती है और वहां पर बहुत सारी मशीनरीज़ आदि भी नहीं होती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्ज स्पैशलिस्ट होते हैं। जिनको यदि रिमोट एरिया यानि डोडरा-क्वार जैसे एरिया में भेज देंगे या कहीं ट्राईबल एरिया में भेज देंगे और वहां पर उनके मतलब की कोई चीज़ नहीं होगी यानि स्वास्थ्य सुविधा तो वह लोगों को दे सकते हैं लेकिन उस प्रकार के इंस्ट्रूमैंट्स उनको वहां पर नहीं मिलते तब वह वहां पर काम नहीं कर पाते हैं। वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वह नौकरी छोड़ करके चले जाता है। इसी चीज की ओर हमें हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस स्थान पर हम नई सुविधा देने जा रहे हैं वहां पर सबसे पहली जरूरत है कि हम वहां पर एक डॉक्टर लगाएं, वहां पर फार्मासिस्ट हो या स्टाफ नर्स इत्यादि हो। इसके साथ-साथ वहां पर मरीज़ के लिए दवाइयाँ मिल सकें। आज स्थिति यह है कि सरकारी अस्पताल में दवाईयां कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। दवाइयां डॉक्टर लिखते हैं और सब बाजार से खरीदनी पड़ती है। उसमें भी सरकार के आदेश हैं कि जैनरिक दवाईयां डॉक्टर्ज लिखेंगे ताकि जैनरिक दवाईयां लोगों को मिले। लेकिन अधिकांश हॉस्पिटल्ज और चिकित्सा संस्थानों में जैनरिक दवाइयां लिखने के बजाए बड़ी-बड़ी ब्रांडिड दवाइयां लिखी जाती हैं। जब गरीब आदमी उन दवाइयों को लेना चाहता है तब वह उन दवाइयों

को खरीदने में असमर्थ हो जाता है। अब उसमें कई लोगों को सुविधाएं आई.आर.डी.पी. परिवारों के लिए, स्मार्ट कार्ड आदि बनाने की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा जागरूकता लोगों में नहीं है इसलिए यहां के लोग स्मार्ट कार्ड को भी नहीं बना पाता है। अगर बन

30.03.2015/1835/जेके/एजी/2

जाता है तो दोबारा से रिन्यू नहीं हो पाता है। बीमार कब हो जाए यह मालूम नहीं होता है। अगर चिकित्सा संस्थानों से डॉक्टर्ज उन जैनरिक दवाईयों को लिखेंगे तो जो लोग छोटे-मोटे स्थानों से स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं उससे उनको लाभ हो सकता है अन्यथा दवाई न खरीद पाने के कारण वह बहुत ज्यादा अस्वस्थ होता जाता है। उसको लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता हैं। हमारे बहुत सारे संस्थान हैं। लेकिन दो संस्थान प्रमुख है, आई.जी.एम.सी. और टांडा मेडिकल कॉलेज । ये बहुत अच्छे कॉलेजिज है। आई.जी.एम.सी. का प्रोडक्ट जब बाहर जाता है तो वह बहुत अच्छे स्थान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज वह सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारे ऑप्रेशन्ज नहीं हो पा रहे हैं। आई.जी.एम.सी. में सी.टी.वी.एस. डिपार्टमैंट है। सी.टी.वी.एस. डिपार्टमैंट ओपन हॉर्ट सर्जरी करता है। हमारे पास उसके चिकित्सक हैं। लेकिन जब परफ्युजनिस्ट रिटायर हो जाता है तब ऑप्रेशन बन्द हो जाते हैं। हम उस परफ्युजनिस्ट को एप्वाईंट नहीं कर सकते हैं। आर.के.एस. में वह मिलता नहीं है। जो इन विभागों में फंक्शनल पोस्टें हैं उन फंक्शनल पोस्टों को तो भरा जाना चाहिए। यह अखबारों में भी आया और प्रिंसिपल ने स्वयं इस बात को एक्नोलेज किया। जब अखबारों में आया तो हमने उसके लिए प्रबन्ध किया। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो पुराने को ही आप री-इम्प्लॉयमैंट दे दीजिए। जहां पर जरूरत है उस तरह की व्यवस्था आप कर सकते हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल जाए। इसी तरह से प्रदेश में स्वाईन फ्लू हो गया। सारे हिन्दुस्तान के प्रदेशों में हुआ होगा लेकिन हिमाचल बहुत ज्यादा हाई लाईट हुआ है। यह हिल स्टेट है। यहां पर दुनिया भर से टूरिस्ट आता है। ट्राईबल एरियाज में जाता है। शिमला, धर्मशाला, डलहौजी आदि स्थानों पर भी जाता है। जब इस प्रकार की खबरें टूरिस्ट पढ़ता है कि स्वाईन फ्लू हो गया है और यहां पर 21 से ज्यादा लोग मर गए हैं, उसके कारण वे यहां आने बन्द हो जाते हैं। उससे टूरिज्म इफैक्ट होता है। उसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं इफैक्ट होती है और लोग घूमने-फिरने आना बन्द कर देते हैं। इस

30.03.2015/1835/जेके/एजी/3

प्रकार से इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले एनीमिया का भी प्रोग्राम होता था। वह प्रोग्राम आजकल बन्द है। उसको ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी.....

30.03.2015/1840/SS-AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

आई0जी0एम0सी0 हमारा बहुत प्रीमियर इंस्टिट्यूशन है। इसमें अगर हम प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल या पी0जी0आई0 नहीं जायेंगे। मोहाली का फॉरटीज़ हॉस्पिटल अधिकांश हिमाचल के लोगों ,शिमला के लोगों पर चल रहा है। हमारे यहां खलीनी में एक इम्प्लॉईज था। उसको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई तो उसे सीधे फॉरटीज हॉस्पिटल ले गए क्योंकि यहां व्यवस्था नहीं थी। फॉरटीज़ में उसको फटाफट तीन स्टंट डाल दिए। 8 लाख रुपया उसका दो दिन में वहां पर लग गया। अब जिसके पास पैसा है वह दे सकता है। नहीं तो इधर-उधर से उधार करके देता है। लेकिन अगर हमारे यहां सुविधाएं हैं तो उसका लाभ उठाया जा सकता है। कभी हमारे पास टैक्निशियन नहीं होता है। डॉक्टर होता है तो टैक्निशियन नहीं होता। अगर हमारे पास टैक्निशियन हैं तो डॉक्टर नहीं होते या कभी इक्विपमैंट नहीं होते। कम-से-कम इन प्रीमियर हॉस्पिटल्ज़ में जैसे कि टांडा मेडिकल कॉलेज और आई0जी0एम0सी0 है में सारी सुविधाएं होंगी तो उससे हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभ होगा। बहुत सारी छोटी-छोटी बीमारियों के लिए पी0जी0आई0 चले जाते हैं। रैफर कर देते हैं। आजकल सारे हॉस्पिटल ज्यादातर रैफरल हॉस्पिटल बन रहे हैं। अगर छोटी बीमारी के लिए रैफर करना है, पी0जी0आई0 में जाते हैं तो वहां डॉक्टर कहते हैं कि क्या इतनी छोटी-सी बीमारी का इलाज आई0जी0एम0सी0 में नहीं होता है। इन चीज़ों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जो यह पैसा अनस्पैंट रहता है उसको पूरे साल भर में खर्च करेंगे तो उससे ये सुविधाएं यहां मिल सकेंगी।

बहुत सारी एम0बी0बी0एस की पोस्टें जब धूमल जी की सरकार थी तो इनकी संख्या 200 के करीब हो गई थी। टांडा की सीटें भी बढ़ गई थीं लेकिन अब नहीं बढ़ रही हैं। एम0सी0आई0 ने रोक लगा दी थी। बाद में सरकार के इंटरवैंशन से उस समय के

स्वास्थ्य मंत्री, डॉ0 हर्षवर्धन जी के इंटरवैंशन से आपको सीटें मिलती रही हैं। अब हर बार आपकी ये पोस्टें चलेंगी या नहीं चलेंगी, संशय रहता है। आपकी जो एम0बी0बी0एस0 के स्टूडैंटस की स्ट्रैंथ है यह चलेगी या नहीं चलेगी इसके लिए तलवार लटकती रहती है। एम0सी0आई0 जब आती है तो आप इधर-उधर से पैचवर्क करते हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन जब वह चली जाती है तो कुछ नहीं होता है। यही कारण है कि आप ई0एस0आई0 हॉस्पिटल लेना चाहते हैं जो सैंटर गवर्नमैंट के श्रम मंत्रालय ने नेरचौंक में बनाया है। अब श्रम मंत्रालय उसको

30.03.2015/1840/SS-AG/2

चलाना नहीं चाहता है। स्टेट गवर्नमैंट ने कहा है कि हम चलायेंगे लेकिन एम0सी0आई0 की आज की खबर आई है कि स्टेट गवर्नमैंट को यह न दिया जाए। क्योंकि आपके ऑलरेडी चल रहे मेडिकल कॉलेजिज़ में प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। आपके पास पूरी फैकल्टी नहीं होती है तो आप कैसे और मेडिकल कॉलेज चला सकते हैं? सैंट्रल गवर्नमैंट पैसा देगी। तीन मेडिकल कॉलेज आप हमीरपुर, सिरमौर और चम्बा में खोल रहे हैं उसके लिए सैंट्रल गवर्नमैंट ने एप्रूवल दी है। लेकिन वहां पर फैकल्टी आयेगी, बाकी चीज़ें मुहैया करेंगे, चलाना तो स्टेट गवर्नमैंट को पड़ेगा। स्टेट गवर्नमैंट के पास अभी एग्जिटिंग मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए साधन नहीं हैं तो उनको कैसे चलायेंगे? अब इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य की जो पूरी नीति है, मेडिकल एजुकेशन की जो नीति है इस पर सम्पूर्ण दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। आजकल आपके छोटे-छोटे हॉस्पिटल में जैसे कि अर्की में 9 की स्ट्रैंथ है। वहां पर आज दो डॉक्टर हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जिस विधान सभा क्षेत्र रोहड़ू को पांच बार रिप्रैंट करते रहे हैं उसमें 17-18 की स्ट्रैंथ होती थी आज वहां पर दो या तीन आदमी मिलते हैं। सब शिमला के लिए रैफर करते हैं। लेकिन रोहड़ू से शिमला पहुंचना सड़क के कारण मुश्किल है इसलिए रोहड़ू के व्यक्ति को शिमला पहुंचने में भी बहुत कठिनाई होती है। सीधा उनको विकास नगर होते हुए पी0जी0आई0 के लिए जाना पड़ता है। पी0जी0आई0 वाले बोलते हैं कि आपका आई0जी0एम0सी0 है वहां पर जाओ। इन सारी चीज़ों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपके पास हैं। आपके पास लैबोरेटरीज़ पूरे प्रदेश में थीं, आपके पास आई0जी0एम0सी0 में फुली इक्विप्ड लैबोरेटरी है, जिसकी पूरी मशीनरी आपके पास है लेकिन आपने उसको आउटसोर्स कर दिया है। आपने सारी एस0आर0एल0 कम्पनी को दे दीं। प्राइम जगह उनको आई0जी0एम0सी0 में दी गई है ताकि जो हमारी अपनी

आई0जी0एम0सी0 की लैबोरेटरी चलती है वहां पर कोई न जा सके और एस0आर0एल0 में ही जाए। अब उसके लिए कोई टैंडर होता, बाकी भी जो लैबोरेटरी वाले हैं, अगर आपने प्राइवेट में ही देना है तो उनको भी दिया जा सकता था। अब उनके सैम्पल लेते हैं और उसके कितने टैस्ट ठीक हैं या नहीं हैं इसकी आप जांच करवा सकते हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

30.03.2015/1845/केएस/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी---
उनके सैम्पल लेते हैं, उसके टैस्टे कितने ठीक है, कितने नहीं है, इसकी जांच आप करवा सकते हैं। प्राइवेट लेबोरेट्रीज़ को देने का बिल्कुल सैंटर में स्थान दे कर आपने प्राइवेटाईजेशन कर दिया और आपने जो आपका लैब है, उसको डीफंक्ट कर दिया है। पूरे 24 घण्टों में 21 घण्टे एस.आर.एल. चलेगा और तीन घण्टे आपकी लैबोरेटरी चलेगी। अब जो आपके आई.आर.डी.पी. के लोग हैं या बाकी गरीब लोग हैं जिनके मुफ्त में टैस्ट होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, एस.आर.एल. उन सबकी पेमैंट लेती है। अगर आपने उनको सुविधाएं दी है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से आपकी दुकानें हैं। सारे प्रदेश के बड़े-बड़े अस्पतालों में आपने सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की दुकानें खोल रखी है। हॉस्पिटल में सुविधाएं देने के लिए आर.के.एस. बहुत सारी चीजों पर चार्ज लगाती है और सिविल सप्लाई कॉपोरेशन को दुकानें अंदर इसलिए दी गई थी कि वे सस्ते दर पर लोगों को दवाइयां देंगें और उनको इंस्ट्रुमैंट्स देंगें लेकिन वहां पर जो इंस्ट्रूमैंट्स मिलते है, ऑर्थो के हों या कोई और हों और जो दवाइयां हैं, वह बाज़ार से ज्यादा रेट पर मिलते हैं और जो दुकानें उनको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने दे रखी हैं वे 100 या 200 रुपये के किराये पर है वे उस किराये को ही नहीं बढ़ाते। लाखों रुपया लेते हैं । दुकानें सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन अपने आप नहीं चलाती, उन्होंने कमीशन पर वे दुकानें दे रखी हैं और जिनको कमीशन मिलती है उनकी दिन में10 - 10लाख रुपये की सेल होती है लेकिन आई.जी.एम.सी. या टांडा मैडिकल कॉलेज को किराया देने के लिए वे

30.03.2015/1845/केएस/एजी/2

तैयार नहीं है। अगर आप लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहते हैं तो हमको इन चीजों पर विचार करना होगा, जो रिक्रूटमैंट्स हो रही है, जो फंक्शनल पोस्टें हैं, स्टाफ नर्सिज़ हैं या लैबोरेटरी टैक्निशियन है, परफ्यूज़निस्ट हैं, डॉक्टर्ज़ हैं, उनको भरने के लिए लिए आप सेंक्शन क्यों नहीं देते? केबिनैट में सेंक्शन करें और जहां भी करनी है फंक्शनल पोस्टों की रिक्रूटमैंट प्रॉपर करें । उनको न तो कॉंट्रैक्ट के द्वारा लगाया जा रहा है, न आर.के.एस. के द्वारा लगा रहे हैं अब आप उसकी आऊटसोर्सिंग कर रहे हैं। किसी कम्पनी को बोलेंगें कि भई ये नाम भेज दो और वह कम्पनी जो स्टाफ नर्स को तनख्वाह देते हैं उसमें अपनी कमीशन लेती है। कई जगह तो आधा-आधा पैसा ले लेते हैं और स्टाफ नर्स या लैबोरेटरी टैक्निशियन को आधा पैसा भी नहीं मिलता है। स्वास्थ्य नीति पर और जो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती की प्रक्रिया है ,इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। डॉक्टर्ज़ के तो आप हर मंगलवार को इंटरव्यू लेते हैं, उनको अप्वाइंट कर देते हैं, उनमें से अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाता है नहीं तो कोई उतने पैसे पर प्राइवेट में चला जाता है लेकिन बाकी जब स्टाफ नहीं होगा तो वह डॉक्टर क्या करेगा? इंजैक्शन डॉक्टर अपने आप नहीं लगाता है वह तो स्टाफ नर्स या कम्पाऊंडर ही लगाते हैं तो उनकी भर्ती अगर प्रॉपर नहीं होगी, आप आऊटसोर्सिंग से करेंगें तो उसके कारण आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं चर्मरा जाएंगी अब तो होम गार्ड भी सुरक्षा नहीं करेंगें, प्राईवेट एजैंसी को आऊटसोर्सिंग करके

30.03.2015/1845/केएस/एजी/3

यह काम आप देंगें। वह काम भी ठेके पर दे दिया आपने और जिन लोगों का सिक्योरिटी में कोई अनुभव नहीं है, उन्होंने ठेके ले लिए हैं । वे यहां-वहां से भर्ती करके हॉस्पिटल्ज़ में लगा देंगें तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन चीजों के ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा सामाजिक सरोकार है, और किसी भी सरकार को वह करने आवश्यक होते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में सुपर-स्पैशियलिटी तो लगभग समाप्त ही है। इसलिए उसके लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एम्ज़ आएगा केन्द्र सरकार ने उसको स्वीकृति दी है उसके लिए हम केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं लेकिन जब तक एम्ज़ बनेगा क्योंकि वह एम्ज़ भी इतनी जल्दी नहीं बनेगा, फैकल्टी तब आती है--

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--5

30.3.2015/1850/ag/av/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----------

फैकल्टी तब आती है जब उनको ऐजुकेशन और सड़क की सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप इसको बद्दी को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के किसी भी भाग में खोल दें क्योंकि बद्दी चंडीगढ़ के नजदीक है। जब तक आपको सारी सुविधाएं नहीं मिलती उस वक्त तक आपको अपने इनस्टिच्यूशन्ज से इनको स्ट्रैंथन करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि आई.जी.एम.सी. को पी.जी.आई. में परिवर्तित करके इसको फंक्शनल ऑटोनोमी देनी चाहिए। यहां पर जो डॉक्टर्ज आते हैं ,हम उनको और सुविधाएं दे सकें तो वह मेरे हिसाब से ज्यादा लाभकारी होगा। वैसे भी पैसा तो सारे-का-सारा आप ही दे रहे हैं। अभी सरकार ही सारी ग्रांट-इन-एड दे रही है। अगर यह मैडिकल युनिवर्सिटी फीजिबल नहीं है तो इसको कम-से-कम एक बड़े इनस्टिच्यूट में बदला जा सकता है। फैकेल्टी आए और यहां पर सुपरस्पैशेलिटी चलें तथा उसके कारण लोगों को लाभ हो। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों की ओर ध्यान देंगे तो हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा बेहतर हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

30.3.2015/1850/ag/av/2

श्री बिक्रम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या:9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बंधित है। विधान सभा में प्रश्नों के माध्यम से जब भी स्वास्थ्य के साथ जुड़ी बातों पर चर्चा हुई है तो उनसे सामने आई चिन्ता के कारण ही ये कटौती प्रस्ताव आया है। वर्तमान स्वास्थ्य नीति,स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती नीति ,उपकरणों की क्रय नीति कारण से यह कटौती प्रस्ताव आया है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, आज सुबह भी हमारा एक प्रश्न लगा था। उस प्रश्न के पीछे भी यही मन्शा थी कि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार से चल रही है। आप कहीं पर किसी इनस्टिच्यूट को अपग्रेड करते हैं तो उसमें आपने मापदण्ड केवल कुछ विधान सभा क्षेत्रों के लिए रखे हैं या ओवरऑल रखे हैं? मंत्री जी, आपने बड़ी चालाकी

से उसका जवाब दे दिया कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से कई बार ऐसा होता है। अच्छा होता अगर आप यह कहते कि कई बार राजनैतिक कारणों से ऐसा करना पड़ता है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक भी करना चाहूंगा। मैंने सुबह आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी के दो इनस्टिच्यूट बोल दिए। बाथड़ी चम्बा में आता है। बाथड़ी उनके विधान सभा क्षेत्र में नहीं आता है। मैंने शायद सुबह उनके विधान सभा क्षेत्र के बारे में बोल दिया तो बाथड़ी चम्बा में है। आज बिना नॉर्म्ज के संस्थानों को खोला जा रहा है। उनकी अपग्रेडेशन हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि पोस्ट क्रिएट करने से संस्थान नहीं चलते। संस्थान तो पोस्टों को भरकर चलते हैं। हम संस्थान को अपग्रेड कर रहे हैं मगर वहां पर डॉक्टर्ज नहीं हैं। जिस प्रकार से सुबह आदरणीय धीमान जी ने कहा कि आपने किसी इनस्टिच्यूट को अपग्रेड करने से पहले ही वहां कुछ पोस्टें भर दी जबकि नॉर्म्ज के मुताबिक तो उसकी 15-15, 17-17 पोस्टें बनती हैं। मगर आपने जो सुबह जवाब दिया वह भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या दिया। यहां पर रिक्रूटमैंट के विषय पर चर्चा होती है कि स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की भर्ती ठेकेदारी पर हो रही है। कई बार आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय भी कहते हैं कि आप केवल विरोध करते हैं। हम विरोध के कारण

30.3.2015/1850/ag/av/3

विरोध नहीं करते हैं। नर्सों की भर्ती ठेकेदारी प्रथा से करना ठीक नहीं है। हमारे पास अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड है, हम उसके माध्यम से ऐसा काम क्यों नहीं करते? नर्सों की भर्ती करने के बाद यही सूचना मिलती है कि जो हम ठेकेदार के थ्रू भर्ती करते हैं और ठेकेदार के थ्रू वहां जो कर्मी लगते हैं; उनको जो वहां पर पैसा मिलना चाहिए वह पैसा नहीं मिलता है-------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

30.03.2015/1855/negi/ag/1

श्री बिक्रम सिंह ..जारी...

जो उनको वहां पर पैसा मिलना चाहिए था वह पैसा नही मिलता है और ठेकेदार पैसा खा जाता है। शायद आपने इनके बारे में इनक्वायरी किया होगा और पता भी लगा होगा। स्वास्थ्य संस्थाओं के अन्दर भर्ती हो रही है । यह कोई बाली जी का डिपार्टमैन्ट

तो है नहीं कि आपने कंडक्टर भर्ती करने हैं और जैसे मर्ज़ी कर लिये। आप स्वास्थ्य संस्थाओं के अन्दर भर्तियां कर रहे हैं । मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कंडक्टर और स्टॉफ नर्स में फर्क है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य ऐसा आप किसी का नाम ले करके आक्षेप नहीं लगा सकते । आपने बाली जी का नाम लिया है। You cannot say like this.

श्री बिक्रम सिंहः सर, बाली जी का विभाग है,लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नही है, मैं तो सिर्फ कम्पेरिजन कर रहा हूं कि स्टाफ नर्स की भर्ती में और कंडक्टर के भर्ती में ज़मीन आसमान का फर्क है। हेल्थ इंस्टीट्युशन्ज़ में जो डॉक्टर लगेगा, हेल्थ इंस्टीट्युशन में जो नर्स लगेगी उसके हाथ में लाखों लोगों की जिन्दगी है। उसने उस क्षेत्र के लोगों की बीमारी का इलाज़ करना है। तो अच्छे लोग आगे आएं, अच्छी नर्सिज़ आगे आएं और अच्छे डॉक्टर वहां पर आएं । हमारे पास इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, हम टैस्ट लेते हैं, इन्टरव्यु लेते हैं और उसको रखते हैं। इसलिए मेरा आपसे केवल सुझाव है आप बेशक जो करना चाहें करें। लेकिन आप खास करके स्वास्थ्य विभाग के अन्दर भर्तियां चाहे नर्सों की हो रही है, डॉक्टर्ज़ की हो रही हैं, वे ठीक हों। हम आर.के.एस. के थ्रू भी डॉक्टर्ज भर्ती करते हैं । लेकिन आर.के.एस. के थ्रू जो कर्मचारी लगे हैं वे आज तक पक्के नहीं हुए हैं। जब भी बात होती है तो आशा वर्कर्ज़ की भर्ती के बारे में सभी बोलते हैं, आपकी तरफ से पता नहीं बोलते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन सभी बोलते हैं कि उसमें बहुत धांदली हुई है। हम यह सुझाव देंगे कि अगर 1000 रूपये महीना उनको मानदेय मिलता है तो इससे उनका घर भी चलेगा। यहां पर जब भी आपका वक्तव्य होता है या प्रश्न का उत्तर होता है तो आप उसमें कहते हैं कि हमने डॉक्टर्ज़ को जेनेरिक दवाइयां लिखने के

30.03.2015/1855/negi/ag/2

बारे में बोला है। लेकिन डॉक्टर्ज़ दवाइयां महंगी लिख रहे हैं। हॉस्पिटल्ज के अन्दर जो सरकारी दुकानें हैं वहां पर दवाइयां और सर्जिकल का जो सामान है वो बाकी दुकानों के मुकाबले महंगा मिल रहा है। डॉक्टर्ज़ को बार-बार इंस्ट्रक्शन्ज़ दी जाती है कि प्रदेश से जो गरीब लोग आते हैं उनको दवाई सस्ती लिखी जाए। सरकारी हॉस्पिटल्ज़ के अन्दर 90 प्रतिशत दवाइयां बाहर से लिखी जाती है। अभी किसी ने कम्प्लेंट भी की थी

कि एक डॉक्टर ने तो अपनी कॉपी लगाई हुई है, वह कहता है कि आप फ्लानी दुकान से दवाइयां लो। फिर जो दुकान का मालिक है वह सर्टिफाइड करता है उसके बाद आगे बात चलती है। पिछली बार भी हमने इस विषय को उठाया था। आप अपने तरीके से इसको मॉनिटर करें। आप हास्पिटल्ज़ के अन्दर देखें कि जिन डॉक्टर्ज़ की इस प्रकार की शिकायत है उनके ऊपर आपको कोई न कोई ऐक्शन लेने चाहिए। आपने लैब बन्द कर दी। मेरे से पहले आदरणीय भारद्वाज जी ने यह विषय रखा कि सरकार ने सारी लैब प्राइवेट कर दी हैं। उनकी गुणवत्त किस प्रकार से देखी जाएगी ,इसमें भी एक प्रश्न-चिन्ह लग रहा है। मैडिकल कालेज टांडा और मैडिकल कॉलेज शिमला में धूमल साहब के समय में तो वहां पर एम.बी.बी.एस. की 115 से 200 सीटें हुई हैं और एम.डी./एम.एस. की 39 से 149 सीटें हुई हैं। जबकि आपके समय में कोई सीट नही बढ़ी । यह भी कहा जाता है कि पूरे सिस्टम के अन्दर...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप एक मिनट बैठ जाइये। टाईम हो गया है। ....(व्यवधान)... I will give you time. _____(व्यवधान) ___ माननीय सदस्य आपको मैं 5 मिनट और देता हूं। क्या आप 5 मिनट में कर वाइंड-अप लेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कट-मोशन्ज़ में एक्सटेंशन नही होती है। There is no provision for extension of time in the rules.

30.03.2015/1855/negi/ag/3

अध्यक्षः माननीय सदन की बैठक आधे घंटे के लिए बढ़ा दें?

Health & Family Welfare Minister: Speaker Sir, when we discuss the Demands and Cut Motions, no extension of time is given. There is rule prescribed for it.

श्री रिखी राम कौंडल : जो सदस्य हमारे बोल रहे हैं वह भी कल बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय.. श्रीमती यू.के. द्वारा जारी...

30/03/2015/1900/यूके/एजी/1

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप इसका जवाब देंगे ? इस आईटम को खत्म कर लें ? कल के लिए स्थगित करें या इस आईटम को खत्म कर लें ?

Smt. Asha Kumari: You have to adjourn the House. The rules say that you have to adjourn the House. He can continue tomorrow. You can give him five minutes tomorrow but you cannot extent the House today because on Cut Motions no extension is given for the House.

Speaker: Thank you very much for reminding me the rules. Member will continue tomorrow.

अब इस माननीय सदन की बैठक, मंगलवार, 31 मार्च, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है ।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा**
दिनांक 30 मार्च, 2015 **सचिव**